हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

4 मार्च, 1994

खण्ड 1 अंक 5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 4 मार्च, 1994

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5) 21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 24
ध्यानाकर्षण सूचनाएं	(5) 25
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव--	
पलवल में नील गाय द्वारा खड़ी फसलों को नुक्सान पहुंचाने सम्बन्धी वक्तव्य--	(5) 28
जंगलात मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(5) 28
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5) 31
वैयक्तिक स्पष्टीकरण--	
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा	(5) 76

मूल्य :

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5) 77
बैठक का समय बढ़ाना	(5) 79
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5) 79
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान	(5) 88
वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान	(5) 89
बैठक का समय बढ़ाना	(5) 91
वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 92
बैठक का समय बढ़ाना	(5) 95
वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 95
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
लोक निर्माण मन्त्री द्वारा	(5) 96
वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 96
बैठक का समय बढ़ाना	(5) 98
वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 98

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 4 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the Question Hour.

Panipat Thermal Plant

***706. Shri Satbir Singh Kadian :** Will the Minister for Power be pleased to state whether it is a fact that the pollution is caused by flying ash and coal released from the Panipat Thermal Plant into the atmosphere and affect the adjoining villages of the area ; if so, the steps taken or proposed to be taken to check the said pollution ?

Power Minister (Shri. A.C. Chaudhary) : Yes, Sir. The Electro-static precipitators are being modified to arrest the pollution caused by fly ash. In addition, coal dust supression and extraction systems are being made effective.

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, पानीपत थर्मल प्लांट से असन्ध खुखराना, जाटल, सुताना आदि गांवों में बहुत प्रदूषण फैला हुआ है। एक तो नहर की वजह से वाटर लॉगिंग हो गयी और दूसरे प्लांट का स्प्रे काम नहीं करता। प्लांट की चिमनी से राख आती है। इसके अलावा, कोयला पिसने के कारण भी राख आस पास के खेतों में आती है जिसकी वजह से वहां के लोगों और पशुओं की सेहत खराब हो गयी है। उन लोगों को इसका कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन्होंने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं तथा यह काम कब तक पूरा हो जाएगा और अगर इन्होंने इसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है तो वह कब से की है?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां-जहां थर्मल पावर हाऊसिज़ लगे हैं, वहां पर कोयले को मैदे से भी ज्यादा महीन बनाकर बिजली जनरेशन के लिए झोंका जाता है। इसलिए यह तो स्वाभाविक ही है कि चिमनी से राख बाहर आती है लेकिन जिस वक्त यह प्लांट लगाये गए थे, उस वक्त यह

[श्री ए० सी० चौधरी]

सिस्टम बनाया गया था । राख को बाहर भेजने के लिए जो इम्पलीमन्ट्स हैं, वह इफैक्टिव नहीं हैं लेकिन इनमें सुधार करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं । लेकिन मैं अपने आदरणीय भाई को बताना चाहूंगा कि ई० एस० पी० को सुधारने के लिए तीस करोड़ रुपये से ज्यादा लगेंगे । सर, आज पानी की कमी के कारण जो बिजली की स्थिति बनी है, उसके कारण हम तीस करोड़ रुपये ओवर नाईट ऐलोकेट नहीं कर पाएंगे । मैं अपने आदरणीय साथी को विश्वास दिलाता हूं कि हम ई० एस० पी० की इंसटालेशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसमें फिर भी दो या ढाई साल तो लग ही जायेंगे । मैं हाऊस को एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि जैसे सभी भाई बिजली के लिए चिंतित हैं, थर्मल प्लांट्स भी बिजली बनाने के लिए लगाये गये हैं, लेकिन इसी बात को लेकर वहां के लोगों ने इस थर्मल प्लांट को बंद करने के लिए कोर्ट में नोटिस दिए हैं । भगवान न करें कल को कोई हम पर इसके कारण दाग न लग जाये कि इन्होंने यह थर्मल प्लांट बन्द करा दिया । मैं इनसे इसलिए यही कहूंगा क्योंकि खुद खुखराना गांव के लोगों ने पंचायत की तरफ से लोगों को मोटीवेट करके मुकदमें चलाये हैं । मैं तो इनसे यही कहूंगा कि बिजली बहुत जरूरी है इसलिए ये मुकदमें कोर्ट में न चलायें । हम इनकी राख की जो समस्या है और जो इम्पलीमैंट्स हैं, उनको सुधारने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे । जहां तक कोयले की राख का ताल्लुक है, उसमें तो पानी नहीं डाला जा सकता क्योंकि चिमनी से राख बाहर आती है, लेकिन बाकी सिस्टम में सुधार करने के लिए मैंने वहां के अधिकारियों से कह दिया है कि मैं इसको खुद फौरन आकर देखूंगा कि मौके पर इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है । अगर ये मेरे भाई चाहें तो मैं इनको भी अपने साथ ले जाकर वहां दिखा सकता हूं ताकि यह भी समझ लें कि सरकार की नीयत में कोई कमी नहीं है । हम वहां के लोगों के कष्ट जल्दी ही दूर करेंगे, यही मेरा इनसे कहना है ।

श्री सतबीर सिंह काद्यान : स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि कोर्ट में केस करवाये गये हैं । हमें नहीं पता कि ये केस किसने करवाये हैं । लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर लोगों की जान मुश्किल में है क्योंकि नीचे तो पानी है और ऊपर से राख है । उन लोगों को बिजली भी नहीं मिलती है । क्या सरकार का उन गांवों के लोगों को नौकरी देने का कोई प्रावधान है ? इसके अलावा, जिन लोगों की वहां पर जमीन ऐक्वायर की गयी है, क्या उनको भी सरकार नौकरी देगी ? वैसे पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी कुछ लोगों को नौकरियां दी थीं, परन्तु स्पीकर साहब, एक आदमी जिसका नाम सतबीर सिंह मलिक है जो भूतपूर्व मंत्री है, उसके खिलाफ महासिंह नाम के एक व्यक्ति ने ऐफिडैविट दिया है कि यह आदमी लोगों से नौकरी दिलवाने के लिए बीस-बीस हजार रुपया लेता है । इस ऐफिडेविट में उसने मुख्यमंत्री का भी नाम दर्शाया है । इसमें लिखा है कि मलिक ने मुझसे कहा.....(विघ्न)

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, नौकरी का इस प्रश्न से क्या ताल्लुक है ?

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, जिनकी जमीनें गयी हैं ..... (शोर एवं व्यवधान) यह ऐफीडैविट मेरे पास है, मैं आपको इसकी एक कॉपी भिजवा देता हूं । आपको इस पर कार्यवाही करनी चाहिए । आपको इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, एक ऐफिडैविट आया, उसकी बाकायदा हमने जांच भी करवाई । वे एक्स एम० एल० ए०, मंत्री व एम० पी० भी रहे हैं । दो बार इस बारे जांच करवाई गई और दोनों बार यह पाया गया कि यह बात बेबुनियाद है, यह सब पॉलिटिकल मामला है और उसको सियासी तौर पर डैमेज करने के लिए गलत शिकायत की गई है । हमने इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाई और पाया कि वह बिल्कुल निर्दोष है । वैसे भी एक मैम्बर जो हाउस में न हो, उस पर इस तरह के इल्जाम लगाना भी मुनासिब नहीं है ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, यह महासिंह पुत्र श्री चूड़ा राम के बारे में है । इस बारे में मैं स्पीकर साहब की भी इन्टरवेंशन चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि इसकी जांच किसी और एजेन्सी से कराई जाए जिससे तथ्यों का सही पता लग सके ? (विघ्न)

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर सर, जो भी मुझे कॉपी दी है, उसके मुताबिक 1991 के चुनाव के बाद ऐसा हुआ है, यह एलेज किया है, उस वक्त जिसका नाम लिया गया है, वो न एम० एल० ए० था, न मंत्री था, सरकार से उसका कोई सरोकार नहीं था । जातीय जिंदगी में अगर उसने कोई लेनदेन किया है तो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि इंक्वायरी हुई है और उसमें कहीं थर्मल का जिक्र नहीं है । इसके अलावा, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा । (विघ्न) मैं अपने फाजिल दोस्त से यह कहूंगा कि वे थर्मल के बारे में ही जिक्र करें ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो लोग राख, पानी और बिजली से परेशान हैं, उनको नौकरी देने के बारे में बार्ज भी बने हुए हैं और बिजली बोर्ड में जगह भी है, उनको नौकरी कब तक दे देंगे ?

श्री ए० सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड के मुताबिक जिन लोगों की जमीन पॉवर हाउस के लिए एक्वायर की गई है, उन सबको नौकरी दे दी गई है । यदि किसी व्यक्ति विशेष का कोई केस रह गया है तो मैं माननीय सदस्य को दावत दूंगा कि वे ऐसा केस मेरे नोटिस में लाएं, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाएगा ।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक से पांच यूनिट तक इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर और मैकेनिकल प्रेसपिटेटर इन दोनों के बारे यह ब्यौरा दें कि कौन सा रनिंग पोजीशन में है और कौन सा बंद है ? मंत्री जी ने यह भी बताया है कि चिमनी की ऐश पर पानी नहीं डाल सकते । जबकि इलैक्ट्रोस्टेटिक और मैकेनिकल प्रेसिपिटेटर लग जाने के बाद ऐश अंदर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ई0 एस0 पी0 और एम0 पी0 एक से पांच यूनिट तक कितने समय में रनिंग पोजीशन में आ जाएंगे ?

श्री ए0 सी0 चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ई0 एस0 पी0 और एम0 पी0 काम तो कर रहे हैं, मगर प्लांट एक और दो पर ई0 एस0 पी0 और एम0 पी0 उतने इफैक्टिव नहीं हैं जिसके कारण ऐश आ रही है । यह दोनों प्लांट हमने आइडैन्टीफाई कर लिए हैं, इसके लिए मिनिमम 30 करोड़ रुपया चाहिए । थोड़ा बहुत पैसे का जो व्यवधान है, उसके कारण काम लेट हो रहा है । इस काम को हम टाप प्रायोरिटी दे रहे हैं । इसके साथ ही मैं अपने आदरणीय दोस्त को बताना चाहूंगा कि मैं भी फरीदाबाद से हूं और वहां भी थर्मल पॉवर हाउस की यही प्रोब्लम है लेकिन मैं दोनों को ऐट पार डील कर रहा हूं और मैं भी उतना ही भोगी हूं जितने पानीपत के भाई हैं ।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दोनों प्लांट कब तक रनिंग पोजीशन में आ जाएंगे ?

श्री ए0 सी0 चौधरी : मैंने यह बताया है कि प्लांट काम कर रहे हैं लेकिन प्लांट नं0 1 और 2 पर इम्प्रूवमैंट की जरूरत है जिसके लिए 30 करोड़ रुपया एलोकेट करके हमने काम चालू कर दिया है और दो साल के अंदर कोशिश करेंगे कि काम पूरा कर दें ।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि कादियान साहब ने जो कुछ कहा है, वह काफी हद तक ठीक है । मैं भी उस गांव में गया था । उस गांव की ज्यादातर जमीन ऐसी है जो थर्मल में चली गयी है । उस समय जमीन की कीमत भी कम थी और जमीन भी कल्लर थी, इसलिये उनकी उसकी कीमत भी काफी कम दी गयी है । उनकी जमीन जाने से उनकी आमदनी का साधन तो चला ही गया, इसके साथ ही वहां पर थर्मल होने की वजह से जमीन के अन्दर से पानी निकलता है । इस वजह से वहां की जमीन भी नीचे धंस गयी है और वहां के लोगों के फेफड़ों में फलाई ऐश का धुआं जाता है जिससे उनकी सेहत भी खराब हो रही है । उनके मकान पूर्व में ऐसी जगहों पर बने हुए हैं जहां हवा का रुख भी उनकी तरफ का रहता है । आपने उनको यह आश्वासन भी दिया था कि हर घर को जिसकी जमीन थर्मल में गयी है एक नौकरी जरूर दी जायेगी । इस बारे में

बोर्ड का बाकायदा रज्योलूशन भी है कि ऐसे लोगों को नौकरी दी जायेगी जिनकी जमीन थर्मल में ली गयी है । कुछ को तो नौकरी दी गयी है लेकिन अभी भी कुछ परिवार रह गये हैं, क्या आप उनको भी नौकरी देंगे ? दूसरी बात यह है कि आप मौके पर जाकर देखो, बिजली बोर्ड द्वारा नहीं, चाहे इसके लिये कोई कमेटी बिठा दें जो जाकर देखे और अपनी तसल्ली करके उनकी समस्या का समाधान टाईम बाउन्ड पीरियड में करने की कोशिश करे ।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उनको नौकरी दी जाये, मुझे रिकार्ड से तो यह पता नहीं लगा कि कोई रह रहा है । फिर भी मैंने कादयान साहब को ओपन आफर दी है कि अगर कोई रह रहा है तो उसके लिये यह हमें बतायें । हालांकि यह बात सच है कि ओवरस्टाफिंग की वजह से मुख्य मंत्री महोदय ने फाईल पर यह आर्डर कर दिये हैं कि आगे से कोई भर्ती नहीं होगी लेकिन जमीन के मामले में हम इनको एकोमोडेट करने के लिये तैयार हैं । दूसरी बात का जहां तक ताल्लुक है, कल छुट्टी है, मैं कल ही खुद मौके पर जाऊंगा । मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिये मुझे टैक्नीकल एडवाईस की जरूरत नहीं पड़ेगी । कादयान साहब या पब्लिक का दूसरा कोई नुमायंदा, अगर मेरे साथ चलना चाहे तो वह भी जा सकता है । मैं इसके लिये कल को ही शुरूआत कर देता हूं ताकि इनको यह अहसास हो कि हम इस बारे में कुछ कर रहे हैं ।

Electricity Connections for Tubewells

***703. Shri Kitab Singh Malik :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) the division-wise number of applications of electricity connections for tubewells, if any, lying pending in the State during the period from 1st January, 1987 to 31st December, 1988 ; and

(b) the time by which the afore-said connections are likely to be released ?

Power Minister (Shri A. C. Chaudhary) :

(a) A statement is laid on the table of the house.

(b) Receipt of applications for new connections and release of connections is a continuous process. Maximum connections are released annually as per a pre-decided target depending upon the resources available.

[Shri A. C. Chaudhary]

STATEMENT

Division-wise No. of Pending Applications for Tubewell Connections as on 1-1-1987 and 31-12-1988

Name of Division	Pending Applications	
	As on 1-1-87	As on 31-12-88
1	2	3	4
1.	Ambala	518	499
2.	Ambala Cantt.	689	827
3.	Panchkula	653	816
4.	Yamuna Nagar	703	707
5.	Jagadhri	1224	1725
6.	Karnal	1096	1223
7.	Karnal S/U	4380	3071
8.	Panipat	1187	1256
9.	Panipat S/U	4106	3724
10.	Karnal S/U-II	—	3322
11.	Kurukshetra	—	1564
12.	Shahbad	1000	843
13.	Pehowa	2186	2492
14.	Kaithal	1958	2905
15.	Faridabad	9	—
16.	Ballabhgarh	388	337
17.	Palwal	308	531
18.	Faridabad old	—	107
19.	Sonepat	603	688
20.	Sonepat S/U	1744	2315
21.	Gohana	—	860
22.	Gurgaon	81	66
23.	Gurgaon S/U	524	879
24.	Sohna	830	1291
25.	Gurgaon (Op-cum-Construction)	784	1256
26.	Sirsa	582	886

27.	Sirsa S/U	1743	2573
28.	Dabwali	140	715
29.	Bhiwani	60	367
30.	Bhiwani S/U	343	1324
31.	Dadri	1050	1562
32.	Jind	745	1139
33.	Narwana	919	1446
34.	Safidon	935	1328
35.	Rohtak	32	72
36.	Rohtak S/U	135	220
37.	Jhajjar	772	1255
38.	Bahadurgarh	150	124
39.	Mohindergarh	1809	2317
40.	Rewari	2014	2213
41.	Dharuhera	573	1326
42.	Narnaul	1961	1635
43.	Hisar-I	22	41
44.	Hisar-II	226	470
45.	Tohana	1256	1230
46.	Fatehabad	1578	2089
47.	Hansi	364	837
		44584	58503

श्री किताब सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गोहाना मंडल में 1-1-1987 तक जो 349 एप्लीकेशन्ज बकाया पड़ी थीं, इस सरकार के बनने के बाद से उनमें से कितने कुनैक्शन्ज दिये गये ? कई जगहें ऐसी हैं, जैसे फरीदाबाद, करनाल सब-अर्बन, गुड़गांव और हिसार, इनमें जो एप्लीकेशन्ज बकाया पड़ी हैं, उनका नम्बर न के बराबर है जबकि दूसरी जगहों पर यह नम्बर बहुत ज्यादा बाकी रहता है । इसका क्या कारण है ?

श्री ए० सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फरीदाबाद और हिसार बगैरह की बात है, मैं अपने भाई को यह बताना चाहता हूं कि यह सारे अर्बन एरियाज हैं जहां पर कोई जमीन ऐसी नहीं है जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिये यूज की जाये । उस नाते से न तो वहां पर कोई ऐसी जमीन ही है और न ही किसी ने ट्यूबवैल कुनैक्शन मांगा है । जहां तक गोहाना की बात का ताल्लुक है, मैं अपने फाजिल दोस्त को

[श्री ए० सी० चौधरी]

कहना चाहता हूं कि 1-1-1987 को जो 349 एप्लीकेशन्ज पैंडिंग थीं, वह 31-12-88 को बढ़ कर 860 हो गयीं । गोहाना में 1-1-1987 को हमारे पास जो टैस्ट रिपोर्ट्स थीं, वह केवल 70 थीं । जितनी भी टैस्ट रिपोर्ट्स उस वक्त हमारे पास थीं, हमने यह कोशिश की है कि उन सब को कुनैक्शन दे दिया जाये । जैसे मैंने कहा है, इस सरकार द्वारा अपने सिल्वर जुबली ईयर में 40,000 कुनैक्शन दिये गये हैं । यह तो एक रिकार्ड की बात है । 31-12-1988 को जो 860 ऐप्लीकेशन्ज पैंडिंग थीं, अब उनमें से केवल 133 रह गयी हैं । बाकी की एप्लीकेशन्ज क्लीयर कर दी गयी हैं । मैं समझता हूं कि सरकार ने सारी स्टेट में जितने कुनैक्शन्ज दिये हैं, उसके हिसाब से गोहाना में प्रोपर्शनेटली काफी कुनैक्शन दिये गये हैं ।

श्री किताब सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी पूछा था कि यह सरकार आने के बाद जो पैंडिंग ऐप्लीकेशन्ज हैं, उनमें गोहाना मण्डल को कितने कुनक्शन्ज दिये गये हैं ?

श्री ए० सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि यह एक कंटीन्युअस प्रोसैस है । डिवीजन वाईज कितनी ऐप्लीकेशन्ज आई, इसका मैंने पहले ही बता दिया है । टैस्ट रिपोर्ट की डिटेल मैंने बता दी है । इंडीविजुअलज का बताना तो जरा मुश्किल है, फिर भी मैं बता देता हूं कि 1-1-87 को 70 टैस्ट रिपोर्ट्स और 31-12-87 को 133 टैस्ट रिपोर्ट्स पैंडिंग थीं ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि लोगों को मुतवातर बिजली न मिलने के कारण सरकार चिन्तित है । रोहतक जिला में भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड की तरफ से बिजली दी जा रही है, जिसका कंट्रोल पंजाब सरकार के हाथ में है । इसका नतीजा यह हुआ कि इररैगुलर कट हो रही है । तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार रोहतक जिला व इसके एडजायनिंग एरियाज में बिजली की मुतवातर सप्लाई के लिये क्या कदम उठा रही है ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत न हो ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि सरकार ने 1993 के बजट सैशन में यह आश्वासन दिया था कि रोहतक जिले व मेरे हल्के बेरी व कलानौर में बड़े ट्रांसफार्मर लगाकर के लज्जर से बिजली की सप्लाई दी जाएगी । जरा इस बारे पोजीशन क्लीयर कर दें ।

श्री ए० सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न से यह सप्लीमैंट्री अरीज नहीं होती, फिर भी मैं बता देता हूं कि बिजली के इस मसले को समझना और उसको हल करना इस सरकार का कर्तव्य है जिसके लिये सरकार पूरी तरह से सजग है । इसमें कोई शक नहीं कि भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है । अगर पीछे से ही स्विच आफ हो जाए या ट्रिपिंग कर दें तो वह समस्या तो सारी स्टेट की हो जाती है । चूंकि हमारा कंट्रोल भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड पर

नहीं है लेकिन फिर भी हमने स्टेट के इंट्रेस्ट को देखकर काफी पग उठाये हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जब कभी फिक्वैन्सी लो होती है तो आटोमैटिकली लोड सैट करना पड़ता है। अगर पीछे से स्विच आफ हो जाए या ट्रिपिंग कर दें जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो यह समस्या सारी स्टेट की हो जाती है। जहां तक रोहतक जिले की बिजली सप्लाई का सवाल है, इसके लिये हमने चार प्रिआरिटीज का काम सिलैक्ट किया है और जिससे सारी स्टेट के अन्दर बिजली की स्टीमिंग होगी और साऊथ हरियाणा के लिये बादशाहपुर से रिवाड़ी का काम किया है। इसी तरह से पानीपत से रोहतक तक की एक स्कीम बना चुके हैं और उसे हम जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यह मसला पूरी तरह से हल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी अर्ज करूंगा कि ट्रिपिंग के मामले में हम बहुत हद तक असहाय हो जाते हैं। जब फ्रिक्वैन्सी फाल करती है तो लो-शैड कर देते हैं और फिर यह मामला हमारे हाथ से निकल जाता है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस सरकार का मैनीफैस्टो था कि हम लोगों को पीने का पानी सप्लाई करेंगे। आदरणीय मुख्यमन्त्री महोदय ने अपनी सरकार आने के बाद इस काम को पूरी प्राथमिकता दी है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल दिया जाए लेकिन पब्लिक हैल्थ विभाग की तरफ से सैकड़ों ऐसे ट्यूबवैल्ज हैं जिनमें सरकार ने करोड़ों रुपया लगा दिया है। केवल मात्र पानी न मिलने से लोगों को भारी दिक्कत आ रही है। क्या मन्त्री महोदय इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे ताकि एक महीने के अन्दर अन्दर सारे प्रदेश के अन्दर सभी जगहों पर ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज दे दिये जाएं और ट्यूबवैल्ज चालू हो जाएं जिससे लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो जाए ?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, जिस दिन मैंने इस डिपार्टमैंट का चार्ज लिया था, सबसे पहले मैंने यही काम किया था। मैं और पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर, दोनों बैठे और अपने अफसरों को बुला कर इस बारे में बातचीत की। हमारी सरकार की पालिसी बहुत क्लीयर है। हमारी एग्रीकल्चर के बाद दूसरी प्रिआरिटी ड्रिंकिंग वाटर देने की है। उस नाते से जितने ट्यूबवैल्ज इन-हैंड थे, हमने ईंडिविजुयल केस को आपस में डिस्कस किया और पूरे तरीके से एक स्कीम बनाई जिसके आधार पर आज हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा ट्यूबवैल अब भी कोई रहता है जिसको कनैक्शन न मिला हो। इसके बावजूद भी कल हमने खुला फैसला किया है कि आप जितने कनैक्शंज के लिए कह देंगे, उसके पेपर पूरे कर दें, हम दो महीने के अन्दर अन्दर उनको कनैक्शन दे देंगे।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, जैसे अभी दो विभागों का जिक्र आया, यह वास्तव में ही एक समस्या है। यह समस्या अकेले ट्यूबवैल्ज की ही नहीं बल्कि वाटर वर्कस के लिए भी आती है। वाटर वर्कस पर जो ट्रांसफारमर लगे हुए होते

[प्रो0 सम्पत सिंह]

हैं, वे छोटे हैं, जबकि वाटर वर्कस ज्यादा लोड लेता है । उसके लिए या तो दूसरा ट्रांसफारमर चाहिए या फिर बड़ा ट्रांसफारमर चाहिए । ऐसी हालत में पब्लिक हैल्थ वाले बिजली बोर्ड को लिखते हैं और बिजली बोर्ड उनसे खर्चा मांगता है । फिर पब्लिक हैल्थ वाले दोबारा लिखते हैं कि यह खर्चा हम से नहीं लेना है बल्कि बोर्ड ने खुद वहन करना है । तो इन मैटर्ज पर दोनों विभागों का तालमेल नहीं है । क्या सरकार इस पालिसी को क्लीयर करेगी क्योंकि इस वजह से वाटर वर्कस ने पानी देना बन्द कर रखा है । इनका लोड फालतू होता है और ट्रांसफारमर बिजली बोर्ड दे नहीं रहा है ।

श्री ए0 सी0 चौधरी : स्पीकर साहब, जहां पर केस जस्टीफाइड होता है, वहां तो हम ट्रांसफारमर अपनी कास्ट पर दे देते हैं । जहां पब्लिक हैल्थ ने कास्ट बीयर करनी होती है, वहां उनको करनी पड़ेगी । हमारी आपस में कोई एम्बीग्यूटी नहीं है। फिर भी मैं आज फिर हिदायत कर दूंगा कि जहां कोई ऐसी चीज हो तो लैटर लिखने के बाद आप कर दें । हम उनको अपने ट्रांसफारमर्ज और दे देंगे । पैसा हम अपने तौर पर एडजस्ट कर लेंगे । पहले तो मीटर भी लेने पड़ते थे लेकिन अब यह भी फैसला कर दिया है कि कुछ भी चीज लेने की जरूरत नहीं है । हम सस्ते रेट पर लेते हैं इसलिए हम खुद लगा कर उनको पूरा करेंगे ताकि कोई दिक्कत न हो। हमने सारा मामला दो मीटिंग्ज में सार्ट आउट कर लिया है इसलिए अब कोआर्डिनेटिड एफर्टस में कोई कमी नहीं है ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिजली मन्त्री जी ने अभी जो फर्माया, यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । इसी सदन में प्रश्न नं0 724 के उत्तर में इन्होंने फर्माया था कि 31-12-93 तक 69463 एप्लीकेशंज ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन के लिए पैंडिंग हैं । क्या बिजली मन्त्री जी किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए कृषि को प्राथमिकता के आधार पर कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएंगे कि किसान को 6 महीने में या एक साल में कनैक्शन दे दिया जाएगा ? जैसे पहले एक्स सर्विस मैन के लिए या दस हजार रुपए भरने वाले को प्राथमिकता दी जाती थी या हैंडीकैप्ड को प्राथमिकता दी जाती थी, इसी तरह किसान को भी कनैक्शन देने के लिए प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे ?

श्री ए0 सी0 चौधरी : स्पीकर साहब, मेरे भाई शायद मेरी बात को मान भी गए थे । मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप इस स्टेटमैंट को देखेंगे तो 1987 में 43584 एप्लीकेशंज कनैक्शन के लिए पैंडिंग थीं और 1988 में 58530 पैंडिंग थीं । इनके बीच के जितने कनैक्शन दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी 14 हजार के लगभग एप्लीकेशंज फालतू हो गई । मैं समझता हूं कि 1988 में इतनी बढ़ी हैं तो 1988 के बाद अगले 5 या 6 साल में इतनी ही और बढ़ी होंगी ।

इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि सरकार ने वाकई में प्रक्टीकल फील्ड वर्क किया है । जहां तक सर्वे करने या पालिसी रिवाइज करने का ताल्लुक है, मैं इस बारे में एक ही बिनती करूंगा और मेरे भाई सम्पत सिंह जी मेरे प्रैडीसैसर रहे हैं, ये जानते हैं, इस वक्त लाईनें बहुत ज्यादा ओवर लोडिड हैं । जब तक इस सिस्टम को रैनोवेट या आगमैंट नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी वायदा सिरे नहीं चढ़ेगा। मैं आपको बिजली बोर्ड की प्रफारमैंस के बारे में बताऊंगा जो अब शुरु कर दी गई है । एक तो लाईनों को स्ट्रैंथन कर दिया जाए और दूसरे बिजली की चोरी को रोका जाए ताकि बिजली के हकदार तक बिजली पहुंच जाए, वह रास्ते में कहीं पर लीक न हो । मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करता हूं कि फसल की कटाई के बाद आगे किसानों को पैडी के लिए पानी चाहिए, उसके बीच के वक्त के एक एक मिनट को इस्तेमाल करके हम बैस्ट पौसिबल सर्विस देने की कोशिश करेंगे । कम से कम आपको तसल्ली जरूर हो जाएगी ।

श्री अजमत खां : स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया था कि पहले 1988 में लगभग 58 हजार एप्लीकेशंज और अधिक पैंडिंग थीं और अब लगभग 69 हजार एप्लीकेशंज पैंडिंग हैं, यानि लगभग 11 हजार एप्लीकेशंज पैंडिंग हैं । इसके अलावा, इन्होंने बताया कि लगभग 40 हजार ट्यूबवैल्ज को बिजली के कनैक्शन इन्होंने दे दिए । स्पीकर साहब, इनके पास जितनी एप्लीकेशन पैंडिंग हैं, उनको देखते हुए, अगर आज कोई किसान ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिए एप्लाई करे तो उसको आगे आने वाले पांच साल तक कनैक्शन नहीं मिलेगा । यह मसला किस तरह से निपटाएंगे, क्या किसान पांच साल तक इंतजार करते रहेंगे ? इसके अलावा, मंत्री जी ने यह कहा कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के ट्यूबवैल्ज को दो महीने में बिजली के कनैक्शन दे देंगे । स्पीकर साहब, प्यास आज लग रही है और पानी दो महीने बाद आएगा। बिजली के कनैक्शन न मिलने के कारण मेरे अपने हल्के के टौंका, गुरामसर, ढकलपुर मनकाना, कोट, जलालपुर, हथीन और शणीयाला खुर्द गांवों में लगभग एक साल पहले से ट्यूबवैल तैयार हैं, लेकिन उनको आज तक बिजली का कनैक्शन नहीं दिया गया है । बिजली बोर्ड के पास कंडक्टर्ज नहीं थे पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने बिजली बोर्ड वालों को कंडक्टर्ज खरीद कर छः मास पहले दिए लेकिन फिर भी आज तक उन ट्यूबवैल्ज को बिजली के कनैक्शन नहीं मिल सके हैं । राज्य मंत्री जी ने 10-2-94 को हथीन में आश्वासन दिया था कि हम 8 दिन में कनैक्शन लगवा देंगे । इन्होंने दो महीने में कनैक्शन देने की बात कही है, वह बहुत लम्बा टाईम है । आगे गर्मी का मौसम आ रहा है । क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जितना जल्दी हो सके, उन गांवों के ट्यूबवैल्ज को बिजली का कनैक्शन देंगे ? वहां पर कंडक्टर्ज पड़े हैं, पोल पड़े हैं, यदि उन गांवों के ट्यूबवैल्ज को बिजली का कनैक्शन नहीं दिया गया तो लोगों को बहुत परेशानी होगी ।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने कहा कि प्यास आज लगी है, बुझाएंगे दो महीने बाद । मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी को आज प्यास लगी और वह कुंआ आज ही मांग ले तो मेरे पास कोई जादू तो होगा नहीं कि मैं रातों रात वह काम कर दूं । जहां तक बिजली के कनैक्शंज देने का ताल्लुक है, मैं हाउस के अन्दर खुले तौर पर एलान करता हूं कि शायद आज तक इतने कंडक्टर्ज, इतने केबल की और ट्रांसफारमर्ज की एक्सपीडिसियस सर्विस कभी भी नहीं दी गई । आज कल खराब हुए ट्रांसफारमर को 72 घण्टे से पहले पहले बदल रहे हैं ताकि किसानों को दिक्कत न हो, जबकि रेट आफ डैमेजिज मैक्सीमम हो चुके हैं । आज सैशन के बाद मैं पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब से बात कर लूंगा । अगर वहां पर ट्यूबवैल्ज तैयार हैं और कंडक्टर्ज पड़े हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज शाम तक आपको प्रोमिस दे दूंगा कि कल से मेरे आदमी फील्ड में लगे होंगे, लेकिन यदि कोई टैक्नीकल फाल्ट या फलो है तो मैं कमिटमैंट नहीं कर पाऊंगा, वह फाईल देखने के बाद करूंगा ।

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मण्डलवार ब्यौरा दिया गया है उसमें कुरुक्षेत्र पहले 13 मण्डलों में आता है जिनमें सब से अधिक केस पैंडिंग हैं । कुरुक्षेत्र जिले में सबसे ज्यादा कनैक्शंज पैंडिंग हैं हालांकि वह चावल का क्षेत्र है, इसलिए यह चिन्ता-जनक स्थिति है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र मण्डल में सबसे ज्यादा पुराने कनैक्शंज के केसिज कितने साल से पैंडिंग हैं, एक साल में कितने कनैक्शंज के लिए प्रार्थना पत्र आए और उनमें से कितने कनैक्शन दिए जा चुके हैं ?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, हम इस बात की बखूबी जानकारी रखते हैं कि कुरुक्षेत्र जरडेज ईलाका है । कुरुक्षेत्र और करनाल के इलाके में सबसे ज्यादा पैडी होती है, इसलिए सबसे ज्यादा पानी की मांग उस एरिया में है, क्योंकि पैडी तो एक मच्छली है, पानी के अन्दर जिन्दा, नहीं तो गई । उस नाते से कुदरती बात है कि ज्यों-ज्यों प्रौसपैरिटी बढ़ रही है, लोग ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शन मांग रहे हैं यदि कनैक्शन मांगेंगे तो एप्लीकेशन आएगी । मैं भाई को इतना ही कह सकता हूं । मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1987 में लोगों की 1655 एप्लीकेशंज पैंडिंग थीं और 1988 में 1564 ।

डा० राम प्रकाश : आपके जवाब में कुरुक्षेत्र के बारे में जो आंकड़े दिए हैं, 10.00 बजे । उनके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि एक साल में कितने लोगों ने कनैक्शन के लिए एप्लाई किया और उसमें से कितने लोगों को कनैक्शंज मिले और कितने रह गए ? मैं जानना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में इतने अधिक कनैक्शंज क्यों पैंडिंग हैं ?

श्री ए० सी० चौधरी : कुरुक्षेत्र जिले में ज्यादा एप्लीकेशंज पैंडिंग नहीं हैं । आप देखिए, इस अवधि में हमने अम्बाला सिटी के लिए 554, अम्बाला कैंट में

701, जगाधरी में 977, यमुनानगर में 699, करनाल में 910 और कुरूक्षेत्र में 1412 कुनक्शंज दिए हैं । इन फिगर्ज को आप देखें तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कुरूक्षेत्र में ज्यादा पैंडिंग हैं ? रेशो के हिसाब से आप देखें तो कुरूक्षेत्र में ज्यादा एप्लीकेशंज आई हैं और ज्यादा ही कुनैक्शंज कुरूक्षेत्र जिले को दिए गए हैं । हम अपनी क्षमता के मुताबिक कुनैक्शन दे रहे हैं । इसके साथ ही साथ मैं हाउस की जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने अब डिवीजन और सब-डिवीजन लैवल पर बाकायदा सीनियरिटीवाइज लिस्ट लगा दी है कि किसका नम्बर किसके बाद आएगा ताकि बंगलिंग न हो ।

Desilting WJC and JSB Canals

*762. **Shri Zile Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the WJC and J.S.Br. Canal ;

(b) if so, the time by which the aforesaid canals are likely to be desilted ; and

(c) whether it is a fact that the pump houses of J.S.B. at Akheri and Ladain are not functioning ; if so, the reasons therefor and the time by which the said pump houses are likely to be re-started ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) :

(a) Yes.

(b) The work of desilting of WJC will be taken up during the year 1994-95 under the project of Operation and Maintenance and the work of desilting of J.S.B. will be taken up during the next financial year subject to availability of funds.

(c) Yes, it is a fact that the pump houses at Akheri and Ladain are not functioning. These pump houses feed Salhawas Lift Channel which has recently been transferred to J.L.N. Feeder temporarily. The Salhawas Lift Channel is being fed by gravity flow now from J.L.N. Feeder and as such there is no necessity to re-start these pump houses at present.

श्री जिले सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि डब्ल्यू0 जे0 सी0 नहर हमारे सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, महेन्द्रगढ़ और भिवानी जिले को सिंचाई के लिए पानी देती है। यानी यमुना में 2/3 पानी हरियाणा को इसी नहर से मिलता है । हमने पीछे पी0 ए0 सी0 कमेटी ने इस को ताजेवाला हैड वर्कस से लेकर आगरा कैनाल तक देखा था । इसमें बहुत सारी जगहों

[श्री जिले सिंह]

पर बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट भरी हुई है और कई जगह पर तो इस नहर में टापू जैसे दृश्य बने हुए हैं, इसलिए मेरी मांग है कि इस सिल्ट को जल्दी से जल्दी निकाला जाये। दूसरे, मंत्री महोदय ने जवाब यह दिया है कि जे0 एस0 बी0 नहर की सफाई धन उपलब्धि के आधार पर करायी जायेगी। मैं बताना चाहूंगा कि इस नहर में भी काफी सिल्ट भरी पड़ी है, अतः इसकी भी सफाई तुरंत कराये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि साल्हावास लिफट चैनल से जे0 एल0 एन0 नहर क्या पूरी चल रही है या आधी चल पा रही है ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, ऐसा है कि डब्ल्यू0 जे0 सी0 कैनाल ताजेवाला से निकलती है और इनकी बात दुरुस्त है कि इसकी कैपेसिटी 12000 क्यूसिक है। ताजेवाला से हरियाणा को पानी का 2/3 हिस्सा और यू0 पी0 को 1/3 हिस्सा जाता है। ओखला से हमारा हिस्सा 1/4 व यू0 पी0 का 3/4 है। इस नहर में सिल्ट ज्यादा हो गयी है, यह बात ठीक है और इस ज्यादा सिल्ट की वजह से इसकी कैपेसिटी में भी फर्क पड़ा है। स्पीकर साहब, अगले साल वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लिया जा रहा है, वह नहरों के रख-रखाव और डीसिलिटिंग पर खर्च किया जाएगा ताकि पानी की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। जे0 एस0 बी0, जे0 एल0 एन0 के साथ चल रही है, इसकी डीसिलिटिंग के लिए फण्ड्ज का प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पर पूरा पानी दिया जा सके। झज्जर सब-ब्रांच साल्हावास से निकलती है और इस ब्रांच से साल्हावास को पूरा पानी मिले, इसके लिए साल्हावास को जे0 एल0 एन0 में टैम्परेरिली शिफट किया गया है। (विघ्न)

श्री जिले सिंह : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि साल्हावास लिफट चैनल को पूरा पानी का हिस्सा दिया जा रहा है या नहीं ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह टैम्परेरी तौर पर शिफट की गई है। अलेड़ी लडान पावर हाउस काफी पुराना हो गया था और ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रहा था। जो पूरा पानी लिफट होना चाहिए यह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए उसको जे0 एल0 एन0 में टम्परेरिली कनैक्ट किया गया है। इसका कारण यह है कि जे0 एल0 एन0 में पानी तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमें एस0 वाई0 एल0 का पानी उपलब्ध न हो जाए। यह मामला एस0 वाई0 एल0 के साथ जुड़ा हुआ है, जब पूरा पानी मिलेगा तो फिर इसको परमानैंटली लडान अलेड़ी माईनर के साथ जोड़ेंगे। (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले बजट सैशन में और उससे पहले भी इन्होंने सदन

में यह आश्वासन दिया था कि फरीदाबाद की सभी नहरों की डी-सिल्टिंग करवा दी जाएगी । मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव के आधे से ज्यादा हिस्से की सिंचाई गुड़गांव कैनाल से होती है । मैं सदन में बताना चाहता हूं कि उसमें 10-10 फुट तक गन्द और गाद भरा हुआ है । पिछले सैशन में मन्त्री जी ने इसको साफ करवाने का आश्वासन भी दिया था । स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आश्वासन यहां हाउस में देते हैं, क्या उस पर कार्यवाही भी होती है या केवल आश्वासन ही देते हैं, क्या अपने आश्वासन को ये सीरियसली लेते हैं ? मैं बताना चाहूंगा कि इस नहर में केवल 3 फुट पानी चलता है । इस कैनाल की सफाई मेवात ऐरिया, गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों के लिए तो जीवन-मरण का प्रश्न है । स्पीकर साहब, मैं फिर मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस कैनाल की सफाई करवाने के लिए फिर से आश्वासन दे कर इसका काम करवाएंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, बिसला जी ने जो कहा है, वह पूरी तरह से दुरुस्त बात नहीं है । फरीदाबाद जिले की दो जगहों से इरिगेशन होती है, एक तो आगरा कैनाल से और दूसरे गुड़गांव लिफट कैनाल से । आगरा कैनाल का सारा कण्ट्रोल यू0पी0 गवर्नमैंट के पास है, जैसे दिल्ली बांध का कण्ट्रोल हरियाणा के पास है । सैकड़ों सालों से यह सिस्टम चल रहा है । पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो आगरा नहर से फीडिंग होती है, उसका कण्ट्रोल यू0पी0 के पास है और गुड़गांव नहर इरिगेशन सिस्टम का कण्ट्रोल हरियाणा के पास है । अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि गुड़गांव नहर और जे0 एल0 एन0, एस0 वाई0 एल0 से जुड़ी हुई हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, वह एस0 वाई0 एल0 से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई है । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव कनाल में से जहां तक गाद निकालने व उसकी टूट-फूट को ठीक करने का सवाल है, इसके लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है और अगले साल तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा ।

श्री जिले सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मंत्री जी के पास जो आफिसर्ज ने रिपोर्ट दी है, वह ठीक नहीं है । जे0 एस0 बी0 और एस0 एल0 सी0 दोनों जेहलम से फीड हो रही हैं । उसमें से एक छोटी सी माईनर काशी, लैडान के पास फीड हो रही है, यह 28 किलोमीटर लम्बी है जो सिल्ट से भरी पड़ी है । उसको कोई भी नहर नहीं कह सकता है । हां, यह कहा जा सकता है कि शायद यह कभी नहर थी । उसमें पानी का नामों-निशान ही नहीं है । दूसरे इस नहर से अखेड़ी और लैडान के दो पम्प हाऊसिज हैं, जैसे

[श्री जिले सिंह]

आप कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, यह ठीक नहीं । जब तक ये दोनों पम्प नहीं चलेंगे, तब तक जो इस इलाके में इस नहर से सिंचाई होती थी, वह नहीं हो सकती । ऐसे कई गांव हैं जैसे मालन हेल, मौनता है, जहां पर पानी नहीं है, इनके ऊपर आबयाना लगाया जाता है । इन पम्प हाउसिज पर कर्मचारी हैं । इन्जीनियर्ज हैं, सर्वेन्टस हैं, मशीनरीज हैं, इस बारे में मंत्री जी बता दें कि इन का भविष्य क्या होगा ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह जो झज्जर सब ब्रांच है जिसे मैं और श्री ओम प्रकाश बेरी जी खुद देख कर आए थे, इसमें काफी डी-सीलिंग हुई है और करीब करीब यह प्रोसैस काफी सालों से चल रहा है । अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने चार साल के राज्य में डक्का नहीं तोड़ा है । यह तो 8–10 साल की बात हो गई है । यह सारी डी-सिल्टिंग हो गई और डी-सीलिंग हो गई । ये बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं । जे0 एस0 वी0 की कैपेसिटी साढ़े पांच सौ क्यूसिक पानी की है, सालहावास की 330 क्यूसिक की है और जे0 एल0 एन0 की कैपेसिटी दो हजार क्यूसिक से ऊपर की है । इनकी हर साल सफाई की जाए तो ठीक है लेकिन इनकी डी-सिल्टिंग भी नहीं होती और न ही डी-सीलिंग होती है क्योंकि साथ की डब्ल्यू0 जे0 सी0 से सिल्ट आती है । लगातार डी-सीलिंग न होने की वजह से यह सारा सिस्टम खराब है । सर, जहां तक सालहावास का ताल्लुक है, वहां पम्प हाउस होना चाहिए जैसे अखेड़ी और लैडान में टैम्परेरी तौर पर है ।

श्री जिले सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम चल नहीं रहा है । ये सच नहीं कह रहे हैं ।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रैक्टीकली इनसे डिस्कस किया है । इनसे मेरी बात हुई थी और जो साइफन है, जो पानी ऐस्केप से आता है जैसे बिजली नहीं आई और ऐस्केप से पानी आया वह पानी लैडान से जाता है लेकिन एक्चुअली इसको जे0एल0 एन0 के साथ जोड़ना चाहिए था, वह नहीं जुड़ा । ये जो बात कह रहे हैं, वह ठीक है क्योंकि पहले मुझे यह ख्याल था जैसे कि वह जोड़ दी गई है लेकिन पानी ऐस्केप से जाता है और फिर लैडान में जाता है । लेकिन कई बार वह ऐस्केप से नहीं जाता है इसलिए उनको दिक्कत होती है । इस बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको परमानैन्टली जोड़ दिया जाए ताकि पानी की समस्या दूर हो सके ।

श्री ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि जे0 एस0 वी0 की डी-सीलिंग की जाएगी, subject to the availability of funds. स्पीकर साहब, मैं इनसे एक बात रिक्वैस्ट के तौर पर कहना चाहूंगा कि ये मंत्री जी

पूरी हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेन्ट करते हैं, केवल हिसार और सिरसा को रिप्रेजेन्ट नहीं करते। जब भी कोई काम हमारे जिलों के बारे में होना होता है तो यह सबजैक्ट टू अवेलेबिलिटी आफ फंड्स का जिक्र करते हैं । स्पीकर साहब, ये मेहरबानी करके अपने रिकार्ड को ठीक करें । जे0 एस0 बी0 की जो कैपेसिटी है, वह 900 क्यूसिक की है , न कि 550 क्यूसिक की, जैसा कि इन्होंने बताया है । लेकिन आज इसकी कैपेसिटी डी-सील्टिंग न होने की वजह से 450 क्यूसिक की रह गई है । स्पीकर साहब, यह हमारे इलाके की एक मुख्य नहर है जिससे अन्य माईनर्ज और सबमाईनर्ज निकलती हैं और इसी नहर से इरीगेशन के लिए और पीने के लिए पानी की सप्लाई होती है । इसलिए क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जे0 एस0 बी0 की लाईनिंग करने के लिए सरकार के पास कोई प्रोपोजल विचाराधीन है ? इसके अलावा, वर्ल्ड बैंक से सारी स्टेट की नहरों की मेन्टीनैंस के लिए जो 800 करोड़ रुपया आ रहा है, क्या प्रायोरिटी के आधार पर उस रुपये से इस नहर की मेन्टीनैन्स करवाने का कष्ट करेंगे ? स्पीकर साहब, हमारा इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है और दक्षिणी हरियाणा में नहरों की मेन्टीनैन्स ठीक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पानी टेल तक नहीं पहुंचता । इस इलाके के साथ पानी के मामले में डिसक्रिमीनेशन हो रहा है । क्या मंत्री जी इन नहरों की मेन्टीनैन्स करने, टेल तक पानी पहुंचाने तथा डिसक्रिमीनेशन दूर करने के लिए ज्यादा पैसा देने का प्रावधान करेंगे ? दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आगरा कैनाल है, जिसका कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार के पास है और हरियाणा में होडल तथा कोसी के इलाके से गुजरती है, इस पर हरियाणा सरकार का कंट्रोल होना चाहिए । क्या मंत्री जी इस नहर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए कोई कदम उठाएंगे । स्पीकर साहब, आज जो स्थिति है, उसके मुताबिक गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों के लिए जितना हमारा शेयर है, वह 25 परसैंट है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है । लेकिन इस शेयर में से वन थर्ड पानी भी इन जिलों को नहीं मिल रहा है । इसलिए मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि वह इसके बारे में क्या कदम उठा रही है ताकि इन जिलों को पानी मिल सके ।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इन्होंने जो यह बात कही है कि डिस्क्रीमीनेशन होता है, यह बात इनकी बिल्कुल गलत है । ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर ये इस तरह की बात करके कोई पोलिटिकल गेन लेना चाहते हों तो अलग बात है । मैं सारी हरियाणा स्टेट का इरीगेशन मिनिस्टर हूं । यह तो है नहीं कि मैं एक ही जगह का मिनिस्टर हूं । इसलिए जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह बिल्कुल गलत है और इस बात से इसका कोई संबंध नहीं है । जहां तक अवेलेबिलिटी आफ फंड्ज की बात है, तो जो डब्ल्यू0 जे0 सी0 है, जिस पर कि करोड़ों रुपये खर्च होने हैं, उसके लिए मैंने 1994–95 में प्रियारिटी की बात कही है । अगर डिस्क्रीमीनेशन की बात होती तो डब्ल्यू0 जे0 सी0, जिसकी कैपेसिटी 12 हजार क्यूसिक है, को हम पहले ठीक करने की बात क्यों करते ? जे0एस0 बी0 तो रोहतक जिले

[चौधरी जगदीश नेहरा]

में लगती है । स्पीकर साहब, यदि हम छोटी चैनल को पहले ठीक करेंगे और बड़ी चैनल को बाद में ठीक करेंगे तो फिर पानी कहां से आएगा ? इसलिए डिसक्रीमीनेशन वाली कोई बात नहीं है । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, जहां तक अवेलिबिलिटी आफ फंड्स की बात है, गवर्नर साहब के ऐड्रैस में साफ तौर पर कहा गया है कि 800 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे और उस पैसे को हम नहरों की मेन्टीनैन्स के लिए लगायेंगे ।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, वह पैसा भी इन सारी बातों के साथ ही लगेगा । (विघ्न) सर, मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता । ऐसा है कि विद इन ईयर डब्ल्यू0 जे0 सी0 का ठीक होना बड़ा मुश्किल है । ये अगले साल की बात कर रहे हैं । स्पीकर साहब, हमारे पास जैसे जैसे पैसा आता रहेगा, वैसे वैसे ही हम काम करते जाएंगे । वर्ल्ड बैंक से 800-900 करोड़ के करीब लिया जा रहा है । मेन बात तो डब्ल्यू0 जे0 सी0 की है । भाखड़ा कैनाल का जो सिस्टम है, वह करीब करीब आलरेडी पक्का हुआ हुआ है । इसलिए स्पीकर साहब, इनकी डिसक्रीमीनेशन वाली बात बिल्कुल गलत है ।

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, भाखड़ा कैनाल में तो सिल्ट भी नहीं है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : जी हां, भाखड़ा कैनाल में दो या तीन परसन्ट के करीब माइनर सिल्ट ही आती है । इस पर डैम बना हुआ है और डब्ल्यू0 जे0 सी0 में जो यमुना का पानी आता है, उसके साथ ही गाद आती है । दूसरी बात इन्होंने जे0 एस0 बी0 कैनाल की लाईनिंग के बारे में कही है, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि यह मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है । दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि आगरा कैनाल का एरिया हरियाणा को मिले, इसके लिए हमने बार-बार लिखा भी है और सैन्ट्रल वाटर रिसोंसिज मिनिस्टर ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी यह अहम, मुद्दा था कि यू0 पी0 वाले हमारी बात सुनते नहीं हैं । इसलिए आगरा कैनाल के नीचे जो हमारा फरीदाबाद का एरिया है, वह हमें मिलना चाहिए ताकि हम उसको ठीक ढंग से मेनटेन कर सकें । मुख्यमंत्री जी ने शुक्ला जी और यू0 पी0 के चीफ मिनिस्टर से भी बात की है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगरा कैनाल का वह एरिया हमें मिल जाए । (विघ्न)

श्री जिले सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या जे0 एस0 बी0 और एस0 एल0 सी0 को डीसिल्ट कराया जाएगा और दोनों पम्प हाऊसिज को जल्दी चालू कराया जाएगा ? इनकी वजह से 12 गांवों की वाटर सप्लाई प्रभावित है, जैसे जासवा के चार गांव, गिलेहड़ी के पांच गांव इससे कनैक्टिड हैं, मातनहेल अकेला है और दादला के दो गांव हैं । वे सभी

गांव वाटर सप्लाई स्कीम के तहत इस चैनल के थ्रू आते हैं । ये चैनल बन्द होने की वजह से वाटर सप्लाई चालू नहीं है । लैडान के साथ, अकेड़ी पम्प हाउस के साथ, यह जो मैंने आबयाने वाली बात पूछी है कि 4–5 गांवों में आबयाना वसूल किया जा रहा है, उसका भी जवाब दें ।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसका जवाब मैं पिछले क्वैश्चन में भी दे चुका हूं कि हम जे0 एस0 वी0 की डी-सिल्टिंग और डी-वीडिंग कराएंगे । जहां तक लैडान को और पानी देने की बात है, पम्प के बारे में तो मैं अभी नहीं कह सकता लेकिन पर्मानैन्ट तौर पर पानी देने की व्यवस्था हम जे0 एल0 एन0 से कर देंगे । पम्प हाउस ठीक करने में ज्यादा पैसे लगेंगे । जे0 एल0 एन0 से पानी देने में हमें दिक्कत भी कम आएगी । मेरे कहने का यही मतलब है कि साइफन से पानी जाता है या एस्केप से जाता है, उसको पर्मानैन्टली जे0 एल0 एन0 से जोड़ देंगे ताकि पानी आपके एरिया में चला जाए और पम्प हाउस की, आपकी दिक्कत दूर हो जाए । दूसरी बात जो इन्होंने कही कि गिरदावरी हो गई । जहां पानी नहीं लगता वहां आबयाने की गिरदावरी नहीं होती । यदि कहीं हो गई हो और आप लिखकर देंगे तो तभी इक्वायरी करा लेंगे । जहां पानी नहीं लगेगा वहां हम आबयाना नहीं लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आपने पिछले सैशन में यह आश्वासन दिया था कि जो डी-सिलटिंग कराते हैं, उसका लिमिटेड टाइम होता है । कुछ पैसा बकाया था, जो देना था और पेमैन्ट आपने करनी थी । आपने आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक पेमैन्ट हो जाएगी । क्या आप अपने आश्वासन को पूरा करेंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, यह बात मेरे ध्यान में है । कैथल सब-डिवीजन में आपके एरिये की बात है । उसमें 90 लाख रुपये की पेमैन्ट है, 40 लाख रुपये की पेमैन्ट कर चुके हैं । कोई 50 लाख रुपये और हैं वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, इस बारे में नेहरा साहब ने विस्तार से बताया है । यह बहुत अहम मुद्दा है कि नहरों की सिल्ट, नहरों में जो गाद है, उसकी सफाई का काम होना चाहिये । हमारी सरकार अप्रैल 1994 से इन चारों बातों को पहल देगी । एक तो बिजली पर, दूसरे नहरी के पानी पर, तीसरे पीने के पानी पर और चौथे सड़कें जो टूटी हुई हैं, उनकी मुरम्मत पर । आने वाले एक साल के अन्दर–अन्दर सारे प्रदेश में कोई भी नहर या माईनर ऐसी नहीं बचेगी जिसमें सिल्ट बाकी रह जायेगी । सब की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचायेंगे ।

Literacy Campaign

***811. Shri Dhirpal Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether any amount has been earmarked under the literacy campaign in the State during the year 1993-94 ; if so, the details of achievement made in this regard ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) : Yes Sir, an amount of Rs. 50 lacs has been earmarkd this year for the literacy programmes in the State. Eight Literacy projects and one post literacy project have been taken up. Projects under literacy phase are in districts of Ambala, Yamuna Nagar, Bhiwani, Jind, Rohtak, Sirsa and Hisar. One post-literacy project is in progress in Panipat. Environment building programme has been started in the remaining districts.

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि रोहतक में कितने लोगों को साक्षर किया गया है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, रोहतक में जो हमने टार्गेट फिक्स किया था, वह 3 लाख 60 हजार का था । आज जो रोहतक में क्लासिज अटैंड कर रहे हैं , वे 28069 लोग हैं । इस में तीन स्टेजिज होती हैं । 20 हजार पहला प्राईमर जिसको हम कायदा बोलते हैं, वह कम्पलीट कर चुके हैं । 6 हजार सैकंड कम्पलीट कर चुके हैं और 500 तीसरा प्राईमर कम्पलीट कर चुके हैं ।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की है, इस बारे में क्या कोई ऐसी शिकायत आपको मिली है कि इसका दुरुपयोग किया गया है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है । यह जो पैसा हम खर्च करते हैं, इसकी डिटेल्ज इस तरह से है । तीन तो हमारी किताबें हैं जिनकी कास्ट 25-30 रुपये आती है । ट्रेनीज, वालंटीयर्ज, मास्टर्ज और ट्रेनर्ज वगैरह पर 15-20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन की कास्ट आती है और 10-15 रुपये सर्वे, एनवायरनमैंट, बिल्डिंग, मौनिटरिंग और इवैल्यूएशन वगैरह पर कास्ट आती है । इस प्रकार से प्रति व्यक्ति साक्षर बनाने की कास्ट 60 रुपये से लेकर 65 रुपये तक आती है । इसके अलावा, मैं माननीय सदस्य को एक और बात बता दूं कि हरियाणा में साक्षरता अभियान केन्द्रीय स्तर से आगे है । जो केन्द्रीय स्तर पर साक्षरता की परसैन्टेज है, वह 64 परसैन्ट है जबकि हरियाणा में 69 प्रतिशत है । अध्यक्ष महोदय, इससे जो सबसे बड़ा फायदा हमारे प्रान्त को हुआ है, वह यह है कि जो बच्चे 6 से लेकर 11 वर्ष के स्कूलों में नहीं जाते थे, उसमें हमने बड़ी भारी अचीवमैंट प्राप्त की है । प्राइमरी स्टेज पर जो 6 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बौएज 119 परसैन्ट ड्रौप-आऊट्स थे और इसी तरह से बच्चियों

की परसैन्टेज 109 थी, वह इस साक्षरता अभियान के प्रचार की वजह से संख्या 49 परसैन्ट से घटकर 15 परसैन्ट पर आ गयी है । इसका स्टेट को बड़ा ही लाभ हुआ है ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि साक्षरता अभियान के लिए इन्होंने जो राशि रखी है, वह केवल दीवारों पर नारे लिखने के काम आती है या किसी को साक्षर करने के काम में भी आती है । इस काम के लिये प्रोपोर्शनेटली कितना पैसा दिया गया है ? मेरा पूछने का मतलब यह है कि विज्ञापन के लिये कितना पैसा खर्च होगा और स्लेटों, पट्टियों और अध्यापकों के वेतन आदि पर कितना पैसा खर्च होगा ?

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर साहब, अभी मैंने पूरी तफसील में बताया है । माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया , इनका ध्यान शायद कहीं और था । मैंने यह बताया है कि 60 से लेकर 65 रुपये प्रति व्यक्ति साक्षर बनाने में आते हैं । इसमें विज्ञापन वगैरह के लिये 10 से लेकर 15 रुपये तक हैं । विज्ञापन में जो हम पैसा देते हैं, उसमें फिल्में दिखाते हैं, कैसेट्स चलाते हैं, मीटिंगे करते हैं, ग्रामोफोन बजाते हैं और गावों में मुनादी वगैरह भी कराते हैं । इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिये 10 से लेकर 15 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा आता है । हमारे पास तीनों तरह की बुक्स हैं । चौथी तरह की बुक्स जो हैं, वह पोस्ट साक्षरता अभियान में आती हैं, वह भी हमारे पास हैं ।

Mr. Speaker : Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Sisana Minor

*740. **Shri Balwant Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that water of Sisana Minor does not reach upto tail ; if so, the reason thereof ; togetherwith the action taken or proposed to be taken to supply water of the said minor upto tail ?

सिंचाई मन्त्री (चौ० जगदीश नेहरा) : नहीं, पानी पहले भी सिसाना माईनर के अन्तिम छोर तक पहुंच रहा था और अब भी पहुंच रहा है ।

Construction of Roads

*767. **Shri Ramesh Kumar** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads from Chhichhrana to Kathura and from Madina to Bhanderi in Baroda constituency, and

(b) if so, the time by which the roads as referred to in part (a) above are likely to be constructed ?

कृषि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह) : (क) एवं (ख) मदीना से भंडेरी तक सम्पर्क सड़क के निर्माण का कार्य मैटलिंग स्तर तक पूर्ण हो चुका है । प्रीमिक्स कारपेट का कार्य शेष है जो कि शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा । छिछड़ाना से कथूरा तक सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

Bus Stand at Mahendergarh

*784. **Prof. Ram Bilas Sharma** : Will the Minister of State for Transport be pleased to state the present stage of the construction of the Bus Stand, Mahendergarh togetherwith the time by which it is likely to start functioning ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह) : निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु सफेदी, रोगन, फर्श तथा चार दिवारी का निर्माण अभी किया जाना है । बस अड्डे के आगामी वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने की संभावना है ।

Construction of Pucca Plat form

*736. **Sathi Lehri Singh** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct 'pucca' platform of Sub-Yards Gumthala Rao (Market Committee, Radaur); and

(b) if so, the time by which the aforesaid platform is likely to be constructed (pucca) ?

कृषि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) यह कार्य अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया जायेगा और मार्च 1995 तक इसे पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे ।

लिखित उत्तर

Schools Building Unsafe

*776. **Shri Jaswinder Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the school building of Pehowa Block ; if any have been declared un-safe during the year, 1992-93 ; and

(b) if so, the steps so far taken or proposed to be taken to repair/construct the aforesaid buildings ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । (क) के दृष्टिगत इसकी आवश्यकता नहीं थी ।

Recruitment made in Slum Clearance Board

*751 **Shri Mohan Lal Pippal** : Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether any recruitment has been made in the Slum Clearance Board, Haryana during the period from Ist December, 1993; if so, the criteria adopted for the said recruitment ?

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (चौधरी धर्मवीर गावा) : जी हां, 1-12-93 के पश्चात केवल एक ही सीधी नियुक्ति की गई।

Construction of Roads by Market Committee, Palwal

*771. **Shri Azmat Khan** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether any road has been constructed by the Market Committee, Hodel or Market Committee Palwal in block Hathin during the period from 1991 to 31-12-93; if so, the details thereof ?

कृषि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह) : खण्ड हथीन में मार्केट कमेटी, पलवल और होडल द्वारा प्रश्न में दी अवधि के दौरान निम्नलिखित पांच सड़कों का निर्माण किया गया है :—

[श्री हरपाल सिंह]

क्रम सं0	सड़क का नाम	प्रगति की अवस्था	व्यय (रु0 लाखों में)
1.	मोधमका से अन्धौरला	कार्य पूर्ण हो चुका है	5.12
2.	स्वामिका से घरोट	कार्य पूर्ण हो चुका है	3.01
3.	अहरवां से भंगूरी	कार्य पूर्ण हो चुका है	8.06
4.	अन्धोप से नांगल जाट	कार्य पूर्ण होने के नजदीक है	8.83
5.	सेविल से बहीन	कार्य पूर्ण होने के नजदीक है	10.12

Construction of Bhambhewa Minor

*742. **Shri Om Parkash Beri :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that the sanction for the construction of new Bhambhewa minor in Haryana Division of W.J.C., Rohtak has been accorded; if so, the time by which the construction work of the aforesaid minor is likely to be started/completed ?

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : हां । यह स्कीम तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं थी तथापि इसे इस कारण स्वीकार कर लिया गया कि जमींदार बिना मूल्य भूमि उपलब्ध करायेंगे । किन्तु बाद में यह स्कीम रद्द कर दी गई क्योंकि जमीदारों ने बिना मूल्य भूमि देने से इन्कार कर दिया था तथा इस क्षेत्र में सिंचाई भी सन्तोषजनक पाई गई थी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Realisation of Sales Tax

166. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the total amount realised as sales tax during the year 1992-93 in Palwal City ; and

(b) whether it is also a fact that amount realised during the year 1992-93 is less than the previous year ; if so, the reasons therefor ?

आबकारी एवं कराधान मन्त्री (श्रीमती करतार देवी) :

(क) 3,07,34,610 रुपये ।

(ख) नहीं, जी ।

Construction of Houses at Palwal

167. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct houses in Palwal, District Faridabad by the Housing Board, Haryana during the year 1994; if so, the number thereof ?

आवास राज्य मन्त्री (श्री बचन सिंह आर्य) : वित्तीय वर्ष 1993-94 (1-4-1993 से 31-3-1994 तक) के अन्तर्गत आवास बोर्ड, हरियाणा ने पलवल में 109 एल0 आई0 जी0 मकानों का निर्माण किया है जिनका निर्माण कार्य समाप्ति पर है । इस समय पलवल में कोई और मकान बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

प्रो0 छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, हमने एक काल अटैन्शन मोशन दिया है कि भिवानी जिले में आतंकवाद सरकार की शह पर फैल रहा है । मैं तो यह कहूंगा कि भिवानी तो क्या सारे हरियाणा के अन्दर ही सरकारी शह पर आतंकवाद बुरी तरह से पनप रहा है ? अगर सरकार के सहारे, सरकार के अपने ही आदमी, सरकार के मन्त्री ही कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर आम आदमी का क्या होगा ? (शोर)

Mr. Speaker : It is under consideration.

श्री जिले सिंह : स्पीकर सर, इस औगस्ट हाउस में कल एक बड़ी अच्छी बहस हो रही थी कि शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए और प्रदेश में नकल को रोका जाए । इस में यह भी कहा गया है कि कुछ मन्त्री व बड़े आदमी, अपने बच्चों को पास करवाने के लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं । इस बात का ताजा उदाहरण हमें मिला है । बैश स्कूल रोहतक के अन्दर श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो मन्त्री हैं, का लड़का और इनका साला कुछ बच्चों को नकल करवा रहे थे । ऐसा करने से उनको रोकने के कारण इन लोगों ने तीन पुलिस कर्मचारियों को बुरी तरह से पिटाई कर दी, परिणामस्वरूप श्री धर्मबीर नाम का एक पुलिस का आदमी मैडीकल

[श्री जिले सिंह]

कालेज रोहतक में बुरी तरह जख्मी होने के कारण दाखिल है। (शोर) इस तरह से अगर अन्तियों के लड़के व रिश्तेदार ऐसा काम करेंगे तो फिर प्रदेश के अन्दर कानून और व्यवस्था क्या सुधरेगी । इस बारे में सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे । (शोर) यह बड़ा ही सीरियस मामला है । (शोर)

Mr. Speaker : It is under consideration.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, स्टेट के अन्दर चाहे कोई कितना ही बड़ा या छोटा आदमी हो, उसे कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी । चूंकि यह झगड़ा रोहतक में हुआ है जिसका फौरन मुकदमा दर्ज करके कृष्णमूर्ति हुड्डा के लड़के और उनके साले को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे हवालात में बन्द हैं । कानून के मुताबिक जिन लोगों ने वहां पर गड़बड़ की है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : * * * * *

* * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये सारी बातें रिकार्ड पर न लाई जाएं । यह मामला सब जूडिस है, इसलिए इस बारे में कुछ भी रिकार्ड न किया जाए ।

प्रो० सम्पत सिंह : * * * * * *

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Speaker, Sir, it is very much a sub-judice matter, how they are saying that it is not a sub-judice matter, when they were arrested yesterday and they have given application for bail ? So, it is a sub-judice matter. (Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : I have already given my decision in this regard.

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटेन्शन मोशन का नोटिस दिया है । पहले भी हमारे विपक्ष के नेता ने एक प्रस्ताव रखा था जो इसी बारे में था । स्पीकर साहब, आज इसी भवन में पंजाब विधान सभा मिलने जा रही है और इससे पहले पंजाब के मुख्य मन्त्री ने कैटेगरीकल ब्यान दिया था कि एस० वाई० एल० नहर बनाने के लिए मैंने कोई आश्वासन चौधरी भजन लाल को नहीं दिया है । (शोर)

श्री अध्यक्ष : वह आपने सुबह 9.05 पर दिया है और मेरे अंडर कंसिडेशन है । आप बैठें ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, अभी जो काल अटैन्शन मोशन का जिक्र आ रहा था, हमने बाकायदा कई दिन पहले लोहारु वाला मोशन दे रखा है । ये ज्यादतियां एक दिन में नहीं हुई बल्कि यह एक कन्टीन्यूस प्रोसैस है । रोज ज्यादतियां हो रही है । लोहारु में 23 तारीख को मुख्य मन्त्री की सभा थी । वहां पर औरतों को पकड़ा गया और उनको तोशाम के थाने में लाया गया.... (शोर)

श्री अध्यक्ष : वह गवर्नमैंट को कमैंटस के लिए भेजा हुआ है ।

Prof. Sampat Singh : He is not only the brother-in-law of the Minister but he is Personal Asstt. (Political) to the Minister. It is his moral responsibility. Either he should resign or the Chief Minister should dismiss him. (Interruptions)

Mr. Speaker : Please take your seat.

सांयी लहरी सिंह : स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैंशन मोशन दिया था । स्पीकर साहब, किसानों की आलुओं की फसल खराब हो रही है, उनको समय पर बिजली नहीं मिल रही है । आपने मेरे काल अटैन्शन मोशन का क्या फैसला किया है ?

श्री अध्यक्ष : वह अंडर कंसिडेशन है ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान: स्पीकर साहब, हमारे भिवानी में पीने का पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है । पीलिया फैला हुआ है और आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपका जौंडिस के बारे में जो काल अटैन्शन मोशन है, वह 15 तारीख के लिए एडमिटिड है ।

श्री ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, मेरे तीन काल अटैंशन मोशंज हैं । एक तो पोलिटिकल पार्टीज द्वारा करप्शन के खिलाफ है । दूसरा डंकल प्रस्ताव के बारे में है और तीसरा डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ कैनाल वाटर के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : वे अंडर कंसिडेशन हैं ।

श्री ओम प्रकाश बेरी : सर, एक रूट परमिट के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : वह गवर्नमैंट को कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

पलवल में नील गाय द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received two calling attention notices Nos. 2 and 10 given notice of by Sarvshri Karan Singh Dalal and Om Parkash Beri, respectively, regarding the damage caused to the standing crop by the "Neel gai". I admit both these notices. Shri Om Parkash Beri may read his notice and thereafter the Minister concerned may make a statement.

Shri Om Parkash Beri : Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance concerning the havoc created by the wild animal called "Neel Gai" to the standing crops and human life in the State. A recent survey of Wild Life Department has revealed that their population is increasing very fast. This survey has reported that their population in the plains of Haryana is eighteen thousand and in hilly areas it is reported to be about 25 thousand. These animals are now causing heavy losses to the standing crops and are even attacking the human beings. They are also causing accidents on the roads. The general public in the State is very sore over the indifferent attitude of the Government towards this acute problem. I therefore request the Government to make a statement on the floor of the House in this regard.

Shri Karan Singh Dalal : I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that there are antelopes (Rojh) in abundance in the area of Palwal and the antelopes in herds wander here and there and graze the standing crops in the fields. The farmers have requested the Administration many times that the arrangements be made to protect their standing crops in the fields but the Administration has not made any arrangements so far. On account of it, the crops worth lakhs of rupees is being grazed by the antelopes.

I, therefore, request the Government to make a statement in the House in this regard.

वक्तव्य–

जंगलात मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

Forests Minister (Rao Inderjit Singh) : The issue in this case is the damage being caused by the neelgai to the crops in the State including the area of Palwal. As per the assessment of the Chief Wild Life Warden, Haryana, the population of neelgais in the State has increased considerably and is presently estimated to be around 20,000. The damage to crops has obviously increased manifold. Over the years, the issue of

finding a permanent solution to this problem has been taken up on many occasions but no final solution has emerged, largely because of the religious sentiments attached to the neelgai Actually, it is an antelope belonging to deer family and in cetain areas this animal is known as "ROJH".

2. The Department of Wild Life Preservation, Haryana, has been receiving complaints as well as representations from the farmers regarding the damage being caused by neelgai to the crops. This matter was discussed at the Government level about 6 years back and vide instructions dated the 21st June, 1988, it was decided that no case of killing/shooting ROJH be sent to judicial court for a verdict unless the permission of the State Government on merits of each case has been obtained, This matter was also discussed in the 13th meeting of the State Wild Life Advisory Board, Haryana held on 7th September, 1993 at Pinjore under the Chairmanship of Hon'ble Forests and Wild Life Minister. The Board also recommended that to reduce the number of blue bulls, the State Government be requested to allow controlled culling and for this, limited permits be issued. There, however, are legal impediments in adopting the above measure. The Board also decided that a report from the Wild Life Institute of India, Dehradun be obtained as the Institute has conducted a detailed study on this problem in the State but the final report on the project 'Ecological studies to evaluate crop damage by neelgai in Haryana' is still awaited,

3. Under the Wild Life (Protection) Act, 1972, as amended with effect from 2nd October, 1991. there is a complete ban on hunting of wild animals including neelgai. However, permits to hunt such animal including neelgai which has become dangerous to human life or property including standing crops can be issued by Chief Wild Life Warden or his authorised officer by order in writing and stating reasons therefor.

श्री ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह माना है कि इस नील गाय से ह्यूमन लाईफ को भी खतरा है और स्टैंडिंग क्राप्स को भी खतरा है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस जानवर के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके तहत वाइल्ड लाईफ (प्रोटैक्शन) एक्ट की अमैंडमैंट करके इस जानवर की हंटिंग की इजाजत दी जाए। जहां तक लोगों की धार्मिक भावनाओं का ताल्लुक है, उस बारे में मेरा कहना यह है कि ऐसी लोगों की कोई भावनाएं नहीं जुड़ी हुई, और न ही लोग इसे गाय मानते हैं। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट में तरमीम करने पर विचार करेंगे, ताकि किसानों को इस जानवर से छुटकारा मिल सके ? इसके साथ ही साथ, मैं यह पूछना चाहता हूं कि चीफ वाईल्ड लाईफ वार्डन ने कितने लोगों को हंटिंग का लाईसैंस दिया है और कितने लोगों ने एप्लाई किया था ?

राव इन्द्रजीत सिंह : जहां तक अमैंडमैंट की बात है, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 2-10-91 को भारत सरकार ने पार्लियामैंट के अन्दर इस एक्ट में अमैंडमैंट की है जिसके तहत किसी भी जंगली जानवर को मारने पर प्रतिबंध है। हरियाणा

[राव इन्द्रजीत सिंह]

सरकार भी भारत सरकार के अमैंडमैंट किए गए एक्ट को मानेगी। दूसरी बात यह है कि हम हंटिंग की परमिशन दे रहे हैं या नहीं। स्पीकर साहब, इस बारे में स्थिति यह है कि पिछले साल यू0पी0 गवर्नमैंट ने, भारत सरकार को एप्रोच किया था कि नीलगाय की वजह से हमें काफी दिक्कत आ रही है, इसलिए आपकी इजाजत चाहते हैं कि यू0पी0 में शिकार करने की इजाजत दी जाए। इस पर भारत सरकार ने यू0पी0 सरकार को कहा कि आप का चीफ वाईल्ड लाईफ वार्डन ही इसकी इजाजत दे सकता है। Chief Wild Life Warden can issue permit after he has obtained applications from the villagers regarding damages being caused to crops and human lives etc. हमारे यहां सन् 1988 में, जब पिछली सरकार सत्ता में थी, उस दौरान यह निर्णय लिया गया था कि नील गाय को अगर कोई मारेगा तो कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। नील गाय को मारने का केस गवर्नमैंट को भेजा जाएगा और गवर्नमैंट उसको कोर्ट में ले जाएगी। जब से यह फैसला हुआ है, सरकार की तरफ से कोई केस कोर्ट में नहीं गया है। 1990-91 तक 6-7 साल के अर्से में किसी भी हरियाणा वासी ने नील गाय का शिकार नहीं किया है और इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक बार यह अन्दाजा किया गया था कि अगर इसको एक जगह बन्द करके रखा जाए तो उस पर कितना खर्च होगा। 1000 एनीमल्ज को एक जगह रखने के लिए 400 हैक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। फैंसिंग के लिए जो खर्च होगा वह अलग। एक हजार नील गाय को एक जगह रखने के लिए एक करोड़ 14 लाख रुपए सालाना खर्च होंगे और अगर 20 हजार नील गायों को एक जगह बन्द किया जाए तो 22 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना खर्च आएंगे। इसमें जमीन की एक्विजीशन का खर्च शामिल नहीं है। इतना अधिक खर्च इसको बन्द करके रखने के लिए वहन करना किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, सरकार नये सिरे से इस पर विचार कर सकती है, नील गाय के शिकार के लिए दोबारा भारत सरकार को लिखा जाए। जो सरकमस्टांसिज इसकी वजह से पैदा हो गए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए शिकार के लिए लाईसेंस देने का जो सिस्टम है, उसको लिबरेलाईज कर दिया जाए ताकि लाईसेंस लेने में कोई दिक्कत न हो।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि जो जीव जन्तु संसार में पैदा हुए हैं, वह इन्सान की भलाई के लिए ही पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने शिकार पर पूरा बैन लगाया हुआ है और हरियाणा में भी बैन है। नील गाय को मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इन्होंने कहा है कि यह फसल को बड़ा भारी नुकसान करती है। स्पीकर साहब, सब को पता है कि जब हरियाणा बना था तो 26 लाख टन अनाज का उत्पादन होता था लेकिन अब 102 लाख टन अनाज पैदा होता है जो एक रिकार्ड है। इस संसार में जो भी जीव-जन्तु आता है, वह अपने भाग का

लेकर आता है, इसलिए किसी जीव को मारे जाने का कोई सवाल ही नहीं है फसल का बहुत ज्यादा नुकसान इसकी वजह से नहीं हुआ, यदि ऐसा होता तो उत्पादन इतना ज्यादा न बढ़ता। (विघ्न) सांप भी वैसे नहीं काटता, उस पर पैर रखा जाए तो काटता है या उसको मारने जाएं तो काटता है।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, अगर किसान खाली हाथ खेत में जा कर नील गाय को खेत से बाहर करने की कोशिश करता है तो नील गाय उस पर प्रहार भी करती है।

चौधरी भजन लाल : निकालने जाएं, तो यह प्रहार क्या करेगी, इसको अगर पकड़ लिया जाए तो पकड़ने से ही मर जाती है। (विघ्न) दूध तो यह अपने बच्चों के लिए देती है और उनको पिलाती है, यह किसी आदमी के लिए दूध नहीं देती। (विघ्न एवं शोर)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon. members, now discussion on Governor's Address will be resumed. Shri Dhir Pal Singh may speak.

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)।

आप सब बैठ जाएं। आप में से एक ही बोल सकेगा और टाईम भी 20 मिनट होगा। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। अब तक ट्रेजरी बैन्चिज से 169 मिनट बोल चुके हैं और 139 मिनट अपोजीशन वाले बोल चुके हैं जिसमें से 78 मिनट तो सम्पत सिंह जी ही बोले हैं। अब आप में से जो भी बोलना चाहे, बोल सकता है और वह 20 मिनट तक ही बोल सकता है।

श्री धीरपाल सिंह (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने जो लिखी हुई किताब पढ़ी और यहां हाउस में सुनाई तथा उस विषय में हमारे कई साथियों ने यह आपत्ति भी की कि समाजवादी पार्टी ने इस अभिभाषण का बाई काट किया है। यह लोकतान्त्रिक प्रणाली में अच्छा नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की इस सरकार में आस्था ही नहीं है और गवर्नर साहब ने एक लिखी हुई किताब यहां पर पढ़ कर सुना दी थी। उस किताब में प्रजातन्त्र की समृद्धि के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसको हमने बार बार पढ़ा और उसको बार बार पढ़ने से पता चला कि उसमें मेरी सरकार—मेरी सरकार लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। (विघ्न एवं शोर)

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार पर से उठ गया है। आज कानून व्यवस्था की क्या हालत है, यह सब जानते हैं। इसके लिए इन्हें शर्म आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्द को बदल लेता हूं। सर, पिछले तीन सालों में जो भी सैशन हुए हैं, इन्होंने पिछली सरकार को सिर्फ कोसने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है जिससे प्रदेश में कोई उन्नति हुई हो, बिजली पानी की स्थिति में सुधार हुआ हो। हमारे ट्रेजरी बैन्चिज के साथी जब बोलें तो उन्हें तो यह कहना चाहिए था कि उनकी सरकार यह कर रही है और यह करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड निकाल कर देख लें, इन्होंने आज तक सिवाय पिछली सरकार को कोसने के और कुछ नहीं किया है। आज हरियाणा में कानून एवं व्यवस्था टूट रही है, आज कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अभी एक राजकुमार का नाम आया था और ऐसे पता नहीं कितने राज कुमार हैं। अगर मैं नाम लूंगा तो ये फिर से खड़े हो जाएंगे। सिर्फ वही नहीं, सब वही काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)। आज तक अढ़ाई साल में कितनी ही हत्याएं हुई हैं, कितनी ही बहनों की आबरू लूटी गई है और उधर मुख्य मंत्री जी कहते थे कि उनके राज में किसी की बहन-बेटी की इज्जत को खतरा नहीं होगा। आज हम सभी इसके लिए जिम्मेवार हैं और खासतौर पर ये ट्रेजरी बैन्चिज वाले इसके लिए जिम्मेवार हैं। स्पीकर साहब, जब नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो और उसके बारे में चिन्ता व्यक्त न की जाए तो कानून व्यवस्था की कैसे बात कही जा

11.00 बजे

सकती है? अगर हम उस पर प्रकाश न डालें तो हम यहां पर किस बात के लिए आए हैं? 19 दिसम्बर को गांव कलावड़ में दो लड़कों की गोलियां मारकर हत्या की जाती है और सरकार के डी0सी0 हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्त्ता के रूप में वहां पर कार्य कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये लड़के गुन्डे थे, अपराधी थे। अगर ये लोग गुन्डे भी थे, अपराधी भी थे तो यह कहां पर लिखा हुआ है कि उनको गोली मारकर हत्या की जाए? आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी के हत्यारों को भी गोली नहीं मारी गई थी बल्कि कानून के मुताबिक ही उनको सजा दी गई थी जिसको सारे देश ने माना था। इसी तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी की भी उनकी कोठी पर अपने पद पर रहते हुए हत्या की गई थी लेकिन उनके हत्यारों को भी गोली नहीं मारी गई थी बल्कि देश के कानून के हिसाब से सजा या मौत की सजा हुई थी जिसको देश के लोगों ने स्वीकार किया था। लेकिन स्पीकर साहब उस गरीब मलिक किसान परिवार के बेटों की गोली मार कर हत्या की गई। जब धर्मपाल जी ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव डाला तो इनकी तरफ से घोषणा हुई कि उनको एक एक लाख रुपए कम्पनसेशन के रूप में दिए जाएंगे। मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि ये हाउस के नेता हैं, इन्होंने किस

बात के लिए उनको कम्पनसेशन दिया ? एक तरफ तो इनका डी0सी0 उनको गुन्डा, बदमाश और अपराधी घोषित करता है और दूसरी तरफ उन दोनों लड़कों की जान की कीमत में दो लाख रुपए देते हैं ?

चौधरी भजन लाल : अभी इस केस की जुडीशियल इंक्वायरी चल रही है।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, एक आदमी का गुर्दा भी डेढ़ लाख रुपए में बिक जाता है और दो आदमियों के गुर्दे की तो तीन लाख रुपए कीमत होती है। साधारण किसान के बेटों को इस ढंग से मार दिया जाए.....(विघ्न) मुख्यमंत्री जी, आपने 90-90 किलो के लड़कों को गोलियों से मरवाकर जो एक एक लाख रुपए दिये हैं, यह क्या दिए हैं, यह शर्म की बात है। स्पीकर साहब, केवल यही एक बात नहीं है। मेरे हल्के बादली के एक गांव लंगरपुर में मंशाराम का बेटा था जो सरपंच था। इसी 17-18 फरवरी को उसके बेटे को उठा लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सारा इलाका एस0पी0 रोहतक से अनुरोध करने के लिए इकट्ठा हुआ कि जिस ढंग से उस लड़के की हत्या हुई है, वह बहुत चिन्ताजनक है। हत्या करने के बाद उस लड़के को नंगा करके सड़क के किनारे डाल दिया गया। सारे लोगों ने उस लड़के की हत्या को देखने के बाद कहा कि हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हत्यारों को पकड़ा जाए। लेकिन हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए। सारे गांव के भाई पुलिस प्रशासन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।

स्पीकर साहब, आज से दस दिन पहले बिजली गायब हो जाती है और बिजली गायब हो जाने का खामियाजा व्यापारी वर्ग को उठाना पड़ता है। रोहतक में बिजली गायब हुई और अपराधी किस्म के लोगों ने एक दुकानदार पर गोली चलाकर हत्या कर दी। स्पीकर साहब, पता नहीं आज हमारे समाज को क्या हो गया है। लोगों ने उसकी लाश को नहीं देखा जिसमें से खून बह रहा था बल्कि उसके सूटकेस को उठाकर, पैसे निकाल कर ले गए, जबकि लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए था लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। बाद में एक दारू पीने वाला पकड़ा गया जो पैसे ले गया था। अगर ऐसा न होता तो सरकार कहती कि अपराधी ही उसके पैसे निकाल कर ले गए हैं। पुलिस यही मानती है कि डकैत ही पैसे लेकर गए हैं।

रोहतक, सांपला के पास, डकौरा और सांपला के बीच गाड़ी दिल्ली से रोहतक की तरफ आती है। आज से 15-20 दिन पहले की बात है, तीन डकैत एक डिब्बे में चढ़ गए। सारे डिब्बे को लूटा लेकिन लोगों ने विरोध नहीं किया। विरोध इसलिए नहीं किया किया तो उनका कानून पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि आज कल कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हैं। सारा सामान एक-एक करके देते गए लेकिन जब उन लोगों की नीयत किसी शरीफ परिवार की बहू बेटी की इज्जत की ओर गई तो उसके

[श्री धीर पाल सिंह]

दो भाइयों ने विरोध किया और उस विरोध का नतीजा यह हुआ कि उन डकैतों ने एक भाई की हत्या कर दी और एक को चाकू मारकर घायल कर दिया। दूसरा भाई अस्पताल में कराह रहा है, सरकार की जान को रो रहा है। (विघ्न) वे नेहरा साहब के साथी हैं जिनको ये सिरसा में पनाह देते हैं। इस तरह से डकैतों और अपराधी किस्म के लोगों को ये पनाह देते हैं और भेजते हैं कि वहां जाकर अपना हाथ साफ करो। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में आज किसी की जान-माल महफूज नहीं है। आज हर व्यक्ति या तो खुद अपनी सुरक्षा कर रहा है या घर के किसी कोने में छिप कर बैठ गया है। इस प्रकार से अगर कोई जिंदा है तो यह सरकार का अहसान नहीं है। इस सरकार के शासन काल में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार हो रहे हैं, किसी की जान-माल सुरक्षित नहीं है।

हमारे कर्मचारी भाई चौधरी भजन लाल के बड़े प्रशंसक थे, हिमायती थे और कहते थे वे बड़े भले आदमी हैं। पिछली बार 1991 के चुनाव में इन्हें समर्थन भी दिया। पीछे उन्होंने अपनी मांगें रखीं, मांगे रखने पर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसा आजादी के बाद न तो किसी ने देखा होगा, न सुना होगा। उनको यातनाएं दी गई, जेलों में डाला गया, पीटा गया। रोहतक शहर में रामचंदर नाम का एक बाल्मीकि भाई, जो हरियाणा रोडवेज में सफाई कर्मचारी था उसने कर्मचारी एकता जिंदाबाद का नारा लगाया। यहां बैठे हुए माननीय सदस्य सुबह से शाम तक हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए चर्चा करते रहते हैं लेकिन आज जो शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हमारे साथी नौकरी में हैं, उनको किस ढंग से पीड़ा दी जाती है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, उसकी ये कभी चर्चा नहीं करते। तो मैं उस कर्मचारी के बारे में कह रहा था। उसे वहां से उठाकर हिसार ले जाया गया। वह शरीर से कमजोर था। रात को मार पड़ी, मार को वह बर्दाश्त न कर सका और इस संसार से चल बसा। उसके बाद सरकार ने रिपोर्ट प्रकाशित की कि हार्ट अटैक से उसका निधन हो गया है। मैं और सरदार बलवन्त सिंह मायना मानवता के नाते उसके घर गए, उसकी विधवा ने पूछा कि चौधरी साहब यह हार्ट अटैक क्या बीमारी होती है मैंने उसे बताया कि जिस व्यक्ति का खून गाढ़ा हो जाता है तो उसका दिल काम करना छोड़ जाता है और हृदय गति रुक जाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस विधवा ने रोते हुए मुझे बताया कि हम बहुत गरीब हैं, जन्म लेने के बाद दूध हमने कभी देखा नहीं, फल किस दरख्त पर लगते हैं, यह हमें पता नहीं, अच्छे प्रोटीन का हमें पता नहीं तो फिर यह खून गाढ़ा कैसे हो गया ? अगर खून गाढ़ा नहीं हुआ तो फिर हार्ट अटैक कैसे हुआ ? (व्यवधान व शोर)।

श्री अध्यक्ष : प्रोटीन के मायने तो वे जानते होंगे ।

श्री धीर पाल सिंह : जी हां, प्रोटीन के मायने यह है कि अच्छी खुराक हो। दूध घी और मक्खन वगैरह उनको मिले। तो मैं राम चन्द्र की बात कर रहा था । इस सरकार ने 15,000 हमारे भाईयों के साथ ऐसा सलूक किया । उनके परिवार से उनके बेटे बेटियों और बहिनों को ले गये । जब इन्होंने देखा कि अब तो यह सारे इकट्ठे हो गये हैं और चौधरी भजन लाल की अपनी कुर्सी हिलती नजर आयी तो यह घबरा गये । उस समय कर्मचारी यूनियन के नेता हमारे नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला के पास भिवानी में आये । उन्होंने यह कहा कि आप हमारी मदद कीजिये । ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको यह कहा कि हमारी इस समय सरकार तो है नहीं जो मैं कुछ कर सकूं लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जब भी कभी परिवर्तन होगा और हमारी सरकार बनेगी तो पहला आदेश मैं यह करूंगा कि यह जो 15,000 कर्मचारी बर्खास्त किये गये है, इनको सेवा में बहाल करूंगा । चौधरी भजन लाल जी को तो * * * * * * * * पहले तो 15,000 कर्मचारियों को यातनाएं दी गयीं, उनको जेलों में ठूंसा गया, उनकी पत्नियों को भी पिटवाया गया। सड़कों पर उनके परिवार के लोगों को पीटा गया । उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के डर से उनको सेवा में बहाल कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : यह जो थूक कर चाटने वाली बात कही गयी है, यह रिकार्ड न की जाये ।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, एस0 वाई0 एल0 हरियाणा प्रदेश की भाग्य रेखा को जोड़ने वाली नहर है । इस गवर्नर एड्रेस में कहीं पर भी इस बात के बारे में एक शब्द का प्रयोग तक नहीं किया गया है कि इसको किस ढंग से जल्दी पूरा किया जायेगा । चौधरी भजन लाल हमेशा बाहर सभाओं में यह ब्यान देते रहे हैं कि हम जल्दी ही वहां पर काम शुरू करने वाले हैं । कभी यह कहते हैं कि एक साल में इसे बना देंगे तो कभी कहते हैं कि 6 महीने में काम शुरू करा देंगे । सारा हाउस इस बात के लिये चिन्तित है । हमारे विपक्ष के नेता यहां इस बारे में एक प्रस्ताव भी लाये थे । इसके लिये उन्होंने यह छूट भी दी थी कि अगर यह चाहें तो सारा हाउस एक मत से इसको पास करके भेजे कि बी0 आर0 ओ0 से इस काम को कराया जाये और जो काम आजकल नहीं हो रहा है, वह जल्दी से पूरा किया जाये । हमारे मुख्य मन्त्री जी बड़े कलाकार आदमी हैं । पहले तो एक बात बड़े जोर से शुरू करवा देते हैं फिर उसके बाद उसको दबा भी देते हैं । मेरा जिला

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

[श्री धीर पाल सिंह]

रोहतक है । मैं वहां से विधायक बनकर आया हूं । पिछले कई सालों से वहां पर पूरी बारिश नहीं हुई है । आज रोहतक में यह हाल हो गया है कि पानी का स्तर बहुत नीचे गिर गया है । इसी तरह से भिवानी की, महेन्द्रगढ़ की और रिवाड़ी की हालत है । बारिश की कमी की वजह से पानी का स्तर नीचे गिर गया है । इसका आप कोई न कोई हल निकालें । बारिश न होने की वजह से वहां पर पानी की बड़ी दिक्कत है, उसको हल करें । नेहरा साहब ने एक और काम किया । पश्चिमी यमुना नहर की कैपेसिटी 12000 क्यूसिकस से घटा कर 9,000 क्यूसिक्स कर दी है । यह हमारे साथ इनकी हमदर्दी है जबकि दूसरी ओर हमारे यहां पर पानी की कमी है । इनको करना तो यह चाहिये था कि यमुना के ताजेवाला हैड से पानी ज्यादा लें । कम से कम 5—6 जिलों को, जिनमें पानी की दिक्कत है, एक महीने में एक बार मुतवातिर पानी देना चाहिये ताकि वहां पर पानी की दिक्कत कुछ कम हो सके । अगर लोगों को यह पानी मिलेगा तो वहां पर रीचार्जिंग होगी । अगर पानी रीचार्ज होगा तो पानी की डिमांड कम होगी । लेकिन सरकार का इस बात की ओर कोई ध्यान ही नहीं है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे । एस0 वाई0 एल के बनाने के लिये न तो कोई धन ही रखा गया है और न ही पिछले अढ़ाई साल में इसके बनाने के लिये एक ईंट भी लगायी गयी है ।

श्री अध्यक्ष : पैसा तो सैंट्रल गवर्नमैंट ने देना है ।

श्री धीर पाल सिंह : वह तो ठीक है कि केन्द्र सरकार ने इसके लिये पैसा देना है लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वह भी तो सही है । इस बारे में कुछ न कुछ चर्चा तो होनी चाहिये थी । चर्चा करते हुए कम से कम इतना तो कहते कि केन्द्र सरकार ने इसके लिये इतना पैसा हमें दिया है । पिछले साल इसके लिये 40 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी लेकिन वह पैसा पता नहीं कहां गया कौन सी मशीनरी खरीदने पर वह पैसा खर्च किया गया या कहां पर खर्च कर दिया गया लेकिन नहर के निर्माण के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगायी गयी । उस नहर के न बनने से जो चैनल हरियाणा में बनी हुई है, वह ज्यादा बदतर होती जा रही है । उसमें पानी न छोड़ने की वजह से वह जगह-जगह टूटी पड़ी है । जिस कारण उस में पानी नहीं छोड़ा जा सकता । आने वाले समय में जितना उसको बनाने में खर्चा हुआ था, उतना ही तकरीबन उसकी रिपेयर पर खर्चा आएगा तब कहीं जाकर उस नहर में पानी छोड़ा जा सकेगा । अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी इस सदन में आश्वासन देने में बड़े तेज हैं । इन्होंने पिछले सशन में शायद यह आश्वासन दिया भी था कि मार्च के महीने में सभी टेलों पर पानी जाएगा, जोहड़ों में पानी भरा

जाएगा लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले ढाई सालों से किसी भी गांव की टेल तक पानी नहीं गया है । मैं नाम बता देता हूं ये पड़ताल करके देख लें । गांव [redacted] बदानी, बदाना छुड़ानी, लगरपुर, दुलेड़ा, बादली वा छारा वगैरह की हालत ऐसी ही है जिन की टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है । ऐसे आश्वासन मुख्य मन्त्री महोदय को नहीं देने चाहियें जो इम्पलीमैंट भी न हो सकें । हार कर लोगों ने यह मान लिया कि जब तक वर्तमान सरकार रहेगी, उन्हें पानी के दर्शन नहीं होंगे । अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जहां तक यमुना नहर की कपैसिटी का सवाल है, इसे बढ़ाया जाना चाहिये और लोगों को पूरा पानी मिलना चाहिये । लेकिन आज वहां पानी का स्तर गिर रहा है । आम आदमी की यह धारणा है और कहता है कि ताऊ गया, चौटाला गया, साथ ही बिजली भी गई । बिजली का न होना आम लोगों के लिये तो हानिकारक है लेकिन जिन लोगों ने महंगा बीज, महंगी खाद डाली है, उनको 10 जनवरी तक कोरवा नहीं मिला । गेहूं, जौ व सरसों की फसल बरबाद हो गई । लोगों ने भगवान से कृपा करने की दुहाई दी । भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी की । बरसात अच्छी हो गई और जो बैगानी की खेती थी, गेहूं की, चने व सरसों की खेती थी, वह अच्छी हो गई लेकिन इस सरकार का लोगों पर कोई एहसान नहीं है । चौधरी भजन लाल जी ने पीछे कहा था कि मैं भगवान को टेलीफोन कर दूंगा और बारिश हो जाएगी । भगवान ने उनके टेलीफोन पर मेहरबानी कर दी । (हंसी) आज लोग भगवान की अपार कृपा से खुश हैं लेकिन आज हालत यह है कि बिजली किसी भी गांव में नहीं मिल रही है । जो थोड़ी बहुत मिलती है, वह भी बहुत कम । बच्चों के पढ़ाई के दिन हैं, वे रात को 8 बजे खाना खाकर सो जाते हैं कि बिजली तो आनी ही नहीं । अध्यक्ष महोदय, आपका और हमारा जमाना और था जब तेल के दीए के नीचे भी पढ़ा जाता था लेकिन आज वह जमाना नहीं रहा । अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने मन बनाया हुआ है कि किसी भी गांव में बिजली नहीं देनी जिससे बच्चे पढ़ न सकें । इनका तो यही मतलब है कि ना होगा नौ मन तेल न राधा नाचेगी । अगर बिजली नहीं होगी तो न ही बच्चा पढ़ेगा और न ही कुछ बन सकेगा । अगर विद्यार्थी को बिजली मिल गई, वह पढ़ गया तो इस सरकार को झंझट पड़ जाएगा कि इनको नौकरियां कहां से देंगे । इनकी इसी धारणा के तहत विद्यार्थियों को बिजली नहीं मिल रही । स्पीकर सर, आम आदमी के लिए आज बिजली एक अत्यन्त आवश्यक भाग बन चुकी है । हमारा आज का समाज बिजली पर काफी हद तक निर्भर करता है । पहले वक्त में आटा, चक्की व दूध तक हाथ से ही निकाल लिया जाता था लेकिन आज हम सभी बिजली पर निर्भर करते हैं । दूध का मक्खन निकालने के लिये हाथ का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि बिजली नहीं मिलती और बच्चे दूध दही व मक्खन को तरसते रहते हैं । जब कटौती न काटी जाए

[श्री धीर पाल सिंह]

तो पशुओं को चारा कैसे दिया जा सकेगा क्योंकि यह सारा काम बिजली पर ही निर्भर करता है ? बिजली न होने के कारण लोगों को फिर दोबारा हाथ के सहारे को ही मानना पड़ा । लोग कहते हैं कि चौधरी देवी लाल जी का जमाना अच्छा था, जिस समय लोगों को गांवों में तो क्या, शहरों में भी 24 घंटे बिजली मिलती थी । मैं एक बात कहूंगा कि जो इन्होंने बिजली बोर्ड पर लाखों रुपये खर्च किए हैं वह किस लिए किए हैं ? अगस्त के महीने में बारिश में कुछ कमी आई और ये किसानों को बिजली नहीं दे पाए । इन्होंने लाखों रुपए बिजली बोर्ड पर थोपे । गांव गांव में हैड बिलों का बंटवारा हुआ क्योंकि बारिश नहीं हुई और भाखड़ा डैम का स्तर भी कम हो गया है इसलिये आपके गांव में बिजली नहीं आ रही है । मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1987 में चौधरी देवी लाल की सरकार बनने के बाद भगवान हमारे से नाराज हो गया था उस समय पूरा साल एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी थी । चाहे नारनौल हो, चाहे रिवाड़ी हो, भिवानी हो, रोहतक हो, या कुरुक्षेत्र हो, यानी हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव और शहर में एक सैकिंड के लिये बिजली नहीं गई जबकि इतना भंयकर सूखा था । चौधरी देवी लाल जी क्योंकि खेती से जुड़े थे और आम आदमी की गुरबत से जुड़े हुए थे इसलिये उन्होंने अपने समय बन्दोबस्त ठीक किए थे । जिस बिजली को आप बेच रहे हैं और उसके बंटवारे में भेद भाव कर रहे हैं, हमने ऐसा कभी नहीं किया था । आज थर्मल प्लांटस पर कोयला नहीं है जिसके अभाव से बिजली पैदा नहीं हो रही है । आपको इस बात के लिए चिन्ता होनी चाहिए । अगर आपके पांच में से चार यूनिट बन्द हो गए हैं तो ये आपकी अयोग्यता की वजह से हुए हैं । आप द्वारा एन0 टी0 पी0 सी0 को किश्त न देने की वजह से बिजली की कमी आई । उसके बाद क्या हुआ, मार्किटिंग बोर्ड से पैसा ले लिया और बिजली बोर्ड की तरह से आज उसको भी बिठा दिया । जहां पहले एक संस्था बैठी हुई थी, वहां एक और संस्था को बैठा दिया । इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है । कल को हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को पूरी सुविधाएं देंगे । (विघ्न) स्पीकर साहब, चौधरी ओम प्रकाश जी की धारणा यह है कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और जब तक आम किसान को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती । तो किसान को खुशहाल करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है । आज पानी और बिजली की कमी हो रही है, यह जिम्मेदारी आपकी है । अगर बिजली की किश्तों की अदायगी नहीं हो रही है तो इसके लिये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है । 5 अप्रैल 1991 को हमारी सरकार गई थी, उस समय 250 करोड़ रुपए का घाटा था लेकिन आज 1400 करोड़ रुपया का घाटा हो गया है । बिजली की दरें चार बार बढ़ चुकी हैं लेकिन बिजली फिर भी नहीं मिल रही है और उसके

बावजूद घाटा अधिक हो रहा है। इन लोगों ने चर्चा कर दी कि बिजली की चोरी हो रही है। यह बात तो हो सकती है कि कारखानों में बिजली की चोरी हो रही है लेकिन मुख्य मन्त्री ने बयान दे दिया कि गांव के लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आप और हम भी गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। गांव में बिजली न जाए और आरोप आप पर लगे यानी गांव के लोगों पर लगे कि वे बिजली चोरी कर रहे हैं, ठीक नहीं। स्पीकर साहब, जब से यह सरकार आई है, तब से गांव में बिजली की कभी भी चोरी नहीं हुई बल्कि चोरी तो ये खुद करवाते हैं। किसान और पिछड़े वर्ग के साथी बिजली न होने की वजह से शाम को सो जाते हैं और जब वे सुबह उठकर बटन दबाते हैं तो बिजली फिर गुल होती है। तो ये बताएं कि क्या वे सोए सोए बिजली की चोरी कर लेते हैं? इस सरकार के आरोप से वे लोग तिलमिलाते हैं। स्पीकर साहब, एक बुजुर्ग ने मुझे एक दर्दभरी कहानी बताई। (शोर)

श्री अध्यक्ष: जो फीडर बिल्कुल ही रूरल एरिया को बिजली फीड करते हैं, वहां कारखाने भी नहीं हैं, वहां जो लाईन लौसिज हैं, वह कैसे हैं?

श्री धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने पेपरों में यह बयान दागा कि गांव के लोग बिजली की चोरी करते हैं। (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी भी पेपर में ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

श्री धीर पाल सिंह: यह बात पेपर में आई है। आप पेपर उठा कर देखें। स्पीकर साहब, एक बुजुर्ग ने मुझ से कहा कि चौधरी देवी लाल जी कहां पर हैं। उस समय मैंने यह सोचा कि बुजुर्ग की पैंशन कट गई होगी .....(शोर)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, मेरी अर्ज है कि हमारी पार्टी के ज्यादा मैम्बर हैं इसलिये बोलने के लिए टाईम मैम्बर के हिसाब से दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: नेहरा साहब, टाईम तो मम्बर्ज के हिसाब से ही दिया जाएगा।

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूंगा कि हमारी पार्टी का यदि कोई मैम्बर बोलता है तो उसको बोलने के लिये केवल 15 मिनट का टाईम दिया जाता है जबकि हमारी संख्या ज्यादा है और इनकी पार्टी की संख्या कम है, फिर भी आप इनको बोलने के लिये 20—20 और 25—25 मिनट दे देते हैं। चौधरी सम्पत सिंह तो एक घंटा बोले हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारी पार्टी के मैम्बर्ज को बोलने के लिये भी समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री धीर पाल सिंह : नहीं जी, मैं पांच मिनट और लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं एक बुजुर्ग की कहानी सुना रहा था। उस बुजुर्ग ने मुझ से कहा कि चौधरी देवी लाल जी कहां हैं । मैंने सोचा उसकी पैंशन कट गई होगी इसलिये वह चौधरी देवी लाल जी को पूछ रहा है लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि चौधरी भजन लाल की सरकार की जो नीतियां हैं वे हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर रही हैं । मैंने उस बुजुर्ग से कहा कि यह सरकार आपको आर्थिक रूप से कैसे कमजोर कर रही है इस सरकार में ऐसा क्या दोष हो गया है । स्पीकर साहब, जिन किसानों ने बासमती की खेती की थी उनके बारे में मैंने और विपक्ष के नेता ने पिछली बार चर्चा करने की कोशिश की थी लेकिन हाउस के लीडर से हमारी बात बर्दाश्त नहीं हुई और हमें उठा कर हाउस से बाहर कर दिया गया था। स्पीकर साहब, हमें अपनी बातें कहने के लिये दो ही प्लेटफार्म हैं । या तो हम अपनी बात कहने के लिये लोगों के बीच में जाएं या विधान सभा में चर्चा करें। स्पीकर साहब, उस बुजुर्ग ने कहा कि क्या पाप हो गया, जिस किसान ने बासमती की खेती कर ली, चाहे वह किसान आपके गांव का है या किसी दूसरे गांव का है । मेरे हल्के के चार गांवों में बासमती की खेती होती है। हमारे क्षेत्र के साथ दिल्ली लगती है और वहां केवल एक नरेला की मंडी है । हरियाणा प्रदेश में जो भी बासमती का एरिया है, उन एरियाज में बासमती पैदा करने के लिये मंहगा खाद, मंहगा डीजल और मंहगी कीटनाशक दवाईयां प्रयोग की जाती हैं । जिस कानून के तहत सर छोटू राम ने किसानों को अधिकार दिया था कि किसान भाई जिस दिन मंडी में अपना अनाज ले कर जाएगा, उसी दिन उसकी बोली होगी लेकिन उसकी अवहेलना की गई है और किसान ट्रैक्टर की ट्राली में अपनी बासमती ले कर चाहे नरेला की मंडी में गया और चाहे हरियाणा की दूसरी मंडी में गया, एक एक हफ्ते तक उसकी बोली नहीं हुई । बोली होने के बाद किसान भाई को बासमती का भाव केवल 600 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया जबकि चौधरी देवी लाल जी के समय में बासमती का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल था। वह भाव घट कर 600 रुपए हो गया यानि किसान भाई को सीधा 1400 रुपए का घाटा हो गया । वह बुजुर्ग किसान को आर्थिक रूप से कमजोर करने की यह बात कह रहा था । स्पीकर साहब, एक तरफ तो वर्तमान सरकार किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ स्टेट में बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं रहा । उस बुजुर्ग ने जो मान सम्मान की बात कही, इसलिये यह दर्द भरी बात है कि गांवों में बिजली आती ही नहीं। किसान भाई को दिन में

बिजली का आसरा था और फसल में पहला पानी लगना था, वह खेत में गया और सारा दिन बैठा रहा। बिजली न आने पर डोलियों पर मिट्टी लगाई और शाम तक बैठा रहा लेकिन बिजली नहीं आई। बिजली न आने पर लड़का घर आ कर अपने बाप को कहता है कि पिता जी, आज दिन में बिजली नहीं आई, आप शाम को खेत में चले जाना। मैं लट्टू को ऑन करके आया हूं जब बिजली आएगी तो आपको पता लग जाएगा। आप स्टार्टर दबा देना पानी चल जाएगा। आपको सिर्फ नाके नाके फेरने हैं। बुजुर्ग शाम को खेत में चला जाता है। जाड़े का टाईम था, वह बुजुर्ग रोटी खा कर रजाई ओढ़ कर सारी रात लट्टू की तरफ देखता रहा, ईब आवै, ईब आवै। लट्टू जा कर सुबह 5.45 बजे जलता है। वह सारी रात का दुखी था, कहने लगा मेरी सुसरी की, मैं सारी रात बैठा देखता रहा ईब आई है। उसके बाद उस बुजुर्ग के लड़के की पत्नी चाय ले कर सुसरे के लिये आई, उसने सोचा होगा कि पिता जी ने सारी रात पानी दिया होगा दुखी हुए होंगे। जब उसने बुजुर्ग की बात सुनी तो वह कोठड़े के बाहर ठिठक कर रुक जाती है। बुजुर्ग स्टार्टर दबाने के लिये जाता है तो फिर बिजली गायब हो जाती है। आपकी एफीसिऐंसी यह है तो उस बुजुर्ग से बात बर्दाशत नहीं हुई वह कहने लगा तनै जाना ही था तो आई खसम रोने के लिये थी। मैं देहाती भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। उसकी दुखभरी कहानी आपको बता रहा हूं। आज हमारे प्रदेश में बड़े बूढ़ों को इस ढंग से अपमानित होना पड़ रहा है। हमारी बहन हमारी प्रदेश सहकारिता मन्त्री इस समय हाउस में नहीं हैं। वे बहुत भले परिवार से हैं मैं उनकी इनएफिसिऐंसी की चर्चा नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब 1987 में कांग्रेस की सरकार गई थी तो उस समय गन्ने का भाव भी 24 रुपये क्विंटल था और जब हमारी सरकार 5 अप्रैल को आई तो उस समय हमने किसानों को 49 रुपये का गन्ने का भाव दिया। यह रिकार्ड की बात है। सारी सहकारी मिलें आपके पास हैं, आप उनका रिकार्ड देख सकते हैं। आज आपकी सरकार के रहते हुए और गन्ने का भाव कम रहते हुए किसान ने गन्ना बोना ही बन्द कर दिया है। आपको अपनी मिलें चलाने के लिये उत्तर प्रदेश से गन्ना लेना पड़ता है हमने अपने समय में जीन्द, शाहबाद, पानीपत मिलों की 150 गुणा कैपिसिटी बढ़ाई थी।

श्री अध्यक्ष : अब आपका समय खत्म हो गया, कृपया बैठ जाय।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूं। स्पीकर साहब, आज प्रदेश के अन्दर से गन्ना लोप होता जा रहा है। जब चौधरी ओम प्रकाश जी की सरकार थी तो उस समय गन्ने की मिलें मई और जून तक चलती

[श्री धीर पाल सिंह]

थी जबकि आज मिलें जनवरी और फरवरी में बंद हो जाती हैं। आज की सरकार किसानों से खिलवाड़ कर रही है। यह सरकार अपने किसानों को तो 55—56 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव देती है जबकि बाहर से जो गन्ना मंगाया जाता है उस गन्ने का भाव 71 रुपये क्विंटल दिया जाता है। इसका कारण यह है कि अब गन्ना यहां पर आपकी अयोग्यता के कारण किसान नहीं लगा रहे, जिस कारण आपको मिलें चलाने के लिये गन्ना बाहर से लाना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक द्वारा 50—50 हजार रुपये के कर्जे किसानों को दिए जा रहे हैं, उनको देना बन्द किया जाये। अगर आप बैंकिंग सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं तो बहन जी इस तरह के कर्जों को बन्द करवा दें। इस पर आप पाबन्दी लगाइए क्योंकि यह सारे के सारे कर्जे मिसयुटीलाईज हो रहे हैं, कहीं इनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। भूमिहीन लोगों को यह कर्जा दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय प्रदेश की जनता पर एक मेहरबानी कर दें और इस मामले की जांच करवा लें कि 50 हजार रुपये के कर्जे में से 10—15 हजार रुपये तक बीच का आदमी खा जाता है क्योंकि उस भोले भाई को यह पता है कि भूमिहीन यह आदमी है, कर्जा उसने देना नहीं, कभी चौधरी देवी लाल जी की सरकार आ गई तो फिर कर्जा माफ हो जाएगा। (घंटी)

श्री अध्यक्ष : बैठिए धीरपाल जी, रामभजन जी अब आप बोलिए।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ अभी एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्रदेश के लड़के और लड़कियां साऊथ में टैक्नीकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हजारों की तादाद में जाते हैं और मैडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सीमा निर्धारित की है वह 1 लाख, 51 हजार या समथिंग है। वह तो लोगों को देनी ही पड़ती है इसके इलावा चन्दा देते हैं। इसके अलावा रहने के लिए तथा खाने-पीने पर जो खर्च करना पड़ता है, वह अलग है और आने जाने का खर्च अलग से लोगों को करना पड़ता है। जो लोग टैक्नीकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिये दूसरे प्रान्तों में जाते हैं, उसके लिये 50—50 हजार, एक एक लाख रुपया उनका खर्च हो जाता है। इसलिये स्पीकर सर, मैं यह चाहता हूं कि हमारा जो पैसा इस प्रकार से स्टेट से बाहर जा रहा है उसी पैसे को यहां पर लगा कर ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को बाहर शिक्षा के लिये न जाना पड़े। उसी

पैसे से मैडिकल कालेज और इन्जीनियरिंग कालेज हरियाणा में ही खोल दिए जाएं और अपने प्रान्त के बच्चों का भविष्य यहीं पर सुरक्षित किया जाए । स्टेट से बाहर जाने पर लोगों को हीनभावना का भी शिकार होना पड़ता है । एक बार वहां पर दंगे भी हो गए थे, हमारे बेटे और बेटियों की जान को जो खतरा हो सकता है उससे भी बचा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिये अब आप अपनी जगह पर बैठें ।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, अभी मैं कुछ बातें और कहना चाहता था परन्तु आपकी इजाजत नहीं मिल रही है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री राम भजन अग्रवाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण पर जो आंकड़े दिए हैं वास्तव में कुल मिला कर जनता को और हाउस को गुमराह करने के लिए दिए हैं । (विघ्न) स्पीकर साहब, जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी हाउस में बैठे हैं और ये कानून व्यवस्था के पालक भी हैं । सारी स्टेट के अन्दर कानून और व्यवस्था का बुरा हाल है । चोरी, डकैती तथा रेप की घटनाएं प्रदेश के अन्दर हो रही हैं जिन के बारे में छतर सिंह चौहान ने विस्तार से बताया है । अभी हाल ही में लोहारु की घटना हुई । औरतों और आदमियों को पकड़ कर अब तक बन्दी बना रखा है, उनका क्या दोष है ? (विघ्न) कुछ ही दिनों में मुख्य मन्त्री जी दादरी जाने वाले हैं । दादरी को आज पुलिस छावनी बना रखा है । पुलिस द्वारा लोगों को, दर्जियों को पकड़ा जा रहा है और तंग किया जा रहा है । उनसे पूछा जाता है कि क्या कोई काला झण्डा बना रहा है, कहीं कोई काली पैंट तो नहीं बना रहा, कोई काले कुर्तों की सिलाई करने वाला तो नहीं है ? स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस का काम यही रह गया है कि जहां मुख्य मन्त्री जी का जलसा हो, सारी स्टेट और पुलिस को वहां पर लगा दिया जाए ? पुलिस लोगों के साथ ज्यादतियां करे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ । जलसे पहले होते रहे हैं लेकिन पुलिस का इतना इन्तजाम कभी नहीं किया गया । कानून व्यवस्था की बात बहुत ही चिन्ता की बात है ।

श्री धर्म पाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मैं माननीय सभी को बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मैं दादरी से हो कर आया हूं, वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है । वहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल

[श्री धर्म पाल सिंह]

ठीक है। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी 6 तारीख को वहां पर जाने वाले हैं और बड़ा भारी जलसा कांग्रेस पार्टी का वहां पर होने वाला है, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है।

श्री राम भजन अग्रवाल : स्पीकर साहब, यह अपने इलाके में दौरा करने के लिए जरूर गए होंगे और इनको अच्छी तरह से पता है कि गांवों के लोग तो इनको गांवों में घुसने नहीं देते हैं। आज यह बात इसलिये कह रहे हैं कि कम से कम इनको गाड़ी मिल जाएगी। यह अलग बात है कि कौन सी गाड़ी मिलेगी। झंडी वाली कार मिलेगी या कौन सी कार मिलेगी, यह तो समय ही बताएगा कि कौन सी मिलेगी। (विघ्न) लेकिन मिलेगी जरूर।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई का सवाल है मेरे ऐरिया में पानी नाम की कोई चीज नहीं है। डीसिल्टिंग के बारे में नेहरा जी ने कहा कि डी-सिल्टिंग के लिये वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है, कोई आदमी मकान बनाने के लिये लोन ले तो बात समझ में आती है लेकिन कोई व्यक्ति मकान की मुरम्मत के लिये और रंग रोगन के लिये कर्जा ले, यह बात समझ में नहीं आती। आज स्टेट गवर्नमैंट की हालत यह हो रही है कि नहरों की सफाई करवाने के लिये भी यह बैंकों से कर्जा ले रही है। नहरों की सफाई करवाने तक के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है और कर्जा ले कर सरकार नहरों की सफाई करवाने जा रही है। मकान बनाने के लिये कर्जा लें तो बात समझ में आती है लेकिन उसकी सफेदी करने के लिये भी कर्जा लें तो इस तरह से कैसे प्रशासन चलेगा ? अध्यक्ष महोदय जहां तक नहरों की डी-सिल्टिंग करने का सवाल है, वह भी नहीं हो रही। मैं तो यह कहता हूं कि हमारे प्रान्त में सरकार बराबर का पानी भी नहीं दे पा रही है, टेलों तक पानी नहीं जा रहा है। एस0 वाई0 एल0 की बात हमारी सरकार कहती है ? कहीं पर तो महीने में 22–22 दिन पानी देती है और कहीं पर 3—3 दिन ही आता है। जब हमारी सरकार स्टेट के अन्दर की बराबरी (भेदभाव) को दूर नहीं कर सकती, तो एस0 वाई0 एल0 की प्रोब्लम को कैसे दूर कर सकेगी, यह बहुत दूर की बात है। अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की हालत यह है कि आज देहातों में पीने का पानी ही नहीं है। महीनों महीनों तक गांव में पानी नहीं पहुंचता, वाटर वर्क्स की सप्लाई का भी बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, भिवानी शहर में पीने के पानी में सीवरेज का पानी आता है जिस के कारण लोगों को पीलिया हो गया है और कई कैजुअलैटीज भी हो गई हैं। फिल्टर्ड वाटर कहीं पर भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो पीने के पानी की लाईनें हैं वह सीवरेज की लाईनों में से गुजरती हैं। मैंने पिछली बार भी मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में यह बात लाई थी कि इस कारण से बड़ी दुर्घटना होने वाली है और उन्होंने

कहा था कि हम 2-4 दिन में यह दिक्कत दूर कर देंगे, इसका इन्तजाम कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं इनके 2-4 दिन कितने लम्बे होते हैं ? आज भी हमारे शहर के अन्दर पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। अगर आता भी है तो वह सीवरेज मिश्रित गन्दा पानी आता है। सीवरेज मिश्रित पानी पीकर लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री बीरेन्द्र सिंह पदासीन हुए।)** चेयरमैन साहब, जहां तक पीने के पानी का सवाल है, इस बारे में मैंने एक योजना दी थी। हमारे पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब वहां पर गए थे। मैंने उनसे कहा था कि जहां पर मीठा पानी है, वहां ट्यूबवैल्ज लगवाकर, ट्यूबवैल ओरिएंटिड स्कीम बनाई जाए। ट्यूबवैल के पानी से सप्लाई लाईनों को जोड़ दिया जाए, लेकिन आज तक उस बारे में कुछ नहीं किया गया और लोगों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। चेयरमैन साहब, इसके लिए सरकार की पालिसी है लेकिन मेरे इलाके में उस पालिसी को पता नहीं क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ? मेरे हल्के में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां ट्यूबवैल लगाकर ऐसी व्यवस्था की गई हो। पता नहीं ऐसा करने में सरकार क्यों असमर्थ है ?

चेयरमैन साहब, आज बिजली की क्या हालत है ? बिजली की सारी स्टेट में बुरी हालत है। पहले तो ट्यूबवैल्ज को बिजली मिलती ही नहीं है, अगर मिलती भी है तो वहां पर इतने ब्रेक डाऊन हैं कि वह न मिलने के बराबर है क्योंकि पानी ऊपर ही नहीं आता। चेयरमैन साहब, बिजली की तारें टूट रही हैं, जिसकी वजह से भिवानी की गऊशाला में दो गाएं मर गई हैं और जिसका मुआवजा बिजली विभाग नहीं दे रहा है। बिजली की सही व्यवस्था अति आवश्यक है।

अब बिजली के बिलों के बारे में, मैं आपको बताता हूं। हमारे ए0सी0 चौधरी जी पिछले दिनों भिवानी गए थे और वायदा करके आए थे कि बिल सिस्टम जल्दी ठीक करवा दूंगा। अगली दफा फिर आ गए और वही बातें कहते रहे ताकि उपभोक्ता को विश्वास रहे कि बिजली दे रहे हैं। चेयरमैन साहब, असल में होता क्या है, आज बिजली के बिल घर बैठे ही मीटर रीडर, बिना मीटर रीडिंग नोट किए भेज देता है। साधारण ग्रामीणों को जिनके दो प्वायंट भी नहीं हैं, हजारों-हजारों के बिजली के बिल आ रहे हैं। चेयरमैन साहब, बिजली के बिलों का सिलसिला बड़ा खराब हो रहा है, जिसको सुधारने की बड़ी आवश्यकता है।

जहां तक पानीपत थर्मल प्लांट की बात है, हमारी कमेटी वहां पर गई थी। हमने देखा कि पांच थर्मल प्लांटस की जगह केवल दो थर्मल प्लांटस ही चल रहे थे। अगर किसी टैक्नीकल फाल्ट की वजह से थर्मल प्लांट बंद हों तो अलग बात है लेकिन पता चला है कि सरकार के पास, कोयला खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है और जो कोयला खरीदा जाता है, वह जी ग्रेड क्वालिटी का घटिया कोयला होता है। उसमें तीस चालीस परसैन्ट पत्थर आता है क्योंकि जिस सरकार की कोई साख न हो, उसे

[श्री राम भजन अग्रवाल]

ऐसा ही माल मिलता है । यही कारण है कि पावर हाऊस बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं । सरकार के पास कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं है । इसके अलावा जो थर्मल प्लांट की मशीनें हैं, वे भी खराब पड़ी हुई हैं । मुझे बताया गया कि इन मशीनों की मुरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जबकि सरकार यह दबाव डाल रही है कि इन थर्मल प्लांटस को चालू रखो । सरकार को यह नहीं पता कि जब तक इनको रैस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये लगातार कैसे चलेंगे ? चेयरमैन सर, स्टेट में बिजली का बहुत अभाव है । सरकार को चाहिए कि सरकार इनकी उचित व्यवस्था करे । एक तरफ तो सरकार और थर्मल प्लांट्स लगाने की बात कर रही है लेकिन दूसरी तरफ पुराने थर्मल प्लांट्स की मुरम्मत करने में ध्यान नहीं दे रही है । सरकार को पहले इन प्लांट्स को ठीक करना चाहिए । मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम नयी सड़कें बाद में बनायेंगे, पहले पुरानी सड़कों की मुरम्मत की जाएगी । उसी तरह से सरकार को नये थर्मल प्लांट्स लगाने की बजाय पुराने थर्मल प्लांट्स को ही ठीक करना चाहिए और उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए । पानीपत थर्मल प्लांट की पांच यूनिट्स हैं लेकिन उसमें एक या दो यूनिट्स ही चलते हैं । मेरा सरकार से आग्रह है कि जो पुरानी यूनिट्स हैं, पहले उनको ही ठीक किया जाए ।

जहां तक सड़कों का सवाल है, सड़क नाम की कोई चीज हरियाणा में नहीं है । सड़कों की रिपेयर भी पता नहीं कैसे करते हैं । सड़कों पर तेल डालकर पत्थर डाल दिया जाता है जो एक बारिश के बाद या बगैर बारिश के ही बह जाता है और सड़कें वैसी की वैसी रहती हैं । रिपेयर नाम की कोई चीज ही नहीं है । अगर कहीं पर रिपेयर हुई है तो वह मामूली हुई है । हमारे यहां बास के पास, दो या तीन मील की एक सड़क का टुकड़ा बनने से रह गया था, 6 महीने हो गए वह ठीक नहीं हो पाया है । भारत सरकार से जिन सड़कों के लिए, नेशनल हाई वे के लिए पैसा आता है, उनको तो डांगी साहब भी कह देते हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, लेकिन जो प्रांत की सड़कें हैं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, उनकी मुरम्मत नहीं हो रही है । इनकी मुरम्मत के लिए महीनों व कभी कभी तो साल लग जाते हैं, थोड़ा काम भी नहीं हो पाता ।

चेयरमैन सर, जहां तक शिक्षा का सवाल है । शिक्षा के क्षेत्र में पहले तो स्कूल ही नहीं हैं, और अगर स्कूल हैं भी तो स्टाफ नहीं है । स्टाफ की इतनी कमी है कि दो सौ बच्चों पर एक टीचर है । लड़कियों के लिए तो स्कूलों का इतना अभाव है कि उनको तीन तीन या चार चार मील तक पैदल जाना पड़ता है । कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया है । लड़कियों को इतनी दूर पैदल इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि रोडवेज की बसों का बहुत बुरा हाल है । जो भिवानी इलाके में लिंक

रोड्ड पर बसें चलती थीं, वे बिल्कुल बंद कर दी गयी हैं सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो ? इस के साथ साथ मेरा सरकार से आग्रह है कि स्कूलों को अपग्रेड किया जाए और शिक्षा का जो स्तर है, उसको ऊंचा उठाया जाए। शिक्षा के स्तर की बात यह है कि भिवानी में एक एस0डी0 हाई स्कूल था, जिसके बारे में मैंने पिछले सैशन में भी कहा था । उस स्कूल पर किसी व्यक्ति विशेष ने कब्जा कर रखा है । सरकार के नोटिस में यह बात लायी जा चुकी है कि कोई व्यक्ति-विशेष इस स्कूल से चालीस या पचास हजार रुपये का फायदा उठा रहा है उसने सरकार को लिखा हुआ है कि उसको इस स्कूल के लिए ग्रांट नहीं चाहिए । कल भी इस बारे में चर्चा हुई थी कि प्राईवेट स्कूल वाले विद्यार्थियों से चालीस या पचास हजार रुपये ले रहे हैं । हमने इस सिलसिले में ऐजीटेशन भी किया था और मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी तथा इनसे मिला भी था लेकिन जब कोई अच्छा काम करना होता है तो लोग उसको करने नहीं देते । लोग कह देते हैं कि विकास पार्टी वाले वैसे ही कह रहे हैं । मैं उस व्यक्ति के बारे में बता देता हूं जिसने इस स्कूल पर कब्जा किया हुआ है । ये व्यक्ति पुराने शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं । जब हमने इस स्कूल को ठीक करने के लिए कहा तो केवल एक नारा देकर मुख्यमंत्री जी को चुप करा दिया कि यह जनता का सवाल नहीं है, यह विद्यार्थियों का सवाल नहीं है । विकास पार्टी के कुछ विधायकों का काम है । इस पार्टी के कुछ विधायक इसमें लगे हुए हैं । फिर हमने इसके बारे में बोलना ही बंद कर दिया और देख रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी कितनी जल्दी इस व्यवस्था को ठीक करते हैं ।

चेयरमैन साहब, अब मैं बुढ़ापा पेंशन के बारे में कहूंगा । बुढ़ापा पैंशन के लिए अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो लोगों को तंग करने की क्या जरूरत है ? गुप्ता जी का खजाना भरा रहना चाहिए लेकिन बूढ़ों को तंग करने की क्या जरूरत है ? अगस्त महीने से बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा रही है । (घंटी) चेयरमैन साहब नये विधायकों को आप बोलने का चांस दीजिए । हमारे भिवानी जिले के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है । **(इस समय श्री उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)**

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के ऐड्रेस में व्यापारियों का जिक्र किया गया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई । बैरियर हटाए जा रहे हैं, यह भी अच्छी बात है । छोटे व्यापारी को सेल टैक्स में पांच लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान किया जा रहा है, यह भी बहुत अच्छी बात है । उपाध्यक्ष महोदय लेकिन एक बात संतोषजनक नहीं है जिस बारे मैंने पिछले सैशन में भी सुझाव दिया था कि सेल टैक्स के एडहॉक बेसिज पर 3-4 स्लैब बना दिए जाएं जैसे "ए" ग्रेड "बी" ग्रेड । सेल्ज टैक्स की सीमा निर्धारित कर दी जाए, जैसे उस व्यापारी से 5 हजार रुपए, इससे 10 हजार रुपए या 50 हजार रुपए सालाना लेंगे ताकि स्टेट को रेवेन्यू भी ज्यादा आए और व्यापारी भी सुखी रहे, इंसपैक्टरी राज की तलवार व्यापारी पर नहीं लटकी रहनी चाहिए ।

[श्री राम भजन अग्रवाल]

लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है । जो टैक्स आता है, वह अधिकारियों की जेबों में नहीं जाना चाहिए । मैं यह चाहता हूं कि रेवेन्यू सीधा स्टेट के खजाने में जाए लेकिन बीच में अधिकारियों की जेबों में रह जाता है । जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, वह अधिकारियों की तनख्वाहों पर खर्च हो जाता है तो स्टेट का विकास कहां से होगा ? सरकार इस ओर विशेष ध्यान देवे । व्यापारियों से तो पैसा लिया जाता है लेकिन अगर सरकार के खजाने में पहुंचे तो मुझे आशा है कि गुप्ता जी का खजाना उसे चारों तरफ फैला देगा । व्यापारी आपको टैक्स देना चाहता है । राजस्व का पूरा सदुपयोग हो तो विकास बहुत जल्दी हो सकता है और जनता जैसे चाहे, वैसे हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में अभी नेहरा साहब ने बताया है कि जहां पर नहरी पानी नहीं लगता, वहां गिरदावरी नहीं होगी । मैं कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में, मेरी कांस्टीचुऐन्सी में ट्यूबवैल ओरिऐन्टिड एरिया है और ट्यूबवैलज का पानी खेतों में लगता है लेकिन इसके बावजूद नहरी पानी का मालिया लिया जा रहा है । ऐसा प्रावधान बिल्कुल ठीक नहीं है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहन करतार देवी जी के यहां रविदास मन्दिर का जिक्र आया था । चौहान साहब ने पूरी डिटेल में उस पर कब्जे के बारे में बताया था । यह एक बड़ा भारी अन्याय है । बहन जी ने उस बारे में यह कहा है कि वहां पर तो जंगल है, और कुछ नहीं है । मैं तो यह कहता हूं कि यह सब कुछ उनके समर्थकों या कृपापात्रों की वजह से ही हुआ है ।

ला एंड आर्डर के बारे में मुख्य मन्त्री जी बात तो करते हैं लेकिन हालत खराब है । उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में चाहे किसी आदरणीय मन्त्री का पुत्र कोई गल्त काम करे या फिर मुख्य मन्त्री का पुत्र कोई गल्त काम करे, वह तो गल्त ही है । यह तो पुराना इतिहास शुरू से ही रहा है कि ऐसे लोगों के पुत्र ही खो के छोड़ेंगे । (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मन्त्रियों के पुत्रों को पुलिस होती है तो वह ही सरकार होती है । वर्दी के अन्दर एक सिपाही जो होता है, वह सरकार ही है । एक मंत्री का पुत्र पुलिस वालों की वर्दियां फाड़े और फिर पुलिस के ऊपर प्रहार करे तो इससे जनता को तो मार्गदर्शन मिलेगा ही । अगर मंत्रियों के बेटे ऐसा करेंगे तो फिर जनता तो हाथ उठाने के लिये मजबूर हो जाएगी । बस मैं इतना कहता हुआ और आपका समय देने के लिए धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं ।

श्री सुरजीत कुमार धीमान (नारायणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर

एड्रैस पर बोलते हुए बहुत थोड़ा सा ही समय लूंगा । आज के दिन को मैं बड़ा ही शुभ समझता हूं क्योंकि हमें 40 साल से ज्यादा समय के बाद 27 परसैंट आरक्षण मिला है जो हरियाणा सरकार ने फौरन लागू कर दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी 27 परसैंट आरक्षण के बारे में कुछ कहूंगा । यह आरक्षण हमारे यहां पर आंसू पोंछने के लिये 27 परसैंट दिया गया है । देश के अन्दर बैकवर्ड क्लासिज का 52 परसैंट हिस्सा बनता है । हम तो यह कहते हैं कि हमें हमारा पूरा हिस्सा दिया जाये । आज भी इन्होंने मजबूरी में 27 परसैंट हिस्सा हमारे गले मढ़ दिया है । लोग बहुजन पार्टी की बहुत बातें करते हैं । हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने भी जैसाकि आज न्यूज पेपर में आया है, उन्होंने भी हमारी पार्टी को एक खतरनाक पार्टी कहा है । ऐसी कोई बात नहीं है । हम तो यह कहते हैं कि हमें हमारा हिस्सा मिले और ये मुख्य मंत्री फार ऐवर मुख्य मंत्री बने रहें, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है । इस 27 परसैंट आरक्षण की जगह हमें पूरा हिस्सा मिले और विधान सभा में भी 27 परसैंट आरक्षण मिलना चाहिये । यह आरक्षण तो बहुत पहले से लागू होना चाहिये था । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनरल कास्ट, बैकवर्ड क्लासिज, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राईब्ज अगर सरकार ने न बनाये होते तो हमें कोई दुःख न था । लेकिन आज जब बने हुए हैं तो सब को हिस्सा तो पूरा मिलना ही चाहिये । यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद ।

मास्टर अजमत खां (हथीन) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 12.00 बजे | जो आपने मुझे बोलने का टाईम दिया । इस समय यहां पर गवर्नर एड्रैस पर बहस चल रही है । इसमें जितनी बातें कही गई हैं, देश के बारे में, देश के जवानों के बारे में और देश की सरकार के बारे में कि किस तरह से देश के सिर को ऊंचा किया गया है । किस तरह से आतंकवाद की गतिविधियों को रोका गया है, इसके लिये सैन्टर गवर्नमैंट बधाई की पात्र है, बधाई की मुस्तहिक है । इस सब का यहां पर जिकर आना जरूरी था । हां, एक बात यह कि चाहे हमें कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, कितनी ही परेशानियां क्यों न सहनी पड़ें, हम भूखे भी रहें तो हमें कोई परवाह नहीं है लेकिन हमें अपने देश के गौरव को दुनिया के सामने बनाये रखना है । अगर हमारे देश का सिर नीचे झुक जाएगा तो फिर हालात और बिगड़ जाएंगे । जिस देश का सिर झुक जाता है, उस देश की इज्जत नहीं रहा करती । इस सम्बन्ध में जो भी गवर्नर ऐड्रैस में कहा गया है, उसके लिये मैं इतना ही कहूंगा कि इन सभी बातों का जिकर आना जरूरी था । लेकिन इसके साथ-साथ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो यहां हाउस के अन्दर कही गयी हैं कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है । डिप्टी स्पीकर साहब, यह सही बात है कि कोई भी सरकार केवल एक दिन में कोई चमत्कार नहीं कर सकती । सुधार की तरफ अगर सरकार के कदम हों तो उन्हें सही माना जाता है । बेगार की तरफ अगर सरकार के कदम होते हैं तो उसको गलत माना जाता है । सरकार को धन के साधन जुटाने होते हैं । बगैर

[मास्टर अजमेर खां]

पैसे के कोई काम नहीं हो सकता । सरकार ने आते ही कुछ ऐसे काम किये, जसे कर्जे माफ करना, इससे धन की कमी आई है । हमारे से पहले चौधरी देवी लाल जी की सरकार आई थी, उन्होंने आते ही कर्जे माफ किये और हमारी सरकार ने भी किये । मैं कहना चाहता हूं कि बैंकों के कर्जे माफ करने से लोगों को राहत तो अवश्य मिली है, लेकिन इससे सरकार के दूसरे कामों पर असर अवश्य पड़ा है । सरकारी खजाने पर भी इसका असर पड़ा है । हमारी सरकार आई । डिप्टी स्पीकर साहब, राजनीति के अन्दर लुभावने नारे दिये जाते हैं । हमारी सरकार ने भी दिये । राजनीति में लुभावने नारे देकर के अपनी सरकार बनाने की कोशिश की जाती है । यह परम्परा शुरू हुई हमारे साथियों की तरफ से, और वह हम तक भी पहुंची । हम लोगों ने भी उनके कर्जों पर सूद माफ किया जिसकी वजह से सरकारी बजट पर काफी असर पड़ा ।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पन्शन की स्कीम भी बनी, उसके तहत 65 साला लोगों को पैन्शन दी गई । उसमें कुछ सही हुआ, कुछ गल्त हुआ, फिर 60 साला पैन्शन की उमर कर दी गई । 60 साला पैन्शन की उमर करने के बाद जो हकदार थे, वे फिर रह गये । चाहिये तो यह था कि जिन लोगों को पैन्शन आलरेडी मिल रही है, उनको ही बेरीफाई कर लेते और अगर नये सिरे से पैन्शन देनी थी तो उनके सर्टीफिकेट लिये जाते, तब 60 साल की पैन्शन की बात की जाती लेकिन आज कुछ ऐसे लोगों को पैन्शन मिल गई जो हकदार नहीं और हकदार जो थे वे रह गये लोगों के दिलों में बेइत्मिनानी पैदा हुई और जिन हकदारों को पन्शन नहीं मिली वह बूढ़े हमारे सामने कर दिये गये, वे हमें कोस रहे हैं । ऐसा हर जिला और हर जगह पर हुआ कि कुछ हकदार रह गये और गैर-हकदारों को पैंशन मिल गई ।

डिप्टी स्पीकर महोदय, इसके साथ-साथ मैं बैरियर्ज के बारे में भी कुछ कहूंगा । यहां पर बैरियर्ज समाप्त करने की बात आई । इससे लोगों को फायदा होगा लेकिन टैक्स की आमदनी को भी हमें ध्यान में रखना होगा । इसका हमें सोचना होगा और आपको इसके लिये साधन भी जुटाने होंगे । अगर इसमें जरा भी ढील दी गई तो हम यह चौकसी सही मायनों में नहीं कर पाएंगे । एक बात और यहां पर आई कि हमें हर वर्ग के लोगों को न्याय देना चाहिये । सामाजिक न्याय लोगों को मिलना चाहिये । लोगों की जरूरी बुनियादी बातों की ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये । पानी की सहूलियत, बिजली की सहूलियत व दूसरी रोजमर्रा की जरूरत की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और खासतौर पर कमजोर तबके के जो लोग हैं उनको हर जगह पर आरक्षण के लिहाज से नौकरियां देते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन माइनारिटी की तरफ भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये । मेरे पास

सारी फिगर्ज हैं, मैं मिसाल के तौर पर बता देता हूं कि सन् 1982 से लेकर के 1994 तक हैफड में लगभग 600 आदमियों की भर्ती हुई । आप लिस्ट निकलवा कर देख लीजियेगा, हमारे पास सारा रिकार्ड मौजूद है । 80 व्यक्ति बैकवर्ड और एस0सी0 के लिए गये और माइनारिटी में से केवल तीन आदमी ही लिये गये । उनमें भी एक आदमी जो अलीगढ़ का है, उसमें भर्ती हुआ । यू0पी0 और बिहार के लोग मौजूद हैं । इसी प्रकार 29 आदमी चण्डीगढ़ से, पंजाब से, अमृतसर से, मौजूद हैं लेकिन अगर कोई नहीं है तो हरियाणा की माइनारिटी कम्यूनिटी का नहीं है । कोई मेरा भाई किसी बात को उलट न समझ बैठे, क्योंकि हम ऐसी कोई बात यहां नहीं कहना चाहते । जबान को बन्द ही रखते हैं मगर देखकर दिल में दुख जरूर है । इसी तरह से पुलिस विभाग में 87 से 91 तक 10 हजार 800 तक की भर्ती हुई है। मेरे सवाल में तादाद जरूर दी गई है परन्तु नाम नहीं दिया गया । लेकिन हमारे इलाके के अन्दर माइनोरिटी के लोग पिछले चार सालों में भरती जरूर हुए परन्तु कितने, एक प्रतिशत भी नहीं, लगभग 30 लड़के। लोग कहते हैं कि यह उस सरकार ने किया या फलां सरकार ने किया । मैं कहता हूं कि यह किस सरकार ने किया ? मैं पूछना चाहता हूं कि 1987 से 1991 तक किस की सरकार थी और 1992 से मार्च 1994 तक किस की सरकार आई है ? तो इसमें सभी सरकारें हैं, मैं किसी एक आदमी या पार्टी को नहीं कहता । जो आदमी माइनोरिटी के लिए जोर शोर से कहते हैं, वे जरा देख लें कि उनके अपने अपने जमाने में क्या क्या हुआ है। आज मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि हमारी वैलफेयर स्टेट है इसलिए हर एक को अपना अपना हक मिलना चाहिए । नौकरियों में जात-बिरादरी के जो लड़के पीछे रह गए हैं, उनका खास तौर से ध्यान रखा जाए । मजहब की बिनाह पर किसी को नौकरी न दी जावे अधिक कमजोरी की बुनियाद पर तो दी जाए । जो लोग ज्यादा कमजोर हैं उनको थोड़ा सा अधिक भाग दिया जाए । जाति बिरादी बुरी बात है । मैं तो यह कहता हूं कि जात-बिरादरी के नाम पर यह बात खत्म हो । यह जो बहुजन समाज पार्टी है, इसके बारे में हमारे सी0एस0 साहब का ब्यान आया था । पहले तो हम धर्म पर बंट रहे थे और अब जाति पर बंट रहे हैं । जाति में बंटने के बाद गोत्रों में बंटेंगे । तो आखिर कहां तक बंटते रहेंगे । इसलिए यह सारा सिस्टम एक कर दिया जाए वरना यह जात-बिरादरी तो बंटती रहेगी । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)**

दूसरी बात यह है कि बिजली के बारे में यहां पर बहुत शोर मचाया गया । मैं बताना चाहता हूं कि 17 जनवरी से 27 जनवरी तक बिजली की कमी जरूर आई लेकिन 27 जनवरी के बाद किसान को उतनी बिजली जरूर मिली है जिससे उसकी जरूरत पूरी हो और जरूरत पूरी हुई भी । यह बात भी हुई कि मेरे इलाके में कई जगह तो ऐसा हुआ कि शाम के टाइम जब बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली चाहिए उस टाइम उनको बिजली नहीं मिली जिससे उनका रोष और

[मास्टर अजमत खां]

शौक बड़ा । तो एक मुद्दा बना कर अगर यह कहा जाए कि बिजली नहीं है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । बिजली की कमी है यह मानना पड़ेगा लेकिन इतनी कमी नहीं है कि उसे इस तरह से उछाला जाए । हमें यह कहा जाए कि कमी बिल्कुल नहीं है यह भी ठीक नहीं है । कमी तो है लेकिन जरूरत भी पूरी हो रही है । हां इसके लिए जो हमने कदम उठाए हैं, उसका रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा यह तो सरकार जाने । पानी के बारे में अभी मन्त्री जी कह रहे थे । हमारी गुड़गांव कैनाल के बारे में कहने लगे कि यह अप-लिफ्ट की नहीं है । गुड़गांव कैनाल अप-लिफ्ट कहीं से भी नहीं है । अलबत्ता गुड़गांव कैनाल पर तीन अप-लिफ्ट हैं । एक झायंसा में है, एक उतावड़ में है और एक हरचन्द पुर में है । ये तीन अप-लिफ्ट स्कीमें हैं, गुड़गांवा नहर को देखने हम गए थे । मदतपुर गांव जहां से यह निकलती है, वहां पर 13 फुट का निशान लगा हुआ था । आफिसर्ज हमारे साथ थे । हमने कहा कि भाई पानी नाप कर तो देखें कि 13 फुट है या कितना है । एक गवाला पानी में घुसा और उसने कहा कि यह तो 10 फुट सिल्ट से भरी हुई है और पानी तो तीन फुट ही है । तो हमारा नाप तो 13 फुट का है लेकिन हमें तीन फुट पानी मिल रहा है । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक उसकी डि-सिल्टिंग नहीं होगी तब तक गुड़गांव कैनाल में पानी पूरा नहीं जा सकता और हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद के इलाके सैराब नहीं हो सकेंगे । आगरा कैनाल के लिए हमारे सी० एम० साहब कोशिश कर रहे हैं कि उसका कन्ट्रोल हमें मिल जाए । जो सरकारें पहले थीं वे भी इसके लिए कोशिश करती रही हैं । तो एक सरकार को उसमें कैसे दोष दिया जाए । यू० पी० सरकार उसका कन्ट्रोल नहीं दे रही है और वह देगी भी नहीं क्योंकि उनकी जमीनों पर कब्जे होते जा रहे है फिर भी वह नहीं सोचते । इसके अलावा उस नहर में सिल्ट भी बहुत भर गई है और वे उसकी डि-सिल्टिंग भी नहीं कर रहे हैं । वे इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनको आबियाना नहीं दे रहे हैं । हमारे इलाके के लोग आबियाना इसलिए नहीं देते कि 58 से 82 तक बहुत बार फ्लड आये थे जो बहुत ज्यादा थे । उस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आबियाना लगा दिया जो करोड़ों रुपए में पहुंच गया । तो मैं अर्ज करूंगा कि जो फ्लड के जमाने में आबियाना लगाया गया था वह हमारे फरीदाबाद के इलाके के लोगों का यू० पी० सरकार से खत्म करवाया जाए । उसके बाद हमारे जमींदार आबियाना देने के लिए तैयार हैं । फ्लड के जमाने में तो हम वैसे ही परेशान थे । तो मेरी अर्ज है कि वह मामला निबटाया जाए । अगर सरकार उस आगरा कैनाल को नहीं लेती तो उसके जो माइनर्ज हैं वह हम ले लें उसके जो खाल हैं, वे पक्के करा दें एक उटावड़ कैनाल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज तक उस कैनाल पर इतना खर्चा हुआ है और उसके मुकाबिले में उससे एक परसैंट भी आमदनी नहीं हो रही है । हथीन से आगे 68 बुर्जी से आगे के लिए हमने एक स्कीम भिजवाई कि यह जो अप लिफ्ट स्कीम है यह कामयाब नहीं, अगर बिजली 12 घंटे चलती रहे तब तो पानी आगे पहुंच

जाता है, वरना पानी वापिस लौट जाता है । इसका कारण यह है कि उसकी टेल ऊंची है और हैड नीचा है, पानी उलटा लौट आता है । पानी 68 बुर्जी से आगे नहीं जाता । इसके इलावा यह 33 कि0मी0 लम्बी नहर है आप अप लिफ्ट स्कीम से अन्दर पानी नहीं दे सकते । सिंचाई विभाग ने एक नई स्कीम बनाई है । जिसके द्वारा हमें पानी रनसीके से आयेगा और 68 बुर्जी पर उटावड़ में वह स्कीम मिलेगी । उस स्कीम पर डेढ़ करोड़ रुपए की लागत आएगी । अगर वह लगा दी जाए तो हमारे इलाके में सारा पानी मिल सकता है । हमारी खास तौर से सी0एम0 साहब से दरख्वास्त है कि वे इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें । सी0 एम0 साहब ने 8 फरवरी 1992 को हथीन से इस नहर को पानी देने का विश्वास भी दिलाया था । आज नहर की हालत यह है कि लोग उसकी ईंटें भी उठा कर ले गये हैं । सरकार कृपया इस ओर विशेष ध्यान दे ताकि वह नहर चलती हो जाए और खेतों को पानी मिल जाए । (घंटी) मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपनी स्पीच को जल्दी ही समाप्त कर दूंगा । यह तो गुड़गांव कैनाल की बात थी ।

अब मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी के जरिए बच्चों और औरतों के लिए जो पैसा दिया जाता है, उस पैसे का कोई फायदा नहीं है । वह पैसा उन तक पहुंचता ही नहीं है । अगर वह पैसा किसी दूसरी स्कीम में लगा दिया जाए तो बेहतर होगा । उस पैसे को बच्चों के स्कूलों में खर्च कर दें या अस्पतालों में खर्च कर दें तो अच्छा होगा, इस तरह उसका काफी फायदा होगा । उस पैसे का बच्चे और औरतों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है ।

अब मैं इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहूंगा । हमारे इलाके में भी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं लेकिन उन इंडस्ट्रीज में जो लड़के नौकरी पर लगाए जा रहे हैं, वे दूसरी स्टेटस से ला कर लगाए जाते हैं । उन इंडस्ट्रीज में बिहार से आदमी ला कर नौकरी पर लगाए जा रहे हैं । हमने आज तक बिहारियों को हथीन में देखा तक नहीं था लेकिन अब तो बिहारी हथीन में काफी मात्रा में दिखाई देने लग गए हैं । हमारे इलाके के लोग भी उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए तैयार हैं । यह बात नहीं है कि हमारे इलाके के लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं । लेकिन बिहारी सस्ते पर काम करते हैं और हमारे इलाके का आदमी जायज पैसे मांगता है । हमने जोर लगा लिया लेकिन वे इंडस्ट्रीयलिस्टस हमारे इलाके के लोगों को नौकरी पर नहीं लगाते ।

इसके अलावा, मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा । सड़कों के बारे में आज ही मैंने एक सवाल दिया था । हमारे इलाके में 1991 के बाद कोई भी नई सड़क नहीं बनी है । जो पुरानी सड़कें थीं, उन्हीं सड़कों की मुरम्मत की गई है, नई सड़क कोई नहीं बनाई गई । मेरे हल्के में एक सड़क सनपालकी से फिरोजपुर राजपूत है । मैं इस सड़क के लिए 1982 से पुकार कर रहा हूं लेकिन वह सड़क नहीं बनाई गई

[मास्टर अजमत खां]

है। इन गांवों के लोगों को इस सड़क की बहुत सख्त जरूरत है। इन गांवों के लोगों को 15 किलोमीटर का चक्कर काट कर हथीन आना पड़ता है। इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि इन गांवों के लोगों को आसानी हो सके। एक सड़क सिहा से गढ़राण है उसको भी बनाया जाए। एक सड़क अलीमेव से नातोली है। यह केवल एक किलोमीटर का टुकड़ा है यदि उसको बना दिया जाए तो इन गांवों का पुनहाना के लिए सीधा रास्ता हो जाएगा और इस टुकड़े को बनाने से औरंगाबाद और चीनी मिल के लिए भी उन गांवों का सीधा रास्ता हो जाएगा। वह सिर्फ एक किलोमीटर का टुकड़ा बनना है यदि वह बना दिया जाता है तो उन गांवों के लोगों को जो काफी लम्बा रास्ता काट करके पुनहाना, औरंगाबाद और चीनी मिल पलवल तक जाना पड़ता है, उस परेशानी से बच जाएंगे। इसी तरह से एक सड़क मालुका से कुमहेरड़ा गांवों की है उसको बनाया जाए। इसी तरह से रानीयाला खुर्द से कोट, सिवली से लुहिना, पुठली से बिचपड़ी और गोहपुर से मोहदमका गांवों की सड़कों को बनाया जाए। इन सड़कों को चाहे सरकार बनाए और चाहे जय प्रकाश गुप्ता जी बनवाएं जिनके पास माईनिंग बोर्ड है उस के वे चेयरमैन हैं। इसी तरह से अब मैं मैडीकल कालेज के बारे में कहना चाहूंगा। हम चाहेंगे कि एक मैडीकल कालेज गुड़गांव या फरीदाबाद में खोल दिया जाए। वह पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं कहता हूं कि एक मैडीकल कालेज गुड़गांव, फरीदाबाद महेन्द्रगढ़ या रिवाड़ी इनमें से कहीं पर भी खोल दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उस साइड में इस समय कोई मैडीकल कालेज नहीं है।

इसके अलावा मैं होस्पीटल्ज के बारे में कहना चाहूंगा। नांगल जाट में 1986 में एक पी0 एच0 सी0 मंजूर हुई थी लेकिन आज तक वह पी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। वह पी0 एच0 सी0 1986 से बिना बिल्डिंग के चल रही है। मेरी रिकवैस्ट है कि उस पी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग के लिए पैसा दिया जाए और हथीन में जो होस्पीटल है उसकी बिल्डिंग के लिए भी पैसा दिया जाए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि हर तहसील हैडक्वार्टर पर लड़के और लड़कियों का कालेज जरूर होना चाहिए। सरकार की यह पालिसी हो कि जहां पर कालेज नहीं है पहले वहां पर कालेज जरूर बनाए जाने चाहिएं। (घंटी) आप बार बार घंटी बजा रहे हैं इसलिए इन्हीं अलफाज के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए। क्या मैं किसी हल्के की नुमायंदगी नहीं करता ? मुझे बोलने के लिए समय क्यों नहीं दिया जा रहा है। I have constitutional right to speak. (Noise).

श्री अध्यक्ष : बैरी साहब, आपका स्ट्रेन्थ के हिसाब से 90 वां हिस्सा टाईम बनता है उसके हिसाब से आपको बजट पर बोलने का समय दिया जाएगा । अब मुख्य मन्त्री जी बोलेंगे ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने 28 फरवरी को सदन में जो अपना अभिभाषण दिया, उस अभिभाषण की जितनी सराहना की जाये, कम है । इसकी सराहना अकेला मैं नहीं करता, सदन नहीं करता बल्कि सारे प्रदेश के लोग करते हैं कि राज्यपाल महोदय ने बहुत तफसील के साथ प्रदेश के विकास के बारे में बताया है कि यह सरकार अगले साल क्या विकास के कार्य करने जा रही है । इसकी जानकारी सारे देश और प्रदेश की जनता को दी है । इसलिए इस बात के लिए राज्यपाल महोदय का किन लफ्जों में धन्यवाद करूं वह शब्द तलाश करने पर भी नहीं मिलते । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर आज तक कभी भी टी0 वी0 पर राज्यपाल महोदय की कार्यवाही नहीं दिखाई गई थी लेकिन इस साल पहली बार राज्यपाल महोदय का भाषण टी0 वी0 पर दिखाया गया । इसके लिए मैं दिल्ली दूरदर्शन और जालंधर दूरदर्शन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस काम में अपना सहयोग दिया । इसके साथ साथ में भारत सरकार का भी आभारी हूं जिन्होंने इसके लिए हमको समय दिया और बाकायदा सारे देश के लोगों को हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण को दिखाया ।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर को भी दिखाने का प्रबंध करा दें तो अच्छा रहेगा ।

चौधरी भजन लाल : इस को भी दिखाने की कोशिश करेंगे । पर मुझे एक बात दुःख के साथ कहनी पड़ती है । अपोजीशन का भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सरकार कोई गलती करती है तो उस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए अपोजीशन का भी होना बहुत जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब भी अपोजीशन ने कोई अच्छे सुझाव दिए हैं तो हमने उनको माना है । लेकिन जिस ढंग से ये विपक्ष के भाई पिछले 4-5 दिनों से व्यवहार कर रहे हैं, वह उनके लिए शोभा नहीं देता । राज्यपाल महोदय का टी0वी0 पर भाषण आये, और ये सजपा के भाई हाउस में न हों, कोई अच्छी बात नहीं है । इनको कम से कम उस दिन तो बैठे रहना चाहिए था । मुझे इन की शक्ल से तो कोई नफरत नहीं है, लोग भी इन की शक्ल देख लेते ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता । ये हमारे ऊपर कोई मास्टर नहीं लगे हुए । इन्होंने अपनी बात कहनी है वह ढंग से कहें, किसी को उपदेश न दें । कौन क्या करता है,

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

क्या नहीं करता, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं । यह इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता । अगर कोई ऐसी बात करता है तो वह आपकी चेयर की भी अवमानना करता है ।

चौधरी भजन लाल : अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं । आप वैसे ही बीच में खड़े हो गए । अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे बीच में ही कुछ कहने लग जाएं, यह इनके लिए शोभा नहीं देता । मैं इनके लिए क्या कहूं, ये तो केवल एक मन बना कर आये थे कि हाउस को ठीक तरीके से चलने नहीं देंगे और हाउस की कार्यवाही को ठप्प करेंगे । इनका काम तो सिर्फ वाक आऊट करना है और गलत बात कहना ही इनका काम रह गया है । इनको, हमारी कोई कमी हो तो वह कहनी चाहिए, न कि आलोचना के नाते सिर्फ बेमतलब की आलोचना की जाये । ऐसी आलोचना का कोई आधार नहीं जिसका कोई मतलब न हो । सिर्फ वाक आऊट करें ताकि प्रैस में इनका नाम आ जाये । सिवाए इस के कोई इनका मतलब नहीं है । कोई कमी निकालते तो बात समझ में आती । अध्यक्ष महोदय, बजट सैशन बहुत महत्वपूर्ण होता है । इसमें अच्छी बातें कही जानी चाहिए, अपने हल्के की कमियों के बारे में कहना चाहिए न कि बेमतलब की आलोचना करनी चाहिए । सिवाय आलोचना के इन्होंने और कोई बात नहीं की । हां, धीरपाल जी ने और चौधरी जिले सिंह जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जो सदन में होता है, उसका प्रभाव सारे देश के लोगों पर पड़ता है । यदि सदन का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा तो फिर प्रदेश की जनता में सदन की गरिमा नहीं रहेगी । इसलिए हम सब का कर्त्तव्य बनता है कि हम सदन की गरिमा को कायम रखें । सदन के स्तम्भ पर लिखा है कि सदन में प्रवेश करें तो सत्य बोलें, असत्य न बोलें । अध्यक्ष महोदय, ये लोग अगर तथ्यों के साथ कोई बात कहें तो बात समझ में आ सकती है । अध्यक्ष महोदय, जो भी बात इन्होंने कही वह ठीक नहीं कही और अशोभनीय बात कही जाए यह ठीक नहीं । इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी सुझाव सरकार को नहीं दिया जिसके लिए मुझे खेद है । अध्यक्ष महोदय, छोटी-छोटी बात को लेकर कैसे ये लोगों की इज्जत उतारते थे । यह बैठे-बैठे कुछ भी कहते रहें । अभी कल ही पशु-पक्षियों के बारे में बात चल रही थी तो बैठे-बैठे इशारे करके बोल रहे थे अगर हमने "शर्म करो" कह दिया तो इन लोगों ने कितना भारी बवण्डर खड़ा कर दिया । हम चाहते हैं कि ये लोग सदन की गरिमा को कायम रखें । ठीक सुझाव सरकार को दें और सदन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलने दें । अगर सरकार में कोई कमी है तो उसको उजागर करें ताकि प्रदेश के लोगों को जानकारी हो और लोगों को पता हो कि प्रदेश में सरकार क्या कर रही है । प्रदेश के विकास के लिए कोई ठोस सुझाव दें । सरकार उस बारे में विचार करती उसका जवाब देती लेकिन इन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही इसके लिए मुझे बड़ा खेद है ।

स्पीकर साहब, इस सरकार को बने हुए अढाई साल हो गए हैं । अढ़ाई साल पहले इस प्रदेश की जो हालत थी वह जनता को अच्छी प्रकार से मालूम है । किस तरह से सारे प्रदेश का माहौल खराब हुआ था कैसे कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी हुई थी और कैसे सारे प्रदेश का वातावरण इन लोगों ने बिगाड़ कर रखा हुआ था । भय और आतंक का वातावरण सारे प्रदेश में बना हुआ था । जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हमने एक ही बात कही कि हम प्रदेश के अन्दर शांति के साथ विकास करेंगे । प्रदेश का शांति के साथ विकास करना हमारा मोटो था । प्रदेश के अन्दर पिछली सरकार ने जो डर और आतंक का माहौल पैदा किया हुआ था उससे लोग भयभीत थे । किसी बहन-बेटी की इज्जत महफूज नहीं थी, किसी भी शरीफ आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी उसे हर समय यह डर लगा रहता था कि पता नहीं कब कोई बदमाश आदमी उसकी पगड़ी उछाल दे । यही नहीं, आतंक अधिकारियों में था, कर्मचारियों में आतंक फैला हुआ था । सारे प्रदेश के अन्दर माहौल खराब हो गया था डर और आतंक छाया हुआ था । अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि अब राम राज आ गया है । राम राज्य तो राम के राज्य में भी नहीं हो सका था, उस वक्त भी रावण पैदा हुआ था जो सीता को हर के ले गया था । इनके राज का और अब के राज का आप खुद मुकाबला करके देख लें तो हर व्यक्ति यह महसूस करेगा कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर बहुत ही शानदार प्रशासन चल रहा है । जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्य मन्त्री थे तो स्टेज पर भाषण दिया करते थे कि वह मुख्य मन्त्री ही क्या जिसके नाम से व्यक्ति रात को सोते हुए चौंक कर चारपाई से नीचे न गिरें । स्पीकर साहब, मेरा एक नारा है कि मुख्य मन्त्री ऐसा होना चाहिए जिसके राज में सभी के जान और माल सुरक्षित हों और लोग चैन की नींद सो सकें उनको किसी प्रकार का कोई खतरा या भय न हो । ये कहा करते थे कि कोई आंख उठा कर देखेगा उसकी आंख फोड़ देंगे । अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ काट देंगे । कौन सी आंख से आंख निकालेंगे या कौन से हाथ से हाथ काटेंगे, यह तो पता नहीं । (विघ्न) आदमी को भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए । स्पीकर साहब, भगवान के घर में देर है परन्तु अन्धेर नहीं है । भगवान से डर कर रहना चाहिए भगवान सब कुछ देखता है । इस का अन्दाजा चौधरी देवी लाल की हालत से लगा सकते हैं । एक इतना बड़ा आदमी जो पूरे हिन्दुस्तान का डिप्टी प्राईम मिनिस्टर रहा हो, वह एम0एल0ए0 के चुनाव में हार जाए ? यह सब कुछ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कारनामों की वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने सारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल बना रखा था । अध्यक्ष महोदय, प्रशासन में इतना आतंक फैला हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं है । यहां तक कि सीनियर सैक्रेटरी भी सोच नहीं सकता था कि कब उसके साथ क्या व्यवहार हो जायेगा, वह कोई भी बात सरकार को कहने से डरता था क्योंकि पता नहीं सरकार कब क्या कह देगी । अध्यक्ष महोदय, हर सैक्रेटरी, हरेक अधिकारी या कर्मचारी अपनी इज्जत रखता है इसलिए हर आदमी का फर्ज बनता है कि वह सबसे इज्जत से बात करे । हर आदमी इज्जत के

[चौधरी भजन लाल]

लये काम करता है कोई आदमी एम0एल0ए0 या मन्त्री बनता है तो इज्जत के लिए बनता है। अगर इज्जत ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने किसी भी आदमी को बेइज्जत किए बगैर नहीं छोड़ा है। किस का नाम लूं ? इन्होंने बड़े-बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, एक बार जय प्रकाश जी जो स्टेट मिनिस्टर थे। हिसार में मीटिंग थी, उसमें चौधरी देवी लाल जी क्या कहते हैं कि जय प्रकाश क्या तू मेरे बिना अपने गांव की पंचायत का मैम्बर बन सकता है ? गवर्नर को जो चाहे कह दें यह इनकी भाषा है। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग अपने साथियों के लिए करना इनको शोभा नहीं देता और अब ये कहां खड़े हैं। मैं तो यह कहता हूं कि भगवान के घर देर होती है अन्धेर नहीं। जो आदमी घमण्ड की बात करता है ईश्वर उसे छोड़ता नहीं है। संसार में रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था न ही है, क्या कोई उसकी तरह शक्तिशाली था लेकिन उसे भी घमण्ड ने मार दिया। घमण्ड का सिर हमेशा नीचा होता है। अध्यक्ष महोदय, किस तरह का प्रदेश के अन्दर इन्होंने आतंक का वातावरण बनाया हुआ था। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने पूरे प्रदेश में अमन और शान्ति कायम की है। अध्यक्ष महोदय, कैसा आतंक का वातावरण पड़ौसी प्रदेश पंजाब में था। जब पड़ौसी के घर में आग लग जाती है तो अपना घर आग से बचा कर रखना मुश्किल होता है। हमारे प्रदेश की पुलिस ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमारी पुलिस ने पंजाब की आग की लपटों को हमारे प्रदेश में नहीं पहुंचने दिया।

अध्यक्ष महोदय अब मैं विकास के बारे में कहना चाहता हूं। अगर 80-81 के मुकाबले में 92-93 की अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखें तो 5.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो एक रिकार्ड है। इसी तरह से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में न सिर्फ डोमैस्टिक प्रोडक्ट में 91-92 के मुकाबले में 92-93 में 12.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन वर्ष 91-92 में 14,551 करोड़ था जो 92-93 में बढ़कर 16,392 करोड़ रुपए हो गया जो एक रिकार्ड है। मौजूदा सरकार के शासन काल में पिछली सरकार के शासन काल के मुकाबले में मूल्यों के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है वह वर्ष 92-93 में 9,609 रुपए बढ़ी है, जबकि प्रति व्यक्ति आय वर्ष 91-92 में 8,722 रुपए थी। हमने अपने प्रदेश की योजनाओं में विकास की गति को और तेज करने और समाज के सभी वर्गों को आर्थिक दिशा की ओर ऊंचा उठाने के लिए विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 94-95 की वार्षिक योजना में एक हजार पच्चीस करोड़ पचास लाख रुपए अनुमानित रखे गए हैं और वह राशि चालू वित्त वर्ष की योजना से 11 प्रतिशत ज्यादा है। हमारे राज्य के कुल प्लैन के आऊट-ले की 36.6 प्रतिशत राशि सामाजिक सेवा तथा 23 प्रतिशत राशि बिजली पर और 28.2 प्रतिशत राशि सिंचाई पर तथा बाढ़ की रोकथाम की स्कीमों पर खर्च करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने बिजली और पानी का मुद्दा उठाया । मैं आपको बिजली के बारे में कहना चाहता हूं । आज बिजली की समस्या इस प्रदेश के अन्दर है । यह समस्या किस की पैदा की हुई है ? यह जो मेरे सामने श्री ओम प्रकाश चौटाला, सम्पत सिंह और इनके साथी हैं, वे मुझे बता दें कि एक भी थर्मल प्लांट की आधारशिला रखकर इन्होंने वहां पर काम शुरु किया हो ? अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जमाने में जब में मैं मुख्य मन्त्री था, कुछ 81-82 और कुछ 83 में, जिन थर्मल प्लांटस की हमने आधारशिला रखी थी, उनको हमने ही चालू किया था और इन्होंने यह कह दिया कि हमारे राज में बिजली बहुत ज्यादा थी । मैं इनसे यह पूछता हूं कि क्या बिजली एक मिनट में बनती है ? अरे बिजली के प्लांट, फैक्टरियां और कारखाने ऐसे ही नहीं चलते हैं । अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि पांच साल तक 24 घण्टे काम करके तीन शिफ्ट बनाकर भी अगर प्रोजैक्टस पर काम करें तो पांच साल से पहले कोई थर्मल प्लांट चालू नहीं हो सकता । लेकिन इनका राज तो पौने चार साल रहा है और ये बिजली की दुहाई देते हैं । इन्होंने एक भी थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला नहीं रखी है । यह रिकार्ड की बात है और आंकड़ों की बात है । आज उसकी दिक्कत हमारे सामने आ गई है और वह दिक्कत क्या आई है कि ये 60,62 हजार ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन्ज छोड़ गए थे और लोगों ने लोन ले रखा था, टैस्ट रिपोर्टस उन्होंने दे रखी थी और लोन की किश्तें आनी शुरु हो गई थीं । हमने पिछले अढ़ाई साल में जैसे कि ए0सी0 चौधरी जी ने बताया है कि 41 हजार बिजली के कनैक्शन दिए हैं जिसके कारण 300 मैगावाट बिजली इनमें चली गयी ।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे आने के बाद कितने उद्योग लगे हैं । इनके राज में तो उद्योग बाहर जा रहे थे क्योंकि ये उद्योगपतियों को कहते थे कि तुम्हारी सारी बिक्री कितनी है ? जितनी सारी तुम्हारी बिक्री है उस पर दो परसैंट कमीशन हमें दो या अपनी फैक्ट्री यहां से ले जाओ । अध्यक्ष महोदय, जब ऐसा होगा तो कौन यहां पर फैक्ट्री लगायेगा ? ये कहते हैं कि हमारे समय में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था । किस तरह अच्छा बना हुआ था ? ग्रीन ब्रिगेड के लोग अपनी मर्जी से किसी की फैक्ट्री पर कब्जा कर लेते थे, किसी से पैसे ले लेते थे, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते थे और किसी भी म्युनिसिपल कमेटी की जमीन पर किसी भी पंचायत की जमीन पर ये लोग अपनी मर्जी से कब्जा कर लेते थे । ये कह रहे थे कि कुछ गांवों की जमीन पर कब्जा हो गया है तो मैं सोच रहा था कि क्या बात है । बाद में मुझे पता नहीं लगा कि इन्होंने दो चार गांव देख रखे होंगे कि जब इनका राज आयेगा तब हम उन जमीनों पर कब्जा कर लेंगे । अध्यक्ष महोदय, इल्जाम लगाना तो बहुत आसान बात है लेकिन इल्जाम लगाने से पहले कम से कम उनकी तह में जाना चाहिए । पंचायत को यह अधिकार है कि अगर वह पंचायत की किसी जमीन के बारे में कोई प्रस्ताव या रैजोल्यूशन पास कर देती है तो बाद में

[चौधरी भजन लाल]

वह मंजूर हो जाता है। बाद में उसकी ओपन आक्शन में नीलामी होती है, उसके बाद ही वह जमीन पंचायत बेचती है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अपनी जमीन प्राईवेट आदमी को बेचना चाहे तो सरकार उसको कैसे रोक सकती है। यह सरकार इनकी सरकार की तरह नहीं है। (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, इनको अपना जमाना याद आता है क्योंकि सारा कबाड़ा इन्होंने कर रखा था। ये अपने जैसा ही सबको समझते हैं सोचते हैं कि यह सरकार भी ऐसा ही करती है जैसा ये करते थे। ये कहते हैं कि अब बगैर पैसे दिए कोई नौकरी नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी बात ये कहते हैं। इनकी बातें तो मैंने पिछले सैशन में ही टेलीफोन की टेप की हुई सुनाई थी। लेकिन मैं अब इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि आदमी को कुछ सब्र भी रहना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सारा प्रदेश जानता है, सारा देश जानता है कि अगर कोई भी आदमी यह कहे कि हमारे राज में पैसे लेकर नौकरी मिलती है, पैसे लेकर तबादले किए जाते हैं या पैसे लेकर पोस्टिंग की जाती है तो हम उसी दिन छोड़कर चले जाएंगे। एक भी आदमी यह नहीं कह सकता कि पैसे लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई की बात होनी चाहिए। इस बात को लेकर पूरा प्रदेश जानता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जहां तक बिजली का ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुनानगर में 840 मेगावाट का प्रोजैक्ट तथा एक हजार मेगावाट का प्रोजैक्ट हिसार में चलाने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। साथ ही मैं आपको एक खुशी की बात और बताना चाहता हूं जैसे कि कल चर्चा चल रही थी कि भारत सरकार ने फरीदाबाद के गैस बेस्ड बिजली प्लांट के लिए कह दिया है कि गैस नहीं है लेकिन बाकायदा भारत सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आ गयी है कि हमने फरीदाबाद के बिजली संयंत्र को गैस से लिंक कर दिया है। अब इस प्रोजैक्ट पर काम शुरू हो जाएगा तो प्रदेश में बिजली की उतनी समस्या नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में तो उद्योग बिल्कुल ही बन्द हो गये थे। अध्यक्ष महोदय, उद्योग और ऐग्रीकल्चर दोनों ही देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। अगर कृषि नहीं होगी, किसान की आमदनी ठीक नहीं होगी तो देश कमजोर हो जाएगा इसलिए किसानों की तरक्की होनी चाहिए, किसानों के लिए बिजली होनी चाहिए। यही सोचकर कि हमने किसानों को बिजली देनी है इसलिए पानीपत के थर्मल प्लांट पर जो कि 210 मैगावाट का है, दिन रात काम चल रहा है। हम इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाने के प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी इसमें चार या पांच साल तो लग ही जायेंगे। फिर भी हम इसको ज्यादा आदमी लगाकर चार या साढ़े चार साल में चालू करवाने की कोशिश करेंगे। जब यह बनकर चालू हो जाएगा तो इससे 210 मैगावाट और बिजली हरियाणा प्रदेश को मिलेगी। आज 2300 मैगावाट बिजली प्रदेश के अन्दर है। इतनी बिजली बनने के बाद किसान और उद्योगपति

के लिए बिजली की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी । नई औद्योगिक नीति की वजह से, स्टेट की पालिसी की वजह से उद्योग भी प्रदेश में आए हैं । कोई 17 हजार नई इंडस्ट्रीज लगी हैं जिसमें एक लाख नौजवानों को रोजगार मिला है । ऐग्रीकल्चर में कितनी शानदार उपलब्धि हुई है आप जानते हैं । अध्यक्ष महोदय, जो ये छोड़कर गए थे उससे 12 प्रतिशत ज्यादा हमने ऐग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्पादन किया है । 102 लाख टन से ज्यादा अनाज पैदा किया है । इनके समय में किसान को 9 लाख टन यूरिया खाद और 3 लाख टन डी0ए0पी0 खाद मुहैया कराई गई थी । पिछले साल 1992-93 में 7.27 लाख टन डी0ए0पी0, 22.73 लाख टन यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध करवाई गई । 31 जनवरी, 94 को 30787 टन यूरिया और 29526 टन डी0ए0पी0 उपलब्ध था । आज हरियाणा प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है । वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान 38.35 करोड़ रुपये की कीड़े मार और खरपतवार नाशक दवाइयां किसानों को उपलब्ध करवाई गई । इन्हीं दो वर्षों में किसानों को 9.67 लाख की सबसिडी दी गई इसी कारण ही वर्ष 1992-93 में 102.65 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ है और इस साल के लिए 103.50 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 1966 में राज्य में गेहूं की पैदावार 8.72 लाख टन थी और आज बढ़कर 70 लाख 84 हजार टन हो गई है । इसी तरह से वर्ष 1966 में चावल की पैदावार 2 लाख टन थी जो अब बढ़कर 20 लाख 50 हजार टन तक पहुंच गई है इसमें 10 गुना वृद्धि हुई है । हम कृषि के विविधीकरण को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दे रहे हैं । इस साल प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 7.50 लाख टन से अधिक होने की आशा है । सरकार ने किसान को उसकी पैदावार के बहुत बढ़िया मूल्य दिए हैं । हमारी सरकार से पहले गेहूं का समर्थन मूल्य कभी दो रुपये, कभी एक रुपये और कभी 50 पैसे दे दिया जाता था । ये कहते हैं कि किसानों का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए लेकिन जो भाव हमने किसानों को दिए वह देश जानता है । केन्द्र में ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर से मेरी बात हुई । मैंने प्रधान मन्त्री जी से कहा कि किसान के साथ मजाक नहीं होना चाहिए । किसान को कम से कम 20-25 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देना चाहिए । 25 रुपये से शुरु किया और अब भारत सरकार ने गेहूं और पैडी का भाव बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है । वर्ष 1991-92 में 225 रुपये था, 1994-95 के लिए 350 रुपये निश्चित किया गया है । चने का समर्थन मूल्य 1991-92 में 450 रुपये था । 1994-95 के लिए 640 रुपये निश्चित किया है । राज्य सरकार ने किसान भाईयों को गन्ने के जो भाव दिए हैं वह एक रिकार्ड है । इनके राज में किसानों को गन्ना खेतों में जलाना पड़ा था । किसान इसे भूले नहीं है । ये लोग किसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कहा था कि आपका कर्ज माफ कर देंगे (विघ्न) किसानों पर कर्जों का कितना बोझ पड़ा । किसान के कर्ज का ब्याज माफ न करते तो किसान बर्बाद हो जाता । कर्जों का ब्याज माफ करने से स्टेट को 52 करोड़ का बोझ उठाना पड़ा । गन्ने का भाव हमने

[चौधरी भजन लाल]

60 रुपये दिया। सारे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा प्रदेश ने दिया। इलैक्शन के बाद यू0पी0 ने कुछ बढ़ाया (विघ्न) अच्छे भाव देने से किसानों को 1992-93 में 1500 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। इसी तरह से इस साल में हमारे किसान भाईयों को 1990-91 के मुकाबले में 2735 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बार-बार बिजली के बारे में कहा है। मैं आंकड़ों से आपको बताना चाहता हूं कि बिजली के मामले में हमने कितना उत्पादन किया है और कितनी सप्लाई की है। इस बारे में कितना सुधार हुआ है। वर्ष 1990-91 में बिजली की प्रति दिन औसत सप्लाई 229 लाख यूनिट थी जबकि 1992-93 में बिजली की प्रति दिन औसत सप्लाई 297 लाख यूनिट रही है। इस साल फरवरी, 1994 तक औसत सप्लाई 286 लाख यूनिट की है। हमने 23-9-1993 को 364 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की है और 24-9-1993 को 360 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की है। इसके अलावा 2-8-1991 को 351 लाख यूनिट बिजली सप्लाई हुई है। जबकि इसके मुकाबले में पिछली सरकार के शासन के दौरान ज्यादा से ज्यादा बिजली केवल 25-8-1990 को 315 लाख यूनिट सप्लाई की गयी थी। अगस्त, 1993 में ग्रामीण क्षेत्र को 65 परसैंट तक बिजली सप्लाई की गयी है। यह एक रिकार्ड की बात है। पिछले अढ़ाई वर्षों में हमने 35 नये सब-स्टेशन्ज बनाये हैं जबकि 112 सब-स्टेशन्ज की क्षमता बढ़ायी है। प्रदेश में हमने बिजली के उत्पादन की कई परियोजनाएं तैयार की हैं जिनके बारे में हम ने सदन में बताया है। हमने हरियाणा में कृषि इन्फास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ-साथ इंडस्ट्रियल इन्फास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया है। हमने प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये जितना अच्छा वातावरण तैयार किया है, उतना अच्छा शायद पहले कभी वातावरण नहीं था। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं वे भी और बड़े-बड़े एन0आर0आई0 हरियाणा में आ रहे हैं। वह इसलिये आ रहे हैं क्योंकि हरियाणा में अमन और शान्ति है। हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। हरियाणा का हर गांव पक्की सड़क पर है। हर गांव में आज बिजली है और हर गांव में पीने का पानी है। कहने का मतलब यह है कि सारे प्रदेश में सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा हरियाणा में इंडस्ट्रियल माडल टाउन जापान की तरफ से विकसित हो रहा है। जापान की कम्पनियां यहां पर आ रही हैं। जर्मनी की कम्पनियां यहां पर आ रही हैं। बहुत से दूसरे मुल्कों के लोग यहां पर आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल पार्क यहां पर बनाये जा रहे हैं ताकि बाहर के लोग यहां पर आयें और इंडस्ट्रीज लगायें। विदेशों से पैसा आयेगा और इससे देश के और प्रदेश के लोगों को काम मिलेगा। देश और प्रदेश की हालत सुधरेगी। आप देखेंगे कि आने वाले दो-अढ़ाई सालों में प्रदेश का क्या नक्शा बदलता है। प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम प्रदेश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे और इंडस्ट्री ज्यादा लगेंगी और डिवैल्प होगी। यह अपोजीशन के हमारे भाई क्या कहते हैं।

यह कहते हैं कि बाहर की कम्पनियां यहां पर आ रही हैं। हिन्दुस्तान को लूटकर ले जायेंगी। अरे, बाहर की कम्पनियां कैसे लूट कर ले जायेंगी। बाहर का पैसा यहां पर वे लेकर आयेंगे। उनके पास पैसा है। उन लोगों के पास ज्ञान है। आप जानते हैं कि इससे कितना लाभ देश और प्रदेश को होगा। कितना ज्यादा टैक्स आयेगा। सारे देश और प्रदेश की इकोनोमी इंडस्ट्री पर डिपैंड करती है। हम उस पैसे से प्रदेश में कितनी कितनी नहरों का निर्माण कर सकेंगे, कितने बिजली के प्रौजैक्ट लगायेंगे। कितने ही लोगों को रोजगार मिलेगा। जो बेकार और बेरोजगार पढ़े-लिखे नौजवान फिरते हैं, उन के हाथों को काम मिलेगा। इस बात की इनको कोई चिन्ता नहीं है। इन्होंने तो किसी तरीके से गलत बात करके और गलत प्रचार करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करनी है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग कुंज नाम से औद्योगिक काम्पलैक्स बनाने की योजना भी तैयार की है। हम यह चाहते हैं कि गांव में भी उद्योग लगें ताकि गांव के नौजवान लड़के-लड़कियों को काम मिले। भारत सरकार ने इस बारे में एक बड़ी शानदार योजना की घोषणा की है। प्रधान मन्त्री जी ने 15 अगस्त को एक बड़ी ही शानदार नयी नीति की घोषणा की है कि एक लाख रुपया हर पढ़े-लिखे नौजवान को देंगे ताकि वह अपनी इंडस्ट्री लगा सके और अपना कारोबार कर सके। इसके लिये सरकार कोई जमानत भी नहीं लेगी। जमानती की कोई जरूरत नहीं होगी। जो काम वह करेगा, वही उसका प्लैज कर लेंगे, वही रहन कर लिया जायेगा। ज्यों ही किश्तों में वह सारा कर्जा दे देगा तो वह रहन नामा फक हो जायेगा। वह चीज तुरन्त उनकी उनके अपने नाम हो जायेगी। इस स्कीम के लिये भारत सरकार से पैसा भी आ गया है। हमने पंचकूला हल्के से इसकी शुरुआत भी कर दी है। हमने अम्बाला जिले से स्टार्ट किया है क्योंकि आप जानते हैं, यह साईड थोड़ी बैकवर्ड है। हम इस योजना का सारे प्रदेश के अन्दर फैलाव करने जा रहे हैं ताकि वह नौजवान जो बेकार फिरते हैं, उनके हाथों को भी काम मिल सके। गत अढ़ाई वर्षों के दौरान प्रदेश में 427 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। 117 बड़े और मीडियम दर्जे के उद्योग स्थापित किये गये हैं। इसी अवधि में राज्य में 16837 यानी लगभग 17 हजार लघु उद्योग भी स्थापित हुए हैं जिनमें एक लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला है। जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक 733 उद्यमियों ने हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिये भारत सरकार को अपने आशय पत्र प्रस्तुत किये हैं। इनमें 5880 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिये जापान, इंग्लैंड, हालैंड इटली और अमरीका से भी अनेक उद्योगों के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इस उद्देश्य के लिए 240 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 176 एन0आर0आई0 को औद्योगिक प्लाट्स दिये जा चुके हैं और 33 विदेशी निवेदकों की इकाईयों ने उत्पादन भी शुरु कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने विभिन्न स्थानों पर सभी प्रकार के नाकों जैसे सेल्ज टैक्स बैरियर, चुंगी बैरियर वगैरह को हटाने का निर्णय लिया है। इनसे लोगों

[चौधरी भजन लाल]

को कितनी सकलीफ थी, कितना ट्रैफिक इनके कारण रुकता था यह लोग जानते हैं । इनसे लोगों को बड़ी भारी परेशानी थी । यह हमारा कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, यह बहुत बड़ा फैसला है । हमने यह फैसला इसलिये लिया ताकि देश की जनता को सुविधा मिल सके और किसी प्रकार की तकलीफ न हो ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना तक 5 लाख लोगों को नया अवसर जुटाने का निर्णय लिया है । इसके तहत रोजगार योजना पर विशेष-तौर से बल दिया गया है । जैसाकि मैंने अभी बताया कि अनपढ़ भाईयों के लिये हमारे सम्माननीय प्रधानमन्त्री महोदय ने यह फैसला किया है कि 18 से 60 वर्ष के बीच आने वाले व्यक्तियों को एक साल में 100 दिनों का पक्का रोजगार दिया जाएगा ताकि गांव का विकास हो सके । गांव के विकास के लिये पैसा दिया जाएगा और गरीब आदमी, साधारण व्यक्ति व आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनको रोजगार गांव में ही मिल जाएगा । इसकी भी व्यवस्था हमने की है । अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर 93 तक राज्य में जवाहर रोजगार योजना के तहत 18 लाख मैन डेज़ श्रम रोजगार जुटाया गया है । हम राज्य में पौलीटैकनिक संस्थाओं का भी प्रसार कर रहे हैं । हमने फैसला किया है कि बजाये साधारण शिक्षा के, टैक्नीकल ज्ञान बच्चों को दिया जाए । इसके लिये हमने आई० टी० आई० , पौलीटैकनिकस, इंजी-नियरिंग कालेजिज खोलने का फैसला किया है और लड़कियों की बी० ए० तक की शिक्षा फ्री की है, साथ में किताबें भी फ्री दी जाएंगी । पौलीटैकनिक तक भी हम लड़कियों को किताबें व वर्दी फ्री देंगे और साथ में पढ़ाई के लिये कोई फीस नहीं ली जाएगी ताकि टैकनीकल ज्ञान हमारे बच्चों को मिले । इससे वे अपने काम में भी लग सकेंगे और उनको रोजगार भी मिल सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय, जैसाकि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जिला अम्बाला व यमुनानगर के पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिये हमने शिवालिक बोर्ड की स्थापना की है ताकि उन इलाकों में तेजी से विकास का काम हो सके । राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और समाज के पिछड़े तथा कमजोर लोगों के लिये आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये वचनबद्ध है । इन इलाकों के विकास के लिये विभिन्न स्कीमें चलाई गई हैं । अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिये विभिन्न सहूलियतें, रियायतें दी गई हैं । अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दी और स्टेशनरी आदि की सहूलियतें दी जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वाधिक बनाने और साक्षरता का सौ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने तथा महिलाओं को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान

दिया है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में 500 नये लड़कियों के स्कूल कायम किये जा रहे हैं । प्राथमिक शिक्षा के लिए 1992-93 में 4.78 लाख से अधिक बच्चों को प्राईमरी स्कूलों में दाखिला दिया गया है । प्राईमरी स्कूलों में लड़कियों के दाखिले की दर 1990 में 87 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 100 प्रतिशत हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ साथ मौजूदा सरकार ने समाज कल्याण, पीने का पानी, सड़कों का निर्माण, पर्यटन के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। ढाई वर्षों में 6.166 किलोमीटर पुरानी सड़कों पर रिनूल कोट बिछाई गई है और 757 किलोमीटर्ज सड़कों को चौड़ा किया गया और मजबूत बनाया गया है । 402 किलोमीटर सड़कें नई बनाई गई हैं । अम्बाला-दिल्ली मार्ग पर भारी यातायात को कम करने के लिये यमुनानगर के और दिल्ली के बीच तक एक ऐक्सप्रैस हाई-वे बनाने का सरकार का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से नैशनल हाई वे और स्टेट हाई वे के सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । 1992-93 में राष्ट्रीय राज मार्ग नं0 1 के 25 किलोमीटर रास्ते को फोर लेनिंग के लिये खोल दिया गया है । जून 94 तक 50 किलोमीटर सड़कें और पूरी होने की सम्भावना है। इन लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय, अपने वक्त में फोर लेनिंग सड़कों के निर्माण को बन्द करवा दिया था । मुझे याद है इन्होंने उस ठेकेदार को कहा कि हमें इतना पैसा चाहिये । उन्होंने कहा कि यह कंपनी बाहर की कंपनी है । हम कोई पैसा दो नम्बर में नहीं रखते । हम इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते । इन्होंने कहा कि इतना पैसा दो वरना काम बन्द कर दो । वे काम को बन्द करके चले गये । नहीं तो आज तक यह फोर-लेनिंग कभी की बन गई होती; अगर ये उनसे पैसा न मांगते । फोर लेनिंग न बनने के कारण अध्यक्ष महोदय, आप को पता है कि एक्सीडैन्ट्स में कितनी वृद्धि हुई ? यातायात में लोगों को कितनी तकलीफ हुई ? हमने आते ही दोबारा उन कंपनी वालों से मीटिंग करके, उनको कहा कि नहीं यह सड़क आपको बनानी ही पड़ेगी । जो रेट उनसे पहले सैटल हुआ था, उसी रेट पर हमने वह सड़क बनवाई है । अध्यक्ष महोदय, रात दिन उस पर काम चल रहा है जो आपके सामने है। अकेली उस सड़क पर ही नहीं बल्कि नैशनल हाईवे 10 नं0 पर भी उससे आगे 8 नम्बर पर भी और दो नम्बर पर भी काम चल रहा है । अध्यक्ष महोदय, जहां सरकार ने क्वालिटी आफ लाइफ को ऊंचा करने की योजना शुरू की है वहां प्रदेश में पर्यावरण यानी शहरों तथा गांवों के सुन्दरीकरण के कार्यक्रम को भी शुरू किया हुआ है । सरकार ने प्रदेश में पर्यावरण अदालतें कायम करने का निर्णय लिया है। ये अदालतें अम्बाला, रोहतक और हिसार में कायम की जाएंगी । इसके अलावा राज्य के स्कूलों में पर्यावरण क्लब खोले जाएंगे । हिसार तथा रोहतक जिलों में पर्यावरण ब्रिगेड की स्थापना के लिए भी कदम उठाने जा रहे हैं । पर्यावरण के काम में प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाना हमारा लक्ष्य है । पर्यावरण की रक्षा और बंजर भूमि के सुधार के लिए अरावली पहाड़ी में पेड़ों को लगाने का

[चौधरी भजन लाल]

विशेष अधिवेशन शुरू किया गया है। इस प्रकार से कई और भी कदम पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ कर्मचारियों के हितों के लिए काम हो रहे हैं, कर्मचारियों की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। इनके वक्त में उनकी क्या हालत थी, क्या हालत थी उनकी चौधरी बंसी लाल जी के वक्त में। चौधरी बंसी लाल के वक्त में वे दिल्ली में गए थे। इन्होंने उनको पिटवाया और उनकी बुरी हालत कर दी थी। यह क्या हालत थी इनके राज में। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के लिए हमारी बड़ी हमदर्दी है। वे हमारे भाई हैं, भाई हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट ऑफ़ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। यह कहते हैं कि मेरे राज में वे दिल्ली में पिट गए थे। दिल्ली तो यूनियन टेरेटरी है। मेरे अपने शहर भिवानी में कर्मचारियों ने 50 हजार आदमियों की रैली की थी और मैंने नाम भी नहीं लिया और इन्होंने पानी के पाइप तुड़वाए, बसों से उतारा और रैलों से उतारा। फिर आज ये लोग एम्पलाइज के हमदर्द बनते हैं। नौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हांसी हज को चली। (हंसी)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या कहूं। चौधरी बंसी लाल जी मेरे से उमर में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता लेकिन कर्मचारियों को सब याद है। जिसको चोट लगती है, उसको याद रहता है और उसका नतीजा उन लोगों ने आपको 1987 के चुनाव में दिखा दिया था। आप मुख्य मन्त्री होते हुए भी हारे थे उनकी मेहरबानी से।

चौधरी बंसी लाल : वह तो मरा हुआ सांप मेरे गले में डाल दिया था।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि मरा हुआ सांप मेरे गले में डाल दिया था। गजब हो रहा है। एमरजेंसी में, 1975 में तो आपका ही राज था और आप ही मुख्य मन्त्री बना कर सेंटर में गए थे। उस वक्त भी आपकी पांच सीटें आई थीं। आपका तो शेर के बच्चे का हाथ ही ऐसा है (हंसी)। मैं ज्यादा नहीं कहता लेकिन कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। मैं कोई इस सदन का माहौल भी खराब नहीं करना चाहूंगा। बातें तो बहुत कह सकता हूं, बहुत जानता हूं क्योंकि आपके साथ रहा हूं और आपकी सारी करतूतें जानता हूं। उधर से बैठे हैं श्री ओम प्रकाश जी, उनको भी जानता हूं लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे आपके दिल को जरा सी भी तकलीफ हो।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सियासी का ... नहीं किया है, ऐसा ही बुरा किया ...

चौधरी भजन लाल : शाबास ! कहते हैं मैंने किसी का [illegible] नहीं किया। चौधरी बंसी लाल जी, अगर आप भी [illegible] टूट पड़ेगा । (हंसी) आप तो यूं कहा करते थे कि [illegible] चलता है और औरत बच्चा पैदा करती है 9 महीने में, लेकिन भजन लाल [illegible] में एम0 एल0 ए0 पैदा करता है । (हंसी) अगर मुझे वह [illegible] वह सुना भी दूंगा ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, यह इनकी मन घड़न्त बात है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सदन बैठा हुआ है [illegible] सम्पत सिंह जी के भट्टू हल्के में पड़ता है और आदमपुर से शायद दस किलोमीटर है, अभी उस गांव के बहुत लोग जिन्दा हैं । ऐसा कर लें कि [illegible] वहां चली जाए । आदमपुर में भी आपने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था [illegible] में भी कहा था । अगर कमेटी वहां जा कर कह दे कि आपने यह नहीं [illegible] अस्तीफा दे कर घर चला जाऊंगा ।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, ये कई बार अस्तीफा दे चुके हैं और कई बार राजनीति छोड़ चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि खुदकशी कर लूंगा । अगर ये एक दिन यह बात सच्ची कर दें तो झगड़ा ही नहीं रहेगा। (हंसी)

चौधरी भजन लाल : बंसी लाल जी, यह सियासत है । इस कुर्सी पर जनता जिसको चाहे उसको बैठा सकती है । आप तो जानते हैं जनता ने आप जैसे आदमी को भी इस कुर्सी पर बैठा दिया था और ओम प्रकाश चौटाला जैसे आदमी को भी बैठा दिया । भजन लाल तो आप दोनों से कुछ सुन्दर ही लगता है । (हंसी) यह जनता की बात है। चौधरी बंसी लाल जी, किसी ने ऊंट से पूछा कि ऊंट के ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी । आपकी कोई कल सीधी भी है क्या, जरा लोगों को [illegible] उतार कर दिखाएं लोगों को पता लगे । मैंने तो आपको कच्छे और बनियान में भी देख रखा है । (हंसी) अध्यक्ष महोदय, हमने कर्मचारियों को पूरी सुविधाएं दी हैं और हमेशा देते रहते हैं । जब भारत सरकार कर्मचारियों को कोई राहत देने का फैसला करती है तो हम वह राहत अपने कर्मचारियों को एक महीने के अन्दर अन्दर देने का फैसला कर देते हैं । आज की सरकार का कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा ही सहानुभूतिपूर्वक रवैया रहा है । आज की सरकार ने तीसरे तथा चौथे वर्ग के कर्मचारियों को 10 और 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, अगला वेतनमान देने का निर्णय लिया है । इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के पैटर्न पर दिनांक 16-9-1993 से 100 रुपए प्रति मास की दर से अतिरिक्त लाभ प्रदान किया है और 1-1-94 से फिक्स मैडीकल अलाउंस 45 रुपए से बढ़ा कर 60 रुपए प्रति मास किया है । चौथे वर्ग के सभी कर्मचारियों को वर्दी देने के बदले में 60

[चौधरी भजन लाल]

रुपए प्रति मास वर्दी भत्ता वेतन के साथ देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1991-92 और वर्ष 1992-93 का बोनस केन्द्रीय सरकार के पैटर्न पर वर्ष 1994-95 में देने का निर्णय लिया गया है । इस तरह से राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं देने पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा । हमने 100 करोड़ रुपए की राहत अपने कर्मचारियों को दी है । (थम्पिंग)

अध्यक्ष महोदय, हम लैंड रिकार्ड की कम्प्यूटराइजेशन और आधुनिकीकरण के लिए वचनबद्ध हैं । इस बारे में हमने ठोस कदम उठाए हैं । इस काम के लिए सबसे पहले रिवाड़ी जिले को पायलेट के आधार पर चुना गया है । कोसली तहसील में भी यह कार्य चल रहा है और 120 लाख रुपए की लागत से रोहतक, हिसार और सिरसा जिलों में कम्प्यूटर लगाने का हमारा विचार है। इसी सैशन में एक बिल ला रहे हैं ताकि हम किसानों को पास बुक दे सकें जिससे किसान को हर वक्त पटवारियों के पीछे न भागना पड़े । कर्जा लेना है, जमीन लेनी है या देनी है तो वह उसी पास बुक में दर्ज हो जाएगा । इस तरह से पास बुक देने से किसान को पूरी राहत मिलेगी । इसके लिए हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर श्री निर्मल सिंह जी ने बहुत प्रयास किए हैं और उन्होंने इस बारे में बहुत शानदार काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस के बारे में चर्चा करता हूं । बहुत से माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए जो बातें कही हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा । सबसे पहले सम्पत सिंह जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोले थे । उस समय मैं समझ रहा था कि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफसर रहे हैं, कोई अच्छी बात कहेंगे, ठीक बात कहेंगे, समझदार हैं क्योंकि ये मंत्री भी रहे लेकिन समझदारी इनके नजदीक से नहीं टपी है, वह बहुत ही दूर है । इन्होंने एक भी सुझाव नहीं दिया । इन्होंने जो पढ़ाई करी थी, वह भूल गए या उसको कहीं जमा कर रखा होगा या पड़ोसी की अकल से काम लेते होंगे । (हंसी) आप इधर के पड़ोसी मत समझो । भट्टू आदमपुर के पड़ोस में है, वह पड़ोस समझो । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है । हमें यह सुन कर बड़ा अफसोस है, बहुत ही अफसोस है । कहते हैं चोरी, डकैती है, मौतें बहुत हो गई, जमीनों पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, ला एंड आर्डर की बात सम्पत सिंह जैसा आदमी करे और कोई करे तो बात समझ में आ सकती है । सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली, गजब हो रहा है । अरे आप अपना जमाना भूल गए, उस समय प्रदेश की क्या हालत थी ? आज आप जा कर लोगों से पूछें, लोग आपको बताएंगे कि प्रदेश में कितना अमन और शांति है और ला एंड आर्डर कितना शानदार है । जिस काम की लोग प्रशंसा करें वह सही काम होता है । आपके कहने से बुरा नहीं

हो सकता है। अच्छा तो आपका कहने का कोई सवाल ही नहीं क्योंकि अच्छा कहना आप सीखे ही नहीं। एक बात इन्होंने यह कही कि स्टेट की फाइनैंशियल हालत बहुत खराब हो गई है, स्टेट दिवालिया हो गई अध्यक्ष महोदय, यदि फाईनैंस की

1.00 बजे | हमारी हालत खराब होती तो फिर ये विकास के काम कैसे हो रहे होते। हमने प्रदेश के हर तबके में पीने का पानी पहुंचाया है। क्या आपने अपने समय में कभी सड़कों पर कोई रोड़ी लगाई? हमने आते ही सारी टूटी हुई सड़कों को फिर अच्छी हालत का बनाया ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। दूसरी बात इन्होंने यह कह दी कि कोई उत्पादन नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमने सैन्ट्रल पूल में 12 परसैन्ट ज्यादा अनाज दिया है। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सैन्ट्रल पूल में गेहूं देने का हमारा टारगेट 18 लाख टन का था, जबकि हमने दिया है 36 लाख टन के करीब। इसी प्रकार से चावल का 10 लाख टन था, जबकि दिया गया है 11½ लाख टन। इससे पता चलता है कि हमारे समय में उत्पादन बढ़ा है या नहीं। यह तो एक रिकार्ड की बात है।

अध्यक्ष महोदय, कभी ये लैंड ग्रेबिंग की बात करते हैं। उसकी चर्चा तो अब मैं नहीं करूंगा, सदन का समय खराब होगा लेकिन एक बात कहता हूं कि इन्हें अपना डिजनीलैंड का स्वप्न याद आ रहा होगा। जो आदमी बेईमान होता है, वही दूसरे को बेईमान समझता है। इसलिए ऐसी कोई बात कहने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखना चाहिए, तब ही किसी दूसरे पर आरोप लगाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने कह दी कि भजन लाल की सभाएं फेल हो रही हैं, इसलिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारी सभाएं बाकायदा पूरी सफल हो रही हैं और सरकारी मशीनरी का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं हो रहा। लोग खुद अपने ट्रैक्टरों में, पैदल चलकर या और किसी साधन के जरिए हमारी सभाओं में पहुंचते हैं। चौटाला साहब ने क्या कर रखा है? हमारे यहां पर 90 हल्के हैं। इन्होंने हर हल्के में 5-5 कैन्डीडेट बनाये हुए हैं। इस प्रकार 90×5 यानी 450 लोग तो ये हो गए। जब इन्होंने कहीं सभा करनी होती है तो इन 450 लोगों को कह रखा है कि अपनी कार में 10-10 आदमी साथ रखो। यानी जहां पर भी ये जलसा करते हैं तो ये 450 आदमी 4500 हो गए। इस प्रकार ये लोगों को इकट्ठा करके सभा करते हैं। इनकी सभा में कभी भी 5000 से ज्यादा आदमी नहीं होते। (विघ्न) ये सभाओं में अपनी तरफ से ही कभी चांदी का मुकुट लेते हैं तो कभी कुर्सी। ये सोचते हैं कि यह कुर्सी न मिली तो यह चांदी की ही सही। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनकी तो यह हालत है कि किसी गांव का एक ठाकुर एक घोड़ी पर चला जा रहा था कि रास्ते में उसकी घोड़ी ब्या गई। इधर पीछे से एक और मरासी चला आ रहा था और परेशान था कि यदि कोई घोड़ी

[चौधरी भजन लाल]

मिल जाये तो उस पर बैठ कर चला जायें । जब वह मरासी उस घोड़ी वाले के पास पहुंचा तो उसने कहा कि भाई यह बछड़ी उठा ले, तो उस मरासी ने कहा कि ए खुदा तेरे यहां की बड़ा बेइसाफ है । मैंने तो घोड़ी मांगी थी चढ़ने के लिए, उल्टा मुझे यह घोड़ी की बछड़ी उठाने के लिए दे दी तो, इनकी तो यह हालत है।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एस0 वाई0 एल0 और भाखड़ा नहरी पानी के बारे में जिक्र किया है । मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि इस मसले पर सारे प्रदेश की जनता बड़ी चिन्तित है । इस बारे में मैं एक बात स्पष्ट करता हूं कि चण्डीगढ़ के बारे में बेअंत सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि मैंने कभी नहीं कहा कि 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन चण्डीगढ़ पंजाब को मिल जायेगा और न ही प्रधान मंत्री ने ऐसी कोई बात कही है कि इस दिन चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जायेगा । दूसरा रह गया सवाल एस0 वाई0 एल0 नहर के बारे में । इस बारे में, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि इस नहर का 95 प्रतिशत काम हो चुका है, 5 परसैंट रहता है । यह नहर बनेगी । ये इस नहर के बनाये जाने बारे एक प्रस्ताव लाये थे, कहने लगे कि इसे पास किया जाये कि एस0 वाई0 एल0 नहर बने । लेकिन इस बारे में मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पड़ोस में पंजाब की भी असैम्बली है, वे भी यह प्रस्ताव ला सकते हैं कि नहर न बने। अगर हम कोई प्रस्ताव करेंगे तो क्या वे प्रस्ताव नहीं करेंगे ? फिर दोबारा नये सिरे से सारा मामला खड़ा हो जाएगा । जिस बात से हरियाणा के हित को नुकसान होता हो, क्या ऐसा काम करना हमें शोभा देता है ? (विघ्न) अगर वे असैम्बली में प्रस्ताव करें कि हम नहर नहीं बनाएंगे तो फिर आप या हम उन का क्या कर सकते हैं ? (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं कह रहे कि ये चिन्तित नहीं हैं। इस मामले को ले कर आज सभी लोग चिन्तित हैं । आपने टैरीटरी का जिक्र किया है । आज सरदार बेअंत सिंह जी का ब्यान भी आया है । एस0 वाई0 एल0 के बारे में उनका ब्यान आया है कि मैंने एस0 वाई0 एल0 के बारे में हरियाणा के मुख्य मन्त्री को कोई आश्वासन नहीं दिया है । ये इस बारे में भी तो बताएं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद बता दिया है और चण्डीगढ़ के बारे में तो इनकी तसल्ली हो गई होगी, अब एस0 वाई0 एल0 का सवाल रह गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में प्रधान मन्त्री जी से कई दफा बातचीत हुई है और कई मीटिंगें भी हो चुकी हैं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को प्रधान मन्त्री जी ने पानी के मामले को ले कर एक बैठक बुलाई है जिसमें पंजाब के मुख्य मन्त्री को और मुझे बुलाया गया है । उस बैठक में पानी के मसले को लेकर बातचीत होगी कि किस तरह से हम एस0वाई0एल0 नहर को पूरा करवा सकते हैं ।

एस0वाई0एल0 कैनाल जरूर बनेगी और हर हालत में बनेगी, इसको रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । अध्यक्ष महोदय, इनकी तरह से नहीं कि जब कुर्सी पर होते हैं, तब तो एस0वाई0एल0 और चण्डीगढ़ की बात नहीं करते और जब कुर्सी पर नहीं होते, तब इन्हें एस0वाई0एल0 और चण्डीगढ़ की याद सताती है । अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 को मिट्टी से भरने की बात कौन कहता है । सरदार प्रकाश सिंह बादल जी कहते हैं कि जो नहर खुदी है, उसको मिट्टी से भरेंगे और चौधरी देवी लाल जी कहते हैं कि पंजाब के मुख्य मन्त्री प्रकाश सिंह बादल जी होने चाहिएं ताकि नहर मिट्टी से जल्दी भर जाए । अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम नहर बनाने के काम में लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि नहर बने और उसका पानी हरियाणा को मिले । हमारी कोशिश है कि 1995 तक इस नहर का काम पूरा हो जाये । चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि इस नहर का काम मैंने करवाया था । चौधरी बंसी लाल जी, जरा पीछे नजर दौड़ा कर याददाश्त ताजा कीजिए कि जब मैं यहां से सैंटर में गया था, तब आप यहां पर मुख्य मन्त्री बने थे । आपने पंचों को और सरपंचों को वहां ले जा कर नहर दिखाई कि देखो, कितनी नहर बन गई है । क्या वह नहर 6 महीने में ही बन गई थी ? (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : जो कुछ भी है, वह आपके सामने की बात है । अध्यक्ष महोदय, ये एक असत्य बात को बार-बार कह कर सत्य बनाने वाली बात की कोशिश क्यों करते हैं । मैंने पिछले साल कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट यहां इस सदन में पढ़ कर सुनाई थी, मैं उसको फिर दोबारा यहां पढ़ दूंगा । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : उसकी बाबत मैं नहीं कहता । आपने पंचों और सरपंचों को ले जा कर जो नहर दिखाई थी, क्या वह नहर आपने बनाई थी ?

चौधरी बंसी लाल : मैंने 6 महीने में बना कर दिखाई थी । पंजाब कैम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की रिपोर्ट सदन में पढ़ कर सुनाई थी, वह रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, इन्होंने कोट लेने के लिए वह नहर दिखाई थी । वह नहर भजन लाल की बनवाई हुई थी । एक महीने में नहर नहीं बनती है । (विघ्न) सम्पूर्ण सिंह और ने कहा कि बी0आर0एम0 का फैसला चन्द्र शेखर जी ने किया । बी0 आर0 ओ0 का फैसला [illegible] एम0पी0 था और राजीव गांधी जी की रिपोर्ट से जब चन्द्र शेखर जी प्रधान मन्त्री बने थे तो तब से वह कोर्ट में केस था कि [illegible] एस0वाई0एल0 नहर इससे बनवाईये, तब इसके हाथ में [illegible] जी ने कहा कि [illegible] ओ0आर0ओ0 का आर्डर [illegible] (विघ्न) [illegible] कहा था कि ओ0आर0ओ0 का आर्डर ही नहीं हुए हैं । स्पीकर

[चौधरी भजन लाल]

साहब, सम्पत सिंह जी की इस बात को सारा प्रेस जानता है और रिकार्ड पर भी यह बात है । (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी तो अब इस संसार में नहीं हैं । ये नहर का काम शुरु करवा दें और चन्द्रशेखर जी से यह कहलवा दें कि उन्होंने ऐसा कहा था । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये स्वयं उनसे अलग से पूछ लें तो इनकी तसल्ली हो जाएगी । (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये तो कभी 24 घण्टे में सत्य बोलते हीं नहीं हैं, इसलिए उनसे पूछना पड़ेगा । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये उन्हीं से पूछ लें, अगर वे इस बात को मान लें तो फिर .....(विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर वे कह देंगे तो हम मान लेंगे । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, फिर इससे आगे ये क्या कहेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इस से आगे इन्होंने बुढ़ापा पैंशन की बात कह दी । हम यह मानते हैं कि कुछ समय से हम बुढ़ापा पैंशन नहीं दे सके हैं । इसमें भी इनकी मेहरबानी हो गई है और वह मेहरबानी क्या हो गई कि बिजली की प्रोब्लम आ गई । बिजली बोर्ड ने सारे प्रदेश के बिजली के कनैक्शन काट दिए । उन्होंने कहा कि पहले पैसा दो, फिर बिजली देंगे । कई दफा ये कहते हैं कि भजन लाल ने बिजली सैन्टर को दे दी । अरे सैन्टर को बिजली देने का सवाल ही नहीं है क्यों कि हम सैन्टर से तो बिजली लेते हैं । हमारे प्रदेश में जो बिजली बनती है, वह कभी 90 लाख यूनिट, कभी एक करोड़ यूनिट से कुछ ऊपर । बिजली हमें तीन करोड़ यूनिट से ज्यादा देनी चाहिए । दो करोड़ यूनिट तो कम से कम हम एन0टी0पी0सी0 से लेते हैं और 1.30 रुपए और 1.50 रुपए के भाव में लेते हैं । कुल मिलाकर हमें 1.50 रुपए प्रति यूनिट बिजली घर में पड़ती है । हम किसान को सबसीडाईज करके 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देते हैं और ये उनको जाकर भड़काते हैं । अध्यक्ष महोदय, आगे जाकर बिजली हमें घर पर ही 2.50 रुपए प्रति यूनिट पड़ेगी । मुझे ये समझ नहीं आता कि ये किसानों को क्यों गुमराह करते हैं ? हम उनको पैन्शन नहीं भेज सके हैं और यह बात मैंने पब्लिकली मानी है कि हमें बुढ़ापा पैन्शन देने में देर हो गई है । उनकी पैन्शन हमारे पास जमा है । हम इनकी तरह यह

नहीं कहते कि हम कर्ज माफ कर देंगे और फिर उसके बाद कह दिया कि कोआप्रेटिव के कर्जे भी माफ कर देंगे। हम जो कहेंगे वह करेंगे भी। किसान हमारे भाई हैं। वे आपके भाई नहीं है। हमने इसके लिए उनसे कहा कि हमें माफ करना, हम आपकी बुढ़ापा पैन्शन नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके क्योंकि हमें बिजली के पैसे देने पड़ गये इसलिए नहीं दे सके। हम आपको पन्शन अप्रैल के महीने में दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह जो आपने कर्जे वाली बात कही है वह कर्जा किस टाईम का था ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये खुद ही मानते हैं कि वह कर्जा इनके वक्त का था।

प्रो0 सम्पत सिंह : आप तो पैन्शन में कटौती भी कर रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : अगर आपने किसी 50 साल वाले का नाम भर रखा होगा तो वह हम काटेंगे ही। गलत ढंग से तो किसी को पैन्शन मिलेगी नहीं। अगर कोई सही है तो हम नहीं काटेंगे। मैं तो यह कहता हूं कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको नोटिस तो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक साल के अन्दर लगभग 11 सौ करोड़ यूनिट बिजली लेते हैं। अगर इससे आधे का भी हिसाब लगाया जाए तो पांच सौ करोड़ बिजली किसानों के घरों में सबसीडाइज्ड करके जाती है। अगर एक रुपए प्रति यूनिट का नुक्सान हो तो सीधा साढ़े पांच सौ करोड़ का नुक्सान होता है। इस प्रकार से किसान को सबसीडाइज करके बिजली देने से सरकार को तकरीबन अढ़ाई करोड़ रुपए का हर साल घाटा रहता है। इसलिए हमने 50 करोड़ रुपए देकर बाकी का पैसा किस्तों में देने की बात कही है और तब जाकर बिजली आई है। अगर हम पैसा देंगे तो बिजली आएगी। बिजली कोई जादू से नहीं बनती है।

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने परमिट की बात कह दी। इस बारे में ओमप्रकाश बेरी ने कहा और इनमें से सम्पत सिंह ने भी कहा था कि जब परमिट मिल रहे थे तो हमने एक से पूछा कि परमिट मिल गया तो वह हंस पड़ा। वह हंसा क्यों ? वह हंसा इसलिए कि ये जो पूछ रहे हैं इनके राज में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता था और आज वही आकर पूछ रहे हैं कि परमिट मिल गया। अरे वह तो आप पर हंसा था। उसे बहुत ही आराम से परमिट मिला। अध्यक्ष महोदय, परमिट बाकायदा लाटरी के द्वारा मिला। जब अम्बाला में लाटरी निकली तो वहां पर पांच सौ-सात सौ नौजवान आमिल थे। इस बारे में अखबारों में छपा है कि बहुत ही अच्छे और फेयर ढंग से परमिट दिए गए हैं।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात कैबिनेट में भी उठी थी । और बात अखबारों में भी छपी थी । हम यह नहीं कह रहे हैं । कैबिनेट ने भी इसका विरोध किया था, आखिर यह मामला क्या था ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने कमेटी बनायी थी जिसमें एम0एल0ए0 भी थे और दूसरे लोग भी थे । कमेटी हमने इसलिए बनायी थी कि रूटों को आईडेन्टीफाई किया जा सके । इसका फोरम बनाकर बाकायदा अखबारों में ऐडवरटाईज हुआ । उसके बाद ऐप्लीकेशंज भी आयीं, तब कहीं जाकर बाकायदा अम्बाला के अन्दर सीनियर अधिकारियों के सामने लाटरी निकाली गयी । लाटरी के निकालने की सारे प्रदेश के लोगों ने प्रशंसा की है । (विघ्न) आप सुनने की कृपा तो करें । कुछ मंत्रियों ने भी कहा है यह ठीक है । मैं आपकी तरह झूठ नहीं कहूंगा । कुछ मन्त्रियों ने यह कहा कि हमें पता नहीं लगा कि लाटरियां कैसे निकाली गयी हैं ? मैंने कहा कि आप लोग बलबीर पाल शाह से जाकर मिल लो क्योंकि इस काम के लिए उन्हीं की ड्यूटी लगायी गयी थी । अगर इसमें कोई गड़बड़ी की बात होगी तो हम इसको दोबारा से करेंगे । इन लोगों ने बाकायदा उनके साथ मीटिंग की । मीटिंग करने के बाद इन लोगों को भी तसल्ली हो गयी कि लाटरी ठीक निकाली गयी है । कुछ एक मन्त्रियों के विभाग में यह था कि सारे हरियाणा की लाटरी इकट्ठी ही निकाली गयी है है लेकिन ऐसा नहीं है । ये लाटरियां रूट वाईज निकाली गयी हैं । (विघ्न) लेकिन अगर एक रूट पर दस दरखवास्त हों तो रूट मिलना तो एक को ही था, सो एक को ही मिल गया ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा; इन्होंने एक टोहाना के केस का जिक्र कर दिया । इन्होंने कहा कि वहां डाक्टर का कत्ल हुआ । ठीक है कत्ल हुआ लेकिन सारे मुजरिम पकड़े गए । कत्ल तो किसी का भी हो सकता है। कत्ल कैनेडी का भी हुआ था लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी को रियायत दी हो । अगर किसी का कत्ल हो गया और सरकार ने किसी को बचाने की कोशिश की हो, तब तो कहा भी जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, बाकायदा जिनका भी कसूर था, उनको पकड़ा गया है ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, वहां पर टैरोरिस्ट ऐक्टीविटीज में एक डी0एस0पी0 और एक ए0एस0आई0 उग्रवादियों द्वारा मारे गए थे । इन दो उग्रवादियों में एक तो बूलर नाम का उग्रवादी वहीं पर मारा गया था और दूसरा निहाला नाम का उग्रवादी इंजर्ड होकर कैलो फार्म पर आया था, जिसका कि इसी डाक्टर द्वारा इलाज किया गया था । हमें यह शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस डाक्टर से डर था कि कहीं वह डाक्टर उस उग्रवादी से बड़े लोगों के संबंधों को उजागर न कर दे, इसलिए उस डाक्टर की हत्या करवा दी गई ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी इंक्वायरी करवा कर दोषियों को पकड़ा है । इसके अलावा, इन्होंने कहा कि थानों में लोग मारे जाते हैं । हो सकता है कि थाने में कोई मर गया हो । यह इंसान की जिन्दगी है, वहां पर किसी का हार्ट अटैक भी हो सकता है । आदमी चलते चलते भी मर सकता है । बस में या हवाई जहाज में भी आदमी मर जाता है, कुछ भी हो सकता है । कोई सिपाही भी वहां पर मर सकता है लेकिन देखना यह है कि वह पुलिस की गोली से न मरा हो । हमने वाकायदा ऐक्शन लिया है । कैथल की बात इन्होंने कह दी, कैथल में भी हमने कमीशन बिठाया है, उस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ही काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, जहां भी इस तरह के केस हुए हैं, बाकायदा सारे मुलजिमों को पकड़ा गया है । इसके अलावा, एक हिसार कांड की बात इन्होंने कही है, यह ठीक है कि वहां पर सुशीला कांड हुआ । मैं यह बात मानता हूं । लेकिन जो इन्होंने कहा कि इसकी सी0बी0आई से जांच कराओ तो मैंने सी0बी0आई0 को चिट्ठी लिखी । चीफ सैक्रेटरी ने होम सैक्रेटरी से और मैंने भी होम मिनिस्टर से बात की । 22 जुलाई 93 को मैंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है । केस लेने का काम उनका है, मेरा नहीं है वैसे होम सैक्रेटरी ने विश्वास दिलाया है कि हम कोशिश करेंगे । सी0बी0आई0 के पास और भी बहुत से केसिज होते हैं, इसलिए इस केस के बारे में वो कितना कर सकेंगे, यह मैं नहीं कह सकता, मगर मैंने अपनी ओर से लिख दिया है । (विघ्न)

प्रो0 छतर सिंह चौहान : मुख्यमन्त्री जी, आपने बहुत अच्छा किया कि मामला सी0बी0आई0 को भेज दिया । भूत मारने वाला भी सी0बी0आई0 को भेज दो । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी छतर सिंह चौहान ने कहा कि पंचकूला में एफ0आई0आर0 दर्ज की गई उसमें धांधली हुई, पुलिस की ज्यादती हुई । ऐसी कोई बात नहीं है । हरियाणा पुलिस पर तो हमें नाज होना चाहिए हमारे यहां की पुलिस ने सारे देश में नाम किया है । छतर सिंह जी ने एक बात और कह दी । (विघ्न)

प्रो0 छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमन्त्री जी को नाम दिया है कि वो रामचंदर नाम का आदमी आपकी कोठी पर रहता है और आपका लड़का उसे छुड़ाकर लाया है । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : जिसने चुनाव लड़ना है, वही उसको छुड़ाने के लिए जाएगा, आप क्यों जाएंगे ? गड़बड़ क्या है ? थाने में उसको बैठा लिया । मैं प्रदेश का मुख्यमन्त्री हूं, मैं कहता तो क्या उसको थाने में बैठाते ? हमने कहा कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए । आप लोगों को तकलीफ इसलिए

[चौधरी भजन लाल]

हो रही है कि उधर तो नरवाना में आप लोगों का बुरा हाल हो गया। चौधरी बंसी लाल जी और बी0जे0पी0 के राम बिलास जी की, सबकी मिलकर जमानत जब्त हो गई।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : जमानत सारे हरियाणा का प्रशासन..... (विघ्न) जो एफ0आई0आर0 दर्ज है वो कहीं गई नहीं .....(विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मुख्यमन्त्री महोदय गवर्नर के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं आपने भी सुना होगा कि जवाब देते-देते इन्होंने कई दफा 'झूठ' लफ्ज का इस्तेमाल किया, कई दफा 'शर्म' लफ्ज का इस्तेमाल किया। शायद इनकी आदत बन गई है जो गांव की गलियों में इस्तेमाल करते रहे। इन्हें सदन की गरिमा का ध्यान नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के लफ्ज कार्यवाही से निकाल दिए जाएं। मुख्यमन्त्री जी ने अपने जवाब में यह भी बताया कि 1700 नये उद्योग हरियाणा में लगे हैं, मुख्यमन्त्री जी ने एक परिवार एक रोजगार की बात भी विस्तार से की है। फोरलेन हमारी सरकार के वक्त में रोक दी गई थी, इंडायरैक्ट-ली में यह भी कहा कि वह सड़क इसलिए रोक दी गई थी कि ठेकेदार से पैसे मांगे गए थे। मैं इस सारे मामले के बारे में लीडर आफ दि हाउस और सरकार से कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र जारी करें ताकि पता लग जाए कि किसने लैन्ड ग्रेबिंग की है, कौन दोषी है ? पिछले शासन काल में कितने उद्योग इस प्रदेश से पलायन करके चले गए मुख्यमन्त्री को सोते हुए भी एक ही डर ओमप्रकाश चौटाला का खाए जा रहा है। मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन यह है कि मेरी सभाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमन्त्री जी कहते हैं कि कहीं ताज पहनाए जाते हैं, कहीं कुर्सियां दी जा रही हैं तो ये तो जनता के प्यार की वजह से ऐसा होता है। जहां तक सभाओं में हाजिरी का ताल्लुक है, कितनी भीड़ जुटती है। विपक्ष भीड़ जुटाया नहीं करता, अपने आप आया करती है। आप जगाधरी में गये थे और वहां पर सभा रखी हुई थी। शेर सिंह जी यहां पर बैठे हैं। इन्होंने मुख्यमन्त्री जी को शिकायत की कि ओमप्रकाश एम0एल0ए0 ने जगाधरी के स्कूल बन्द करा दिये और बच्चे सभा में ले आये। ऐसा करने से पार्टी की बदनामी होती है। मुख्यमन्त्री महोदय बड़े नाराज हुए। ओम प्रकाश एम0एल0ए0 को कहने लगे कि आपने ऐसा क्यों

कर दिया । जब यह सभा में गये तो वहां पर बच्चे स्टेज पर ही बिठा रखे थे । इन्होंने बड़े गुस्से में आकर डिप्टी कमिश्नर से यह कहा कि यह स्कूल बन्द करके बच्चे क्यों लाये हो ? (व्यवधान व शोर) मैं तो पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन पर बोल रहा हूं । फिर प्रैस के लोगों ने मुख्य मन्त्री से कहा कि अगर बच्चे स्कूलों में चले जायेंगे और सारे अधिकारी दफ्तरों में चले जायेंगे और प्रैस के लोग भी अन्दर चले जायेंगे तो फिर यहां पर रहेगा ही कौन ? मुख्य मन्त्री जी को पता है कि यहां पर तो समाजवादी जनता पार्टी की लोकप्रियता की वजह से भीड़ जमती है । इस वजह से इनको तकलीफ है ।

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, आप बैठिये । चीफ मिनिस्टर साहब, जवाब दे रहे हैं । उनको बोलने दें ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : क्या यह कोई पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन नहीं है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती से ये कुछ दिन राज्य सभा में भी रहे और बदकिस्मती से एक हफ्ता या तीन-तीन दिन तक यह चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं । हम यह समझते थे कि कुछ समझ गये होंगे लेकिन इस तरह से बीच में खड़े हो जायें, क्या यह कोई वाजिब बात है ? (व्यवधान व शोर)...अध्यक्ष महोदय, छतर सिंह चौहान जी ने एक बात पुलिस के बारे में कही । उन्होंने डी0आई0जी0 हिसार का नाम ले लिया । (व्यवधान व शोर) अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा कि वह एक कांस्टेबल को अपने यहां ले आये । एक जगह तो वह फेल हो गया लेकिन दूसरी जगह ले जाकर उसको पास करा दिया । मैंने इस बारे में पूरी बात का पता किया है । यह बात तो ठीक है कि सिपाही ट्रांसफर होकर वहां गया है लेकिन वह जब फेल हो गया तो वहां पर पास होने का कोई मतलब ही नहीं है । यह बिल्कुल बेस-लैस और बे-बुनियाद बात है ।

प्रो0 छतर सिंह चौहान : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही है, मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूं । उस आदमी का ट्रांसफर रात को हुआ । 11 बज कर 20 मिनट पर उसने ज्वायन किया । अगले दिन 29 को वह टैस्ट में पास हो गया । आप कृपया हाउस को गुमराह न करें । इस बात को वैरीफाई कर लें ।

चौधरी भजन लाल : मैं जब हाउस के अन्दर यह बात कह रहा हूं तो वरीफाई करके ही कह रहा हूं । जब वह आदमी एक जगह फेल हो गया तो दोबारा उसी आदमी का दूसरी जगह पर इम्तहान लेने का तो सवाल ही नहीं है । न ही उसको पास किया गया है और न ही उसने टैस्ट पास किया है । मैं आन रिकार्ड यह बात कह रहा हूं । आप मेरे को तो कहते हो लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने अखबार में जो बयान दिया है उसका जिक्र नहीं करते । चौटाला साहब क्या कहते हैं । चौटाला ने कहा है कि बंसी लाल का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है (हंसी) । यह अखबार में लिख रखा है । आप मेरी तरफ तो देखते रहते हो । इनको कुछ नहीं कहते । चौटाला साहब आप भी तो कुछ कहो । अगर आप कहें तो यह अखबार आपके पास भिजवा देता हूं, पढ़ लें ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : मैंने पढ़ लिया है ।

चौधरी भजन लाल : पढ़ लिया तो ठीक है । दूसरी बात नहरों की सफाई के बारे में कही । मैंने आज भी सदन को विश्वास दिलाया है कि हम सबसे ज्यादा पहल बिजली, पानी, नहरों की सफाई और टूटी हुई सड़कों को देंगे । इस ओर ज्यादा ध्यान देंगे कि जल्दी से जल्दी नहरों की सफाई कम्पलीट करके पानी किसानों की टेल तक पहुंचायें ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय पिछले साल भी मुख्य मन्त्री महोदय ने नहरों की सफाई के बारे में कहा था कि सफाई करा देंगे । सिंचाई मन्त्री ने कहा था कि बारिश खत्म होते ही सफाई करा देंगे । उसके बाद कितनी बार बारिश हो चुकी है । कुछ करोगे भी या सारा जेब में ही डालोगे ? (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लाल : चौधरी साहब आप तो बागड़ी के बागड़ी ही रहे । मैं समझा था कि आपने नहर का पानी तो देख लिया होगा । ...(व्यवधान व शोर)

चौधरी बंसी लाल : मेरे से ज्यादा बागड़ी तो आप हैं । मुझे तो बागड़ी कहलाने में कोई शर्म नहीं आती ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय मैं यह बता रहा था कि हरियाणा में पानी दो प्रकार का आता है । एक तो भाखड़ा का और दूसरे यमुना का । यमुना का जो पानी आता है वह बरसात का आता है । उसमें पानी के साथ में रेता, गर्दा और गाद आती है । दूसरा भाखड़ा का जो पानी आता है, उसके लिये बाकायदा कैचमैंट एरिया बना हुआ है और बांध बना हुआ है । पानी वहां से फिल्टर कर आता है । वह पानी पहाड़ों से बर्फ के पिघलने से आता है । उसमें रेत नहीं होती । भाखड़ा के पानी में तो बड़ी मुश्किल से एक या डेढ़ परसैंट सिल्ट होती है ।

चौधरी बंसी लाल : मैंने किसी दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने तो नहर शब्द का इस्तेमाल किया है। आपने कहा था कि नहरों की टेल तक बारिश खत्म होते ही सफाई करा देंगे और गाद निकाल देंगे लेकिन आज तक भी वह वहीं पर है। कोई सफाई नहीं हुई है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यमुना के पानी में सिल्ट इतनी होती है कि हम तो निकालते हैं लेकिन वह साल में दोबारा आ जाती है। क्या कभी सिल्ट भी एक बार निकालने से खत्म हुई है। जब पानी चलता है तो सिल्ट तो आयेगी। सिल्ट तो आती है और जम जाती है। (व्यवधान व शोर)...एक बात मनी राम केहरवाला जी ने बिजली, पानी और नहरों के पानी के बारे में कही है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप कितना टाईम और लेंगे ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : मैं 15-20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : चूंकि अभी एक आईटम एजेंडा पर और है इसलिये यदि हाउस की सहमति हो तो आधा घंटा के लिये हाउस का समय बढ़ा लिया जाये।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, पानी के मामले में भेदभाव करने की बात भी ओमप्रकाश जी ने कह दी। हमारा पानी के मामले में किसी से कोई भेद-भाव नहीं है, हमारे लिये सारे एक समान हैं। लेकिन पानी का सिस्टम अलग अलग है। भाखड़ा का सिस्टम अलग है, यमुना का सिस्टम अलग है। यमुना पर बांध नहीं है। बरसात के दिनों में पानी बहकर नीचे चला जाता है। भारत सरकार से इस बारे में हमने बातचीत की है। कसाउ डैम व रेणुका बांध बनाने के बारे में हमने बातचीत की है। बांध बनने के बाद तो पानी रुकेगा ही और हिसाब से चलेगा। भाखड़ा पर बांध है, उसमें पानी हिसाब से छूटता है। नहरों का भी सिस्टम अलग अलग है लेकिन फिर भी नरवाना ब्रांच में जितना पानी आ सकता था, उतना देने की हमने पूरी कोशिश की है ताकि उस इलाके के साथ कोई ज्यादती न

[चौधरी भजन लाल]

होने पाए । हमने किसी इलाके के साथ पानी के मामले में और दूसरे किसी भी मामले में कोई ज्यादती नहीं की और न ही होगी ।

इसके साथ साथ यहां पर इन की ओर से सिरसा के अन्दर एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का भी जिकर किया गया । अध्यक्ष महोदय, इस बारे में बाकायदा कोर्ट के अन्दर इस्तगासा दर्ज किया हुआ है मामला सब जुडिस है लेकिन फिर भी हम इस मामले की बाकायदा जांच कर रहे हैं और इसके लिये जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । ज्यूं ही हमें इस बारे में पता चला, जरा भी हमें इस बात का सन्देह हुआ तो हमने उनसे चेयरमैनी से इस्तीफा ले लिया ।

अध्यक्ष महोदय, धीरपाल जी ने महिलाओं के साथ बलात्कार का भी जिकर किया । इस संबंध में उन्होंने कलावड गांव का जिकर किया । कलावड़ में जो इस तरह का वाकया हुआ, उसका हमें बेहद दुःख है लेकिन सरकार जो कर सकती थी, इस केस में बाकायदा केस दर्ज किया और हमने कार्यवाही की है । इसकी जुडिशियल इंक्वायरी चालू है । केस सब जुडिस है, अगर आज इस बारे में, मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं है । इन्होंने साथ में बोलते हुए यह भी कह दिया कि एक एक आदमी की कीमत इन्होंने एक-एक लाख डाली है । मैं इनको बताना चाहता हूं कि यहां पर कीमत का सवाल नहीं है । सवाल होता है, मदद करने का, सहायता देने का । जिसके पीछे बूढ़े मां-बाप हों, बच्चे किसी के छोटे हों, ऐसी हालात में किसी की मदद करने का, सहायता करने का सवाल होता है, न कि कीमत डालने का... (शोर) ।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने उन्हें पिटवाया, मरवाया और साथ में उनको गुण्डा बदमाश कहा और फिर कंपैन्सेशन दिया । यह दोनों बातें विरोधाभास सी हैं । साथ में इनके पार्टी के जो मुखिया हैं, वे वहां पर गये और उन्होंने वहां पर इनाम भी बांटे, हमारे पास उस समय की फोटो हैं, यह रिकार्ड की बात है । उन्होंने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी है । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो कहते हैं, मैं उस बारे में बताता हूं । ये जरा शान्ति से सुनने की कृपा करें । एक तरफ तो ये कहते हैं कि उनकी मदद क्यों की ? दूसरी ओर कहते हो कि पुलिस ने उन्हें गुण्डा बदमाश बतलाया तो मदद करने की जरूरत नहीं थी । हम कहते हैं कि पुलिस ने बाकायदा उनका पीछा किया । जो उनका वर्शन है, वह मैं कहता हूं । आज उस वर्शन की तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केस में फर्क पड़ेगा लेकिन हमारा फर्ज उन लोगों की सहायता करने का था जो हम ने की है और हमने रिपोर्ट मांगी है, जिसका उसमें कसूर पाया जाएगा, उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाएगी ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो जुडिशियल इंक्वायरी का मुख्यमन्त्री ने बताया कि चालू है, उसको हम ऐप्रीशिऐट करते हैं लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी जो जज कर रहा है, उसको सरकार की तरफ से कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। साधन तो उस को मुहैया करवाने ही पड़ेंगे चाहे विहक्लज के हों, पैसे के हों, कागज पत्र के या फिर स्टाफ के साधन हों, साधन अवश्य मुहैया करवाये जाने चाहियें। हमारी सूचना के अनुसार अब तक कोई साधन उनको मुहैया नहीं करवाये गये हैं।

चौधरी भजन लाल : ऐसी बात नहीं है। हम सभी प्रकार के साधन, अगर अभी तक न दिये गये होंगे तो फौरन मुहैया करवाये जाएंगे। हर प्रकार की मदद उन्हें दी जाएगी। न देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें सब कुछ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ तीन चार बातों का और भी जिकर यहां पर किया गया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों को लोन का भी जिकर किया गया है।

चौधरी भजन लाल : हां जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं। इन्होंने साथ में लैण्ड मार्गेज बैंक के बारे में भी कह दिया कि 50 हजार तक लोन देते हैं, और उसमें गड़बड़ होती है। नहीं देना चाहिये था .....(शोर) इसका मतलब तो यह हुआ कि ये लोग गरीब भाईयों व हरिजन भाईयों व बैकवर्ड भाईयों को मदद देने के खिलाफ हैं। यह पैसा गरीब लोगों को मिलता है। (शोर) ऐसी बाकायदा स्कीम सरकार की है जिसके तहत गरीब लोगों, बैकवर्ड भाईयों को मदद दी जाती है। (शोर) अध्यक्ष महोदय, इतनी बातें करने का मतलब यह है कि ये लोग गरीबों के खिलाफ हैं। क्या इन की बैकवर्ड व गरीब लोगों के साथ कोई हमदर्दी है ? सरकार ने ऐसी पालिसी बनाई है ताकि हर गरीब आदमी भी एक दो किल्ले धरती ले ले। (शोर) भूमिहीन किसानों की बात भी है, इसमें सारे आ जाते हैं। इस में किसी जात पात वाली कोई बात नहीं है। उनमें सभी जाति के लोग हैं। दूसरे आपने सांपला के पास हुए कांड का जिक्र किया। उसमें सारे मुलजिम गिरफतार हो चुके हैं। रोहतक में झज्जर रोड पर रोबरी केस हुआ था, उसमें भी सारे मुलजिम गिरफतार हो चुके हैं और माल भी बरामद हो चुका है। एक आपने कहा कि राम चन्द बाल्मीकी, स्वीपर हरियाणा रोडवेज हिसार जेल में बन्द था। उसको हृदय की तकलीफ महसूस हुई जिसके कारण वह मर गया। उसकी मत्यु के बाद उसका बाकायदा पोस्ट मार्टम हुआ और रिपोर्ट आई कि वह हार्ट अटैक से मरा है। अगर हार्ट अटैक से मरा है तो फिर क्या कर सकते हैं। हार्ट अटैक तो किसी को किसी भी जगह हो सकता है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : उसके शरीर में तो खून का टीपा भी नहीं था।

चौधरी भजन लाल : हार्ट फेल होने वाले का खून नहीं बहा करता । (विघ्न) हार्ट अटैक से तो एक दम आदमी का सांस बन्द हो जाता है ।

श्री धीर पाल सिंह : फिर उसको मुआवजा किस चीज का दिया गया है, क्या पीटने के लिए दिया गया है ?

चौधरी भजन लाल : वह तो मदद के तौर पर दिया गया है क्योंकि वह गरीब आदमी था । आप गुमराह कर रहे हैं । आप ही कहते हैं कि उसका कोई खून नहीं बहा । तो वह मर कैसे गया ? आप तो एक ही बात में दो बातें कहते हैं । एक आपने कहा कि चरण सिंह, पुत्र मंशा राम, वासी लंगर पुर थाना सदर, बहादुर गढ़ जो दिल्ली में वाटर वर्कस में काम करता था । वह शराब पीने का आदी था । दिनांक 16-2-94 को उसकी लाश दिल्ली बहादुरगढ़ रोड पर खेतों में मिली । मुकदमा नं0 53 दिनांक 16-2-94 थाना सदर बहादुरगढ़ में धारा अधीन 302 दर्ज किया गया । पुलिस अधीक्षक रोहतक मौके पर गए थे । मृत्यु का कारण सिर में चोट तथा गला घोटना बताया गया है जिसकी तफतीश श्री रछपाल सिंह एस0 एच0 ओ0 बहादुरगढ़ कर रहे हैं । अपराधियों को पकड़ने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

श्री धीर पाल सिंह : उसको नंगा करके मारा गया । लोगों में बहुत नाराजगी बढ़ी हुई है । सारा इलाका एस0पी0 साहब को सहायता देना चाहता है । बदमाश और अपराधी किस्म के लोग अगर पकड़े नहीं गए तो वहां बुरी हालत हो जाएगी ।

चौधरी भजन लाल : आपको किसी अपराधी पर शक हो तो मुझे अकेले में उसका नाम बता देना, हम पूरी कार्यवाही करेंगे । पुलिस आज उसकी तफतीश कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अपराधियों का पता लग जाए ।

एक बात मैं गन्ने के भाव के बारे में कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, दो बातों की मैं सदन के अन्दर घोषणा करना चाहता हूं । एक तो हमने फैसला किया है कि चूंकि अब गन्ने की बीजाई शुरू होने जा रही है, आप जानते हैं मिलों के एरिया में गन्ना कुछ कम हो गया है । ये कहते हैं कि क्यों कम हो गया है । गन्ना कम होने के कारण हैं । क्योंकि गेहूं और जीरी का हमने बहुत अच्छा भाव दिया जिसके कारण लोगों ने जीरी और गेहूं की तरफ एरिया बदल दिया । इसलिए गन्ने का एरिया कम हो गया । मैं सदन के अन्दर घोषणा करता हूं कि हम अगले सीजन के लिए ताकि गन्ने की कुछ ज्यादा बीजाई हो जाए पांच रुपए क्विंटल का भाव अभी बढ़ाने का एलान करता हूं । (थम्पिंग) जब सीजन का टाइम आएगा, पीड़ाई का टाइम आएगा उस टाइम दोबारा रिव्यू करेंगे । हम कोशिश करेंगे कि किसान को और भी ज्यादा गन्ने का भाव दिया जाए ताकि गन्ने की बीजाई अच्छी हो जाए ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हम सब को एक समान समझते हैं, इस सदन में जो एम0 एल0 एज0 हैं चाहे वे अपोजीशन के हैं चाहे हमारी पार्टी के हैं, हर एम0एल0ए0 को हमने 20-20 लाख रुपया एक साल में उनके हल्कों में काम करने के लिए देने का फैसला किया है। हमारे दिल में कोई भेद भाव की बात नहीं है। (थम्पिंग) चाहे वह अपोजीशन का मैम्बर है और चाहे किसी भी पार्टी का है। सभी एम0एल0एज0 को उनके अपने इलाके में काम करने के लिए एक साल में बीस लाख रुपए देंगे, राम भजन जी ने कहा कि दादरी और लोहारु में पानी और सड़कों की दिक्कत है। मैंने उनकी सारी बातें नोट की हुई हैं....

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, इन्होंने 20-20 लाख रुपए की बात की है और उधर के भाई फबकियां ले रहे थे कि आप इसको तो मन्जूर करेंगे, आप इसमें तो हां भर लें। स्पीकर साहब, यही पालिसी गवर्नमैंट आफ इंडिया ने, प्रधान मन्त्री ने एम0पीज0 के लिए अनांउस की है और यही पालिसी आज चीफ मिनिस्टर साहब ने अनांउस की है। हम इसको अपोज करेंगे, यह बिल्कुल गलत बात है। यह पैसा एम0एल0ए0 को नहीं देना चाहिए, गवर्नमैंट के अपने मिनिस्टर हैं, विभाग हैं, डायरैक्टर हैं और कमिशनर्ज हैं। वे जहां वाजिब समझते हैं और जहां जरुरत है, वहां बिना भेद-भाव के खर्च करें। (शोर) स्पीकर साहब, यह क्रप्शन है। हम इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानते। इस तरह से एम0एल0एज0 को क्रप्ट करना है, उनको बाइब करना है। हम तो यह चाहेंगे कि सरकार बिना भेदभाव के सभी हल्कों में विकास के काम करे। यदि आप एम0एल0एज0 की डिस्पोजल पर पैसा देंगे तो एम0एल0एज0 की डिस्पोजल पर हम पैसा लेने के लिए कतई तैयार नहीं हैं।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, यह पैसा किसी एम0एल0ए0 को कैश नहीं मिलेगा। इस पैसे से हल्के के विकास के काम करवाए जाएंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी नीयत प्रदेश में विकास करने की नहीं है। इनकी नीयत प्रदेश के लोगों के भले के लिए नहीं है। इनकी तो वह काम करना है ताकि यह पैसा इनकी जेब में आ जाए। ये लोगों के कामों की तरफ नहीं देखते। यदि आप न चाहें तो यह पैसा मत लेना हम कब कहते हैं कि आप लो। आज की सरकार हर हल्के में 20 लाख रुपए विकास के कामों पर खर्च करेगी।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह जनतंत्र की परिभाषा नहीं है। सामन्तशाह युग में तो राजा नवाब खैरात बांटा करते थे। जनतान्त्रिक सिस्टम में किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह सरकारी कोष से अपने मंजूरे नजर लोगों को पैसा बांटने का काम करे। इस हाउस में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और यह सम्मानित हाउस एक अधिकार रखता है। स्टेट के विकास में पूरी तरह से स्टेट का

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

पैसा खर्च किया जाए। सरकार की विशेष रूप से जिम्मेदारी होती है कि विकास के काम में, योजनाओं में एम०एल०ए० से परामर्श करके उनसे पूछताछ करके उनके हल्कों के विकास के लिए इस प्रदेश के विकास के लिए पैसा खर्च करें। हमारी समाजवादी जनता पार्टी जो पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम किसी की खैरात लेना पसंद नहीं करेंगे। हम इसका डट कर विरोध करते हैं। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। यह जनतंत्र की परिभाषा नहीं है। हम इसको नहीं मानेंगे।

श्री मनी राम केहरवाला : अध्यक्ष महोदय, इस हरियाणा प्रदेश ने एक वक्त ऐसा भी देखा था। आज ये जिस बात को खैरात कहते हैं, किसी वक्त में * (शोर)

चौधरी भजन लाल : * * * (शोर)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि चौधरी देवी लाल जी इस सदन के मेम्बर नहीं हैं इसलिए उनका नाम नहीं आना चाहिए। माननीय सदस्य ने उनकी शान के खिलाफ जो शब्द कहे हैं वे हाउस की कार्यवाही से निकाले जाएं। माननीय सदस्य द्वारा इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना कि * * * यह बात कार्यवाही से निकाली जानी चाहिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : माननीय सदस्य ने कोई अपशब्द नहीं कहा। माननीय सदस्य ने तो यह कहा है कि * * * * इसमें गलत क्या है ? क्या आपको इस बारे में पता नहीं है ? (शोर)

चौधरी बंसी लाल : माननीय सदस्य ने उनके फादर का नाम लिया है। (शोर)

चौधरी भजन लाल : किसके फादर का नाम लिया है ? (शोर)

चौधरी बंसी लाल : माननीय सदस्य ने चौधरी देवी लाल का नाम लिया है और उनकी शान में जो शब्द कहे हैं, वे हाउस की कार्यवाही से निकाले जाने चाहिएं। (शोर)

चौधरी भजन लाल : हमें तो इस बात की खुशी है कि आपके मन में चौधरी देवी लाल के प्रति प्रेम जाग गया है। (शोर)

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री पीर चन्द : स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसे अपोजिशन के माननीय सदस्यों ने एतराज किया है कि वे अपने हल्कों के विकास के लिए 20 लाख रुपए नहीं लेंगे तो मैं यह चाहता हूं कि जो भी सदस्य 20 लाख रुपए अपने हल्के के विकास के लिए लेना चाहे, उससे एफेडेविट ले लें और जो सदस्य न लेना चाहे वह न ले, उसमें दिक्कत क्या है। जो सदस्य एफेडेविट देगा वह यह पैसा ले लेगा।

साथी लहरी सिंह : स्पीकर साहब, ऐसा है कि यह खैरात वाली बात बड़ी संदेहजनक है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने हमारी स्टेट से 200 बिजली के ट्रांसफारमर यू0 पी0 को भेज दिए थे। क्या वे ट्रांसफारमर खैरात मान कर दिए थे ? मैं इस बारे में मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा। (शोर)

चौधरी भजन लाल : चौधरी देवी लाल जो ट्रांसफार्मर यू0 पी0 को दे कर आये थे, वह पुरानी बात है। मैं रिकार्ड देख कर इस बारे में बाद में बता दूंगा। (शोर एवं विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने आज जो यह घोषणा की है कि हरेक एम0एल0ए0 को 20-20 लाख रुपये दिए जाएंगे, इसमें कोई गलत-फहमी न रहे, इसलिए मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये पैसे विधायक को कैश नहीं मिलेंगे। अब तक तो अधिकारी ही विकास की योजनाएं बनाते थे, जबकि एम0एल0ए0 जनता का नुमाइन्दा होता है और असल में विधायक को ही अधिक पता होता है कि उसके अपने हल्के में कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। उनको पता है कि फलां गांव में लोगों की क्या मांग है, इसलिए बाकायदा इस पैसे को खर्च करने के लिए किसी स्कीम के तहत ही पैसा मिलेगा। यह पैसा कैश किसी की जेब में नहीं जायेगा, इसलिए इसमें गबन होने की कोई बात नहीं है।

चौधरी भजन लाल : मोटी सी बात यह है कि जो विधायक विकास की स्कीम बनाएंगे उस पर यह पैसा खर्च किया जायेगा। एम0एल0ए0 को पता है कि माइनर की डी-सिल्टिंग कहां पर होनी है, एम0एल0ए0 जानता है कि फलां सड़क बनानी चाहिए, इसलिए ऐसे कामों पर ही यह पैसा खर्च होगा और इसीलिए यह 20 लाख रुपये हर हल्के के विकास के लिए दिए जा रहे हैं। (विघ्न) इनका रोला मचा कर चौटाला साहब नगद लेना चाहता है क्या ? यह नगद नहीं मिल सकता, यह तो इलाके के विकास के लिए मिलेगा। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक मैंने जो बात कही, उसकी पुष्टि अब स्वयं लीडर आफ दी

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

हाउस ने की है और मंगे राम जी ने भी यह कह दिया कि यह पैसा किसी को कैश नहीं दिया जा रहा । और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला नगद लेना चाहता है । क्या इसके अधिकार में है पैसा देना ? जरा इससे पूछिए । जरा इसको पूछिए कि क्या किसी को देने के लिए स्टेट का पैसा इसके अधिकार में आता है और ओम प्रकाश जैसे व्यक्ति को खरीदने की हिम्मत है क्या ? यहां इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए और इनको अशोभनीय बात नहीं कहनी चाहिए । अपनी औकात में और हैसियत के मुताबिक जरा बात करें । (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : औकात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं । (विघ्न) सब जानते हैं सब की औकात । (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको जरा हैसियत के मुताबिक ही यह बात यहां पर कहनी चाहिए, यही ज्यादा ठीक रहेगा । बोलते हुए कुछ लोगों को ज्ञान नहीं रहता । अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात कही और आपने उस बात का नोटिस नहीं लिया कि इस हाउस में जो व्यक्ति न हो या हाउस का मैम्बर न हो उसका जिक्र आया और चौधरी देवी लाल जी के बाप का नाम भी लिया गया है । स्पीकर साहब, मुझे हैरानी है और मुझे खेद है कि उस बात पर आपकी तरफ से कोई चर्चा ही नहीं हुई है । यहां तो कुछ लोग एक एक गज लम्बी जबान लिए हुए बैठे हैं, जो मुंह में आए सो कहते चले जायें । कुछ हाउस की गरिमा भी हुआ करती है, कुछ पद की गरिमा भी होती है । मैं सर्वप्रथम यह पूछना चाहता हूं कि * * * के नाम को इस हाउस में लिया जा सकता है ? जिन लोगों की कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनको समझ नहीं है, वे अपने पैमाने पर रहेंगे तो यह हाउस ठीक चलेगा । यह इनका कोई बोलने का तरीका है क्या ? (विघ्न) अरे भई आपने सुनी नहीं, आप तो खुशामद सुनने में यकीन रखते हो । जिस किसी आदमी को यह पता न हो कि क्या कहने जा रहा हूं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस हाउस की कार्यवाही देखी जाये कि इसने क्या कहा है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय हाउस की कार्यवाही देखें कि क्या लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगर कहीं पर चौधरी देवी लाल जी के बाप का नाम लिया है तो वह एक्सपंज कर दिया जाये । (शोर)

चौधरी भजन लाल : इन्होंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं । (शोर)

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने * * * * नाम को तो एक्सपंज कर दिया लेकिन मैं चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी के नाम को भी एक्सपंज किया जाये । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आप रिकार्ड तो देखिए ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मैं उस प्रोसिडिंग को देख लूंगा और अगर उसका नाम लिया गया है तो उसको एक्सपंज कर दिया जायेगा ।

खेल राज्य मंत्री (श्री राजेश कुमार शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी हाउस जब इस सदन में एड्रैस करते हैं तो वे आप करके करते हैं । सबको सम्मानित सदस्य कहते हैं और श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी इनके लिए जिस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आप बेशक रिकार्ड निकलवा कर देख लें इनको और उसको कह कर बात करते हैं । ये बहुत सम्मानित सदस्य हैं, उन्हें आप कहें कि और कम से कम अपनी लैंग्वेज तो सुधारें ।

चौधरी भजन लाल : कोई बात नहीं । जिसकी जैसी बुद्धि और अकल होगी, वह वैसी ही बात करेगा । अगर कोई कहे कि बटोड़े में से गुड़ की भेली आ जाए तो वहां से गुड़ की भेली तो आने से रही, वहां से तो सिर्फ गोस्से ही आने हैं । हमको इस बात की चिन्ता नहीं । जिसके पास जैसी बुद्धि होती है वह वैसी ही बात करता है । इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है ।

प्रो0 राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस की ग्रेस के लिए यह जरूरी है कि चौधरी मनी राम केहर वाला जी से बोलते हुए गुस्से में चौधरी देवी लाल जी के बारे में जो बात मुंह से निकल गई है, उसको हाउस की कार्यवाही से एक्सपंज करवा दिया जाए तो बात समाप्त हो जाएगी । (विघ्न एवं शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने इस बारे में पहले ही कह दिया था कि इसको एक्सपंज कर दिया जाए, इसलिए यह बात खत्म हो जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक बात कवेरी के बारे में कही गई कि मन्त्रियों को दे दी, कोई एम0एल0ए0 को दे दी । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में हाउस में बतलाना चाहूंगा कि 1990-91 में कवेरी से 9 करोड़ 25 लाख की इन्कम सरकार को होती थी लेकिन 1991-92 में यह इन्कम 9.25 करोड़ से बढ़ कर 15 करोड़ 28 लाख रुपये हुई और 1993-94 में यह बढ़ कर 16 करोड़ 50 लाख की इन्कम स्टेट की हुई है । अध्यक्ष महोदय, राम भजन जी ने, धीरपाल सिंह जी ने और दूसरे

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[चौधरी भजन लाल]

माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं और जो बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, जैसे सड़कों की बात है, पीने के पानी की बात है, सड़कों की रिपेयर की बात है, सीवरेज से गन्दा पानी पीने के पानी में मिलने की बात है, पीलिया की बात है, उसको यह सरकार देखेगी और हर समस्या का समाधान करने का हर सम्भव प्रयास करेगी। इन शब्दों के साथ ही मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसको सर्वसम्मति से पास किया जाए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I put the amendments to the vote of the House. The amendments are from Sarvshri Bansi Lal, Om Parkash Jindal, Chattar Singh Chauhan, Attar Singh, Ram Bhajan Aggarwal, Smt. Janki Devi Mann Sh. Karan Singh Dalal.

Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely:—

"but regret that no mention has been made of—

1. Concrete steps which the Government proposes to take to arrest price-rise and bring back the price-line to January 1993-level.
2. Concrete steps proposed to be taken by the Government to streamline the deteriorating Public Distribution System.
3. To facilitate the formation of Co-operative Societies of the unemployed educated youth in the State which would be preferred for the allotment of Bus-route permit, Agencies like Gas, Petrol Pumps, Tractors, Four Wheelers Motor cycles, Scooters, Cars, Trucks Cement, Kerosene oil etc. and contracts for developmental works like digging/disilting canals, construction work of Govt. and all the corporations and autonomous bodies only be allotted to the Co-operative Societies of the educated youth of the State.
4. Declaration of Government intention to nationalise all the mines in the State to prevent looting of precious resources of the State by the vested interests.
5. Intention of the Government to allow police personnel to form Association.
6. Declaration of the intention of the Government to ban colonization by private parties and to have it done only through HUDA Cooperative Societies of unemployed educated youth Housing Board to put a step to exploitation of the public by the private colonisers.
7. Scheme for giving employment to the members of each family in the States even though he or she may be unfortunate to have remained uneducated by a definite date.
8. Concrete steps which the Government proposes to take to complete SYL canal to facilitate the farmers to irrigate their fields in the State.
9. Eradication of un-cleanliness in villages by a definite date.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

"That an Address be presented to the Governor in the following terms:—

'That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 28th February 1994,".

The motion was carried

वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान

1. Discussion on the Estimates of expenditure on the revenue of the State.

2. Discussion and voting on the Demands for Supplementary Grants.

Mr. Speaker : Now the discussion and voting on the Supplementary Estimates will take place.

According to the previous practice and in order to save the time of the House all the demands appearing on the order paper (No. 1 to 10, 14, 15, 17, 21, 23 & 25) will be deemed to have been read and moved togehter. The members are requested to indicate the demand No. in which they wish to raise the discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 46,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,45,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 19,30,80,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 50,85,56,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,64,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs 19,32,99,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 6—Finance.

[Mr. Speaker]

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,48,43,05,600 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,87,51,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 8—Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4.40,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,32,98,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 10—Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,19,59,000 for revenue expenditure and Rs. 1,74,59,39,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 14—Food & Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,36,80,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 15—Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,10,34,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,58,45,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 21—Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,58,67,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 23—Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20.06,23,000 for loan & Advances be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट हैं, यह हकीकत में एडीशनल बजट है। इन्होंने बिना किसी चीज को एक्सप्लेन किए एक हजार सात करोड़ रुपए के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट पास करवा रहे हैं। यह बहुत ही ज्यादती की बात होगी। मेरे विचार में इस पर डिस्कशन के लिए पूरा एक दिन होना चाहिए। इन्होंने जनरल डिमान्ड पर दो करोड़ पैंतालीस लाख तेरानवेहजार रुपए, होम डिपार्टमैंट के लिए 19 करोड़ तीस लाख रुपए, रेवेन्यू के लिए पचास करोड़ पचासी लाख रुपए, एक्साईज एंड टैक्सेशन के लिए एक करोड़ चौंसठ लाख रुपए फाईनान्स के लिए उन्नीस करोड़ बत्तीस लाख रुपए। इसके साथ ही बड़े ही ताज्जुब बात की

है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसीज के लिए छः अरब 48 करोड़ रुपए, एजुकेशन के लिए चार करोड़ चालीस लाख रुपए, मैडीकल एण्ड पब्लिक हैल्थ के लिए दस करोड़ 32 लाख रुपए, फूड एण्ड सप्लाई के लिए एक सौ चौहत्तर करोड़ रुपए, इरिगेशन के लिए दो करोड़ छत्तीस लाख रुपए, कम्युनिटी डवैल्पमैंट के लिए तेरह करोड़ अठावन लाख रुपए और ट्रांसपोर्ट के लिए ग्यारह करोड़ अठावन लाख रुपए रखे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमैंटरी एस्टीमेट है या बजट है ? क्या इस बारे में पिछला बजट बनाते वक्त ध्यान नहीं रखा गया था ? अभी तो साल निकला भी नहीं और साल निकलने से ही पहले इतनी सारी सप्लीमैंटरी डिमान्डज आ गई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो पूरा का पूरा बजट ही आ गया है।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जवाब दे देता हूं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे पहले बात पूरी कर लेने दें, तब ये जवाब दे दें। होम के उन्तीस करोड़ तीस लाख रुपए की कोई डिटेल नहीं है। होम का 50 करोड़ रुपए है, इसके साथ रेवेन्यू और फाईनेन्स का भी आ गया है। अदर्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसीज में छः सौ अड़तालीस करोड़ तैतालीस लाख रुपए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें लाटरीज का भी जिक्र आया है। लाटरीज के बारे में स्टेट के लोग क्या कहते हैं, वह मैं आपको बताता हूं। वे कहते हैं कि जो डेली लाटरी चलाई गई है, इससे गरीब लोग तबाह हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अकेले शाहबाद कस्बे में तीन लाख की डेली लाटरी बिकती है। कुरुक्षेत्र में 15 लाख की बिकती है। यह कौन खरीदता है, यह गरीब आदमी ही खरीदता है। अध्यक्ष महोदय, वह इसमें मरा जा रहा है। वे बेचारे लोग सोचते हैं कि कभी तो किस्मत खुलेगी। लेकिन वह इसमें मरा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैडीकल एण्ड पब्लिक हैल्थ में दस करोड़ बत्तीस लाख का अन्दाजा है। फूड एण्ड सप्लाई में 174 करोड़ मांगा है और एग्रीकल्चर में चौदह करोड़ दस लाख मांगा है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अमाउन्ट कैसे खर्च हो गया ? इसमें एक होम डिपार्टमैंट का भी अमाउन्ट है। अभी छत्तर सिंह जी ने जिक्र किया था कि भूत माजरा में एक ब्राह्मण की दो लड़कियों को उठा लिया गया था। उनमें से एक तो मिल गई थी परन्तु दूसरी का अभी तक कुछ पता नहीं है। पुलिस की जो कार्यवाही है, उससे लड़कियों के घर वालों को तसल्ली नहीं है। इसलिए अगर हो सके तो यह केस भी सी0 बी0 आई0 को भेज दें। अगर यह केस सी0 बी0 आई0 को भेज देंगे तो उसके घर वालों को भी तसल्ली हो जाएगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाऊस की सहमति हो तो हाऊस का समय 15 मिनट के
14.00 बजे | लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाज : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाऊस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर ये ईरीगेशन के लिए ज्यादा पैसा लें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर काम तो होना चाहिए। आज नहरों की डीसिल्टिंग नहीं हो रही है । मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि भाखड़ा कैनाल की भी डीसिल्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि भाखड़ा कैनाल में भी 18-18 फुट बीड पैदा हो जाती है जो कि मशीनरी से साफ करवानी पड़ती है । हमने भी 1986-87 में दो करोड़ रुपये खर्च करके इसकी सफाई करवायी थी । हरियाणा की सभी नहरों में डीसिल्टिंग की प्राब्लम है और यही प्राब्लम वैस्टर्न जमुना कैनाल की है । अगर इस कैनाल में हर साल सिल्ट आती है तो हर साल ही इसकी सफाई के लिए प्रोविजन रखा होता है । इसके अलावा, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों को पानी देने की जब भी बारी आती है तो नहर में पानी नहीं आता है । अगर एक किसान को टाईम पर एक बार पानी न मिले तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उससे आबियाना चार्ज नहीं करना चाहिए । किसान से आबियाना तब चार्ज करना चाहिए जब उसकी बारी आने पर उसको पानी मिल जाये । ऐसे ही आबियाना नहीं चार्ज करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से जोर देकर कहूंगा कि डेली लाटरीज बंद कर दी जानी चाहिए । अगर डेली लाटरीज बंद न की गयी तो गरीब लोग लुट जाएंगे और यह इस प्रदेश के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादती होगी । सरकार शायद यह सोचती है कि इससे 20 या तीस करोड़ रुपये की कमाई उसको हो जाएगी । मगर इससे नुक्सान कितना होगा यह भी सरकार को सोचना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो 600 करोड़ रुपये की सरकार सप्लीमैंटरी डिमांड्स लेकर आयी है, वह आगे से इतना लम्बा चौड़ा बजट सप्लीमैंटरी डिमांड्स के नाम से न लाया करें । सप्लीमैंटरी डिमांड्स तो तब लायी जाती हैं जब फाईनैंशियल ईयर खत्म हो जाता है, अभी तो फाईनैंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है । इसलिए मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये इस तरह से बैक डोर से बजट पास करवाने की कोशिश न किया करें ।

श्री बलवन्त सिंह मायना (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । अध्यक्ष महोदय, हाऊस के अन्दर सदन के नेता और मुख्यमंत्री जी एक दावा करते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इंसान की जिंदगी में सबसे पहले उसकी सुरक्षा का होना ही जरूरी है। आज इस हरियाणा प्रदेश के अन्दर कोई लॉ एंड आर्डर वाली बात नहीं है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रांट नं0 3 पर जो गृह से सम्बन्धित है, पर बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, चाहे वह पुलिस द्वारा मारा जाना हो, चाहे टोहाना और कलावड़ गांव की बात हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत का सवाल हो, चाहे पृथला कांड की बात हो, जहां पर लोग गोलियों से मारे गए थे या निर्सिंग के अन्दर किसानों को गोलियों से मारने वाली बात हो या चाहे हमारे रोहतक के अन्दर झज्जर रोड पर हुई डकैती की बात हो या जैसे कल ही कृष्ण मूर्ती मंत्री जी के बेटे द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के साथ हुए व्यवहार की बात हो तो यह सब एक ही किस्म की बातें हैं । अध्यक्ष महोदय, जो ड्यूटी पर हैं, जो सुरक्षा करते हैं, आज उन के साथ हरियाणा में क्या हो रहा है, यह आप जानते हैं । इसी प्रकार से हिसार के अन्दर सुशीला नाम की जे0 बी0 टी0 टीचर थी, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा (विघ्न) आज ये डिमांड लेकर इस प्रकार से आ जाते हैं। इसके साथ-साथ डिमांड नं0 8 पर रोड्ज की बात आई है । पी0 डब्ल्यू0 डी0 मिनिस्टर श्री आनंद सिंह डांगी जी का भाई रोड्ज का ठेका लेता है, यह रिकार्ड की बात है । चाहिए तो यह था कि इसके लिए ओपन टेन्डर इन्वाइट करते लेकिन इनका भाई वह ठेका किसी दूसरे को नहीं लेने देता, इसी वजह से आज इस पैसे की जरूरत पड़ रही है । मैं समझता हूं कि यह ठेका कम से कम मंत्री जी के भाई को तो नहीं मिलना चाहिए। रोड्ज की हालत यह है कि चाहे झज्जर-रोहतक रोड हो, बालंद सिमली से भम्भेवा रोड हो, सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं । (शोर एवं व्यवधान) इसी प्रकार से आज लगभग 300 आदमी डेली वेजिज पर लगे हुए हैं आप मौके पर जाकर देख लें कि कितने आदमी वहां काम करते हैं । वास्तव में वे पी0 डब्ल्यू0 डी0 मंत्री के खेत में काम करते हैं । डेली वेजिज पर आदमी लगाए कहीं और जाते हैं और काम कहीं और करते हैं । आप बेशक इंक्वायरी करा लें ।

डिमांड नं0 9 शिक्षा के बारे में है । शिक्षा का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। स्कूलों में मास्टर नहीं हैं । बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी और लिखने के लिये चॉकबस्ती नहीं मिलती है । दीवारों पर विज्ञापन लिखने में पैसा खर्च किया जाता है। मेरे हल्के में सांपला के अंदर चौधरी देवी लाल जी ने लड़कियों के लिए एक स्कूल मंजूर किया था जो इस सरकार ने आकर कैंसिल कर दिया । इसी तरह से इस्माइला और पुलियाना गांव में लड़कियों के लिए 10 जमा 2 स्कूल मंजूर किए गए थे, वे भी कैंसिल कर दिए गए हैं । आज पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य उप केन्द्र खुले हुए हैं उदाहरण के तौर पर जसैया गांव के अंदर जो स्वास्थ्य-उप-केन्द्र है

[श्री बलवन्त सिंह मायना]

वहां पुलिस ने कब्जा किया हुआ है । बलियाना गांव में भी जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र खुला हुआ है, उसमें गधे बैठते हैं । आज पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री जी जांच करवाएं कि प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में कितने-कितने कर्मचारी हैं और किस किस जगह पर बैठे हैं ।

इसी प्रकार से डिमांड नं0 17 में भी सिंचाई की बात आयी है । झज्जर सब-ब्रांच की बहुत बात आयी थी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसकी सफाई कब तक कर दी जायेगी, इस बारे में इसमें कोई टाईम नहीं दिया गया है । इसी प्रकार से झज्जर सब-ब्रांच, जे0 एल0 एन0 और जे0 एस0 बी0 के साथ-साथ चलती हैं । वहां पर हालत यह है कि पूरी नहर के साथ-साथ लगभग 5 एकड़ भूमि किसान की, नहर की सीपेज के पानी की वजह से बरबाद हो रही है । सीपेज की वजह से किसानों की जमीन खराब हो रही है लेकिन आज तक उन किसानों को मुआवजा देने के लिये कोई कानून नहीं बनाया गया । सरकार को उन्हें मुआवजा देना चाहिए था । इस किताब में उनको मुआवजा देने का कोई जिक्र ही नहीं है । जो पानी किसानों को सिंचाई के लिये दिया जाना चाहिये, वह उसके खेत को बरबाद कर रहा है । इससे उनको बचाया जाये । आज इस प्रकार से प्रदेश के लोगों पर बोझ तो डाला जा रहा है लेकिन उन किसानों के हितों के लिये जो ख्याल रखना चाहिये, उसका इस डिमान्ड में कोई प्रोवीजन नहीं रखा है । यह सरकार उन किसानों की जमीन को बरबाद होने से नहीं बचा सकती है, उनके हितों की सुरक्षा से यह सरकार भाग रही है । फिर यह कैसे कहते हैं कि यह सरकार किसानों की हितैषी है ? इसी प्रकार सदन में रजवाहों के अन्दर पानी की बात भी आयी है । मेरे हल्के के अन्दर एक सिंचाई माईनर है । मेरे हल्के के अन्दर हसनगढ़ एक ऐसा गांव है जहां आज तक कभी भी जोहड़ में पानी नहीं भरा है और रिपोर्ट यह आती है कि टेल तक पानी जा रहा है । एक मेरे यहां कसरेहटी गांव है । यह सरकार पानी देने का दावा तो बहुत करती है लेकिन खेतों की बात तो दूर रही, किसरेहटी गांव में पीने का पानी भी नहीं मिलता । यहां पर ये गलत तो बोल लेते हैं लेकिन इनको सच भी सुनना चाहिये ।

इसी प्रकार से डिमांड नं0 23 की बात है । आज हरियाणा प्रदेश में बसों की क्या हालत है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । इन्होंने कुछ बसें खरीदी हैं । जो आर्डीनरी बसिज हैं, वह तो इतनी टूटी-फूटी हैं कि आम आदमी उनमें बैठ नहीं सकता । जो एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं, वह सरकार के ऊपर बोझ बनी हुई हैं । उन गाड़ियों के अन्दर सवारी इसलिये नहीं बैठती क्योंकि आपने एक रुपये के बजाये उसका किराया सवा रुपया कर दिया है । यह सरकार दावा तो करती है कि हमने इस प्रदेश की जनता की सुविधा के लिये यह सुविधा प्रदान की है लेकिन इससे आम

जनता को कोई सुविधा प्रदान नहीं कर पाये हैं। आज प्रदेश में बसों की बुरी हालत है जो इसी वजह से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश में हरेक आदमी सुखी है, मुझे तो कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया। आप किसानों की बात करते हैं। किसानों के लिये खाद की बात जब कहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल के समय में डी० ए० पी० का एक कट्टा 180 रुपये में मिलता था लेकिन आज वही कट्टा 350 रुपये में मिलता है। वह भी नकली खाद मिलती है। आप बेशक इस बात की इंक्वायरी करवा लें क्योंकि यह खाद आज किसान के खेतों में काम नहीं कर पा रही है।

इसी तरह से कीड़े मार दवाईयों की बात है। वह अब्बल में तो किसान को मुहैया ही नहीं हो पा रही है, अगर कहीं पर मिलती भी है तो वह नकली है, काम नहीं कर रही है। मैंने खुद अपने खेत में स्प्रे करके देखा है। वह दवाईयां काम नहीं कर रही हैं। स्पीकर साहब, आज प्रदेश के अन्दर मुख्यमन्त्री महोदय दावा तो करते हैं लेकिन वह किसानों को किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं दे पाये हैं (घंटी) स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा सा तो और बोलने दें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब आप बैठिये। हाउस का समय समाप्त हो रहा है। यदि हाउस की सहमति हो तो 5 मिनट के लिये हाउस का टाईम एक्सटैंड कर दिया जाय।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 5 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमिशन है कि यहां पर एक हजार सात करोड़ की सप्लीमैंट्री डिमांड की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव इस सदन में आया है। यह बड़ा भारी अमाऊंट है जिसे सरकार जल्दी जल्दी में पास करवाना चाहती है। सर, इसके ऊपर बहुत से मैम्बर साहिबान बोलना चाह रहे हैं, इसलिये आप बोलने वाले मैम्बरों, जो रह गये हैं, पांच-पांच मिनट का समय अवश्य दें। (शोर) सर, आपकी परमिशन के बगैर हम नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं। आप बैठिये।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण –

लोक निर्माण मन्त्री द्वारा

लोक निर्माण मन्त्री (श्री आनन्द सिंह डांगी) : स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। अभी मेरे साथी ने पब्लिक वर्कस डिपार्टमैंट से सम्बन्धित डिमांडज पर बोलते हुए कहा। मेरे भाई के बारे में ठेकेदारी का जिकर किया कि उसको ठेका दिया गया। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि जो टैण्डर हुये थे, वे लगभग पांच कंपनियों के थे, जिसमें मेरा भाई भी कंपीटीशन में था, उसमें पार्टनर था। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि लोग डेली वेजिज पर लगा कर मेरे खेतों में काम कर रहे हैं। स्पीकर साहब, अगर एक भी आदमी सरकार के खर्चे से मेरे खेतों में काम कर रहा होगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। डांगी आज से खेत का काम नहीं करता, हमेशा से ही, सालों से पांच सात आदमी मेरे खेतों में काम करते आ रहे हैं। डांगी अपने हिसाब से ही काम करता है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, नैतिकता के आधार पर किसी सम्बन्धित मन्त्री के भाई को तो कम से कम इस विभाग का ठेकेदार नहीं होना चाहिये था। हमारा तो केवल इतना ही कहना है। (शोर)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, काम करना कोई गल्त बात नहीं है। भीख तो कोई नहीं मांगता। (शोर) आप रेट्स वगैरह कम्पेयर करवा लें। पहले जो नेशनल हाई-वे पर काम हुआ है, उस रेट से अगर कम रेट पर ठेका दिया गया हो तो आप कहें। (शोर)

वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेंटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी व प्रो० राम विलास शर्मा जी ने सप्लीमैंट्री डिमांडज पर बोलते हुए कुछ संशय जाहिर किया है कि यह 1 हजार 7 करोड़ रुपये की जो सप्लीमैंट्री इस हाउस में रखी गई है। यह वाजिब नहीं उन्होंने कहा कि इतना अमाउंट नहीं होना चाहिये। मैं क्लीयर कर देता हूं कि तीन डिमांडज जिसमें डिमांड नम्बर 7, 14 व 4 शामिल हैं, इनमें मेन डिमांड नम्बर

7 है, पर 648 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है, जो लाटरी से सम्बन्धित है। 176.89 करोड़ रुपया फूड एण्ड सप्लाईज पर और डिमांड नं0 4 में रेवन्यु एक्सपैन्डीचर का 50.50 करोड़ है। लगभग 900, 925 करोड़ रुपया इन डिमांडज पर खर्चा हुआ है। कुछ सिस्टम ही ऐसा है जिस के तहत अगर सरकार का एक रुपया कम खर्च होता है या एक रुपये की आमदनी होती है तो इस हाउस के द्वारा इनको पास करवाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि आप द्वारा इस हाउस के माननीय सदस्यों को एक ऐस्टीमेट्स कमेटी का भी गठन किया हुआ है जो इस ऐडीशनल ऐक्सपैन्डीचर को पहले ही पास करती है, उस के बाद अन्तिम स्वीकृति के लिये इस हाउस के सामने डिमांड आती हैं। सो उस कमेटी के सम्माननीय सदस्यों ने इन डिमांडज को पास किया हुआ है और चेयरमैन महोदय ने अपनी रिपोर्ट भी इस सदन में पेश कर दी है और उन्होंने यह वाजिब माना है। अगर हमें किसी पर नैट प्रोफिट भी हुआ हो तो जब तक उस डिमांडज को इस विधानसभा में पास न करवा लिया जाए तब तक सरकार उसको बजट में शामिल नहीं कर सकती। डिमांड नम्बर 7 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज से सम्बन्धित है, उसमें लाटरी विभाग भी आ जाता है उसमें 648 करोड़ रुपये का ऐक्सपैन्डीचर हुआ है। जब बजट को बनाते हैं तो पिछले साल हुए ऐक्सपन्डीचर को भी ध्यान में रखा जाता है और उससे हम 10, 15 परसैन्ट ज्यादा का प्रौवीजन करते हैं। पिछले साल लाटरीज घाटे में थी और इस साल हमें लगभग 25 करोड़ रुपये का नैट प्रोफिट हुआ है। इसमें सरकार की कोई इनवैस्टमैंट नहीं होती। चौधरी सम्पत सिंह को याद होगा कि हमने हरियाणा गवर्नमैंट की ईमेज को कायम किया है। पहले हमारी लाटरी का ईनाम लोगों को नहीं मिलता था लेकिन हमने पिछला 140 करोड़ दिया ताकि किसी किस्म की संशाएं न हों। पहले हरियाणा की लाटरी किसी और के हाथ में थी जिसका पैसा हमने दिया।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, खास तौर पर जो डेली लाटरी निकलती है यह एक तरह से लोगों का डैथ वारन्ट है। रोज हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है और जिन लोगों का पैसा इसमें बर्बाद हो जाता है वह बाद में सुसाइड कर लेते हैं। यह बिल्कुल बन्द होनी चाहिए।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, यह हिन्दुस्तान की हर स्टेट में चल रही है। अगर हम बन्द भी कर देंगे तो दूसरी स्टेट की बिकेंगी। जब सारी लाटरीज बन्द हो जाएंगी तो हम भी बन्द कर देंगे। इसको बन्द करने की पावर पार्लियामैंट के पास है। तो मैं कह रहा था कि इसमें कोई एडीशनल खर्चा नहीं है सिर्फ फिगर्ज की बात है। पिछले 26 साल में हरियाणा सरकार ने जो लाटरी से मुनाफा कमाया था वह एवरेज दो करोड़ रुपए साल का था लेकिन अब हमें 25 करोड़ रुपये साल का मुनाफा है। क्या आपने अपने जमाने में इसको बन्द किया था या चौधरी बंसी लाल जी ने बन्द किया था। (विघ्न) दूसरी जो 176 करोड़ रुपए की डिमांड नं0 7 फूड

[श्री मांगे राम गुप्ता]

एंड सप्लाई की है। इसके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने भी बताया था कि हरियाणा में गेहूं की रिकार्ड पैदावार हुई। हमारा जितना गेहूं खरीदने का टारगेट था उससे कहीं ज्यादा गेहूं आई। सरकार ने किसानों को अच्छे भाव देने के लिए ज्यादा गेहूं खरीद लिया। यह कोई खर्ची नहीं है बल्कि इससे कैपिटल अमाउंट बढ़ेगा। इसी तरह से 50 करोड़ रुपए नैचुरल क्लैमिटीज के हैं, जो भारत सरकार से मिलने हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय पांच मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय पांच मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1993-94 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

वित्तमंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): तो स्पीकर साहब, ये फिगर्ज को देख कर शक न करें। ये जो सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स हैं इनसे कोई ज्यादा बर्डन नहीं पड़ा है। जब आप रसीट साइड देखेंगे तो उसमें इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इन डिमांडज को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Now I put the various demands to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 46,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,45,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 19,30,80,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 3- Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 50,85,56,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,64,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 19,32,99,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,48,43,05,600 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,87,51,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of paym ent for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 8—Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,40,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,32,98,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 10- Medical and Public Health

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,19,59,000 for revenue expenditure and Rs. 1,74,59,39,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 14—Food & Supplies

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,36,80,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 15- Irrigation.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is —

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,10,34,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of paym ent for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,58,45,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 21– Community Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,58,67,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1994 in respect of Demand No. 23—Transport.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,06,23,000 for loan & advances be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1994 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 2-00 p. m. on Monday, the 7th March, 1994.

*14.25 hrs] (The Sabha then *adjourned till 2.00 p. m. on Monday, the 7th March, 1994.)

25696-H.V.S.—H.G.P., Chd.